राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 65

मूल्य ₹8 .00, नई दिल्ली, शनिवार, 14 अगस्त, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

राजनाथ बोले, अगले 25 वर्षों में हमें बनाना है एक भारत श्रेष्ठ भारत >>3

हिंसा से काबुल पर किया कब्जा तो नहीं मिलेगी मान्यता

अफगान संकट ▸ दोहा में आयोजित बैठक में शामिल दर्जनभर देशों ने तालिबान को किया आगाह

इनमें अमेरिका, रूस व भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात के बीच वहां शांति स्थापित करने के उद्देश्य से कतर की राजधानी दोहा में बुलाई गई बैठक में शामिल दर्जनभर देशों ने तालिबान को चेतावनी दी है कि अगर उसने काबुल पर हिंसा के जरिये कब्जा किया तो उसे कोई भी मान्यता नहीं देगा। तीन दिनों की बैठक के बाद गुरुवार आधी रात को एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें उक्त बात है, लेकिन शुक्रवार को तालिबान ने जिस तरह से काबुल को घेरकर आस-पास के शहरों में पुलिस थानों, विश्वविद्यालयों, रेडियो स्टेशन, बैंकों और सैन्य अड्डों पर आसानी से कब्जा कर लिया उससे साफ है कि शांति वार्ता में शामिल देशों के संयुक्त बयान का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। एक दिन पहले तक अनुमान था कि तालिबान एक महीने में काबुल पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि ऐसा कुछ ही दिनों में हो जाएगा।

भारत के कूटनीतिक सूत्रों ने 'दैनिक जागरण' को बताया कि ज्यादातर देश अब काबुल में अशरफ गनी सरकार के पतन का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही वे अपने अपने दूतावासों को सुरक्षित करने में भी जुटे हुए हैं। गुरुवार को दोहा में हुई बैठक में अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, नार्वे, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान के अलावा भारत का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। संयुक्त बयान में नौ बिंदु हैं और उनका निचोड़ यही है कि तालिबान को आक्रमण व हिंसा की राह छोड़कर शांति की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें तालिबान से अफगानिस्तान के सभी प्रांतों और उनकी राजधानियों पर हमले रोकने की अपील की गई है। तालिबान और अशरफ गनी सरकार से कहा गया है वे हिंसा की राह छोड़कर अफगानिस्तान की समस्या का राजनीतिक हल निकालने के लिए आगे बढ़ें।

चेतावनी को दरकिनार कर तालिबान ने काबुल को घेरा

कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के हालात पर बुलाई गई बैठक के दौरान बातचीत करते अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद (दाएं) व अन्य देशों के प्रतिनिधि। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल भी इस मौके पर मौजूद रहे। एएफपी

राजनीतिक हल का रोडमैप भी दिया

राजनीतिक हल का एक रोडमैप भी संयुक्त बयान में शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि मानवाधिकार का पालन किया जाएगा, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे देशों की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा और सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकार कानूनों का पालन किया जाएगा।

वार्ता से हुआ हल तो पुनर्निर्माण में करेंगे मदद

संयुक्त बयान में अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा, नागरिकों की हत्या, ढांचागत सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों की निंदा करते हुए इन पर तत्काल रोक लगाने की अपील की गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर काबुल पर सैन्य ताकत से कब्जा किया गया तो उसे कोई भी देश मान्यता नहीं देगा, लेकिन अगर अफगानिस्तान में दोनों पक्षों के बीच विमर्श से एक उचित राजनीतिक समाधान को लेकर सहमति बनती है तो सारे देश अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे।

कंधार और लश्करगाह पर तालिबान का कब्जा

काबुल : अफगानिस्तान में तालिबान के आगे बढ़ने की तेज गति बरकरार है। शुक्रवार को कट्टरपंथी लड़ाकों ने देश के दूसरे बड़े शहर कंधार और एक अन्य बड़े शहर लश्करगाह पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि कंधार हवाई अड्डे पर सरकारी बलों का कब्जा बना हुआ है। कंधार शहर कंधार प्रांत की राजधानी है जबकि ऐतिहासिक शहर लश्करगाह हेल्मंद प्रांत की राजधानी है। तालिबान का दावा है कि उसने देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 14 पर कब्जा कर लिया है। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों पर उसका कब्जा पहले से ही है। अफगानिस्तान में कंधार का खास महत्व है। माना जाता है कि कंधार जिसके पास होता है वह ही अफगानिस्तान पर शासन करता है, क्योंकि यह देश का मुख्य व्यापारिक शहर है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसकी प्रांतीय सीमाएं पाकिस्तान व ईरान से लगती हैं। तालिबान के लिए यह शहर इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं पर उसका जन्म हुआ था। अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए मुल्ला उमर ने कंधार में ही तालिबान का गठन किया था। (पेज-11)

कंधार शहर की सड़कों पर घूमते तालिबानी। एएफपी

स्वतंत्रता के सारथी

महामारी से आजादी

मुश्किल समय में अर्जुन बने मदद के चैंपियन

ग्रेटर नोएडा: छोटी उम्र में बड़ा नाम और बड़ा काम। विश्व जूनियर गोल्फ चैंपियन अर्जुन भाटी ने देश व समाज के प्रति जिम्मेदारी समझते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की इंटरनेट मीडिया के जरिये मदद कर एक मिसाल कायम की है। (पेज-6)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

देश की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा ट्विटर: राहुल

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर मनमानी का अरोप लगाया है। उन्होंने कहा, कंपनी देश की सियासी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है जो लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एक कंपनी भारत के करोड़ों लोगों की आवाज दबाने में सरकार की मदद कर रही है।

कोरोना से जंग ▸ पृष्ठ 6

मुंबई में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट से पहली मौत

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट के बाद अब उसी से पैदा हुए डेल्टा प्लस वैरिएंट के भी खतरनाक होने की आशंका पैदा हो गई है। मुंबई में डेल्टा प्लस वैरिएंट से पहली मौत हुई है और सबसे चिंता की बात यह है कि जिस महिला की जान गई है, उसने कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज भी लगवा ली थी। महाराष्ट्र में इस वैरिएंट से तीन लोगों की जान जा चुकी है और 65 लोग इससे संक्रमित हुए हैं।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 7

देश में घरेलू विमान यात्रा और महंगी होगी

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराये की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 से 12.82 फीसद तक की वृद्धि की है। इससे घरेलू हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी। इससे पहले पिछले साल पांच मई को विमान सेवाओं के बहाल होने के साथ सरकार ने उड़ान अवधि के आधार पर हवाई किराये पर निचली और ऊपरी सीमाएं लगाई थीं।

नई ऊंचाई पर शेयर बाजार

मुंबई, प्रेट्र: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के शेयरों में तेजी से शुक्रवार को सेंसेक्स 593 अंक की छलांग के साथ पहली बार 55,000 के पार बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 593.31 अंक या 1.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 55,437.29 अंक पर पहुंच गया है। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 55,487.79 अंक के सर्वकालिक उच्चस्तर को भी छुआ।

इसी तरह नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी पहली बार 16,500 अंक के स्तर को पार कर गया। निफ्टी 164.70 अंक या 1.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 16,529.10 अंक के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान यह 16,543.60 अंक तक गया। टीसीएस का शेयर तीन फीसद से ज्यादा चढ़ा। टाटा स्टील और भारती एयरटेल के शेयर में तेजी दिखाई दी।

स्क्रैपेज नीति बदल देगी आटो सेक्टर की तस्वीर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कई वर्षों की योजना को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय आटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति को लांच कर दिया। इस नीति के तहत पुराने व अनफिट वाहनों को नष्ट करने की व्यवस्था होगी। मोदी ने इस नीति को लांच करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ आटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि देश में सर्कुलर इकोनोमी को भी बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से भी बचाया जा सकेगा। इस नीति को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित इन्वेस्टर समिट में लांच किया। देश की आटोमोबाइल कंपनियों ने इस नीति का स्वागत किया है, क्योंकि इससे नए वाहनों की बिक्री बढ़ने की संभावना है। कुछ बड़ी आटोमोबाइल कंपनियां स्क्रैपेज कारोबार में उतर भी रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यह नीति देश में 10 हजार करोड़ रुपये के नए निवेश का रास्ता साफ करेगी, जिससे हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस नीति का एक अन्य फायदा यह होगा कि आयातित स्क्रैप स्टील पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि देश में भी स्क्रैप स्टील उपलब्ध होगा। साथ ही नए वैज्ञानिक तरीके से पुराने धातुओं या वाहनों से बहुमूल्य धातु निकालने का काम भी होगा। मोदी ने उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे अगले 25 वर्षों की दीर्घकालिक नीति तैयार करें कि देश में आयातित स्क्रैपेज पर निर्भरता कैसे कम की जा सकती है।

बदलाव की ओर

- पीएम मोदी ने लांच की राष्ट्रीय आटोमोबाइल स्क्रैपेज पालिसी
- पुराने व अनफिट वाहनों को नष्ट करने की व्यवस्था होगी
- दुनिया का अहम आटोमोबाइल हब बनकर उभरेगा भारत

नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से गांधीनगर में आयोजित इन्वेस्टर समिट में आटोमोबाइल स्क्रैपेज पालिसी लांच की। प्रेट्र

पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपेज में देने पर नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क

- स्क्रैपेज नीति लागू होने के बाद पुराने वाहनों को स्क्रैपेज यानी नष्ट करने वाली एजेंसियों को देने पर ग्राहक को एक प्रमाणपत्र मिलेगा।
- इस प्रमाणपत्र धारक को नया वाहन खरीदने पर कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। कुछ लोगों को रोड टैक्स से भी छूट मिलेगी।

वाहन की आयु नहीं, फिटनेस टेस्ट से होगा स्क्रैपेज में जाने का फैसला

वाहन की आयु से उसके स्क्रैपेज में जाने का फैसला नहीं होगा, बल्कि एक फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके आधार पर इस बारे में फैसला किया जाएगा। अभी तक 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि के बाद वाहनों को स्क्रैपेज में देने की नीति पर विचार किया जा रहा था।

भारत ने गत वर्ष 23 हजार करोड़ रुपये की स्क्रैप स्टील का आयात किया था

भारत ने पिछले वर्ष 23 हजार करोड़ रुपये की स्क्रैप स्टील आयात किया था। सरकार का अनुमान है कि भारत में तत्काल एक करोड़ पुराने वाहनों को स्क्रैपेज में भेजने की जरूरत होगी। यही वजह है कि कई आटोमोबाइल कंपनियां भी इस नए कारोबार में उतरने का एलान कर रही हैं।

गुजरात, असम में स्क्रैपेज प्लांट के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

शुक्रवार को गांधीनगर में हुई बैठक में गुजरात व असम में स्क्रैपेज प्लांट लगाने के लिए सात सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। टाटा मोटर्स ने गुजरात सरकार संग समझौता किया है कि वह अहमदाबाद में स्क्रैपेज सेंटर स्थापित करेगी। यहां सालाना 36 हजार वाहनों को स्क्रैप करने की सुविधा होगी।

यह नीति भारत को दुनिया के एक महत्वपूर्ण आटोमोबाइल हब के तौर पर स्थापित करेगी। जल्द ही देशभर में वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग और स्क्रैपेज सेंटर स्थापित होंगे। नए वाहनों को लांच करने में कंपनियां तेजी दिखाएंगी। -वेंकटराम मामिल्लापल्लेन, रेनो इंडिया के एमडी

विपक्षी सदस्यों के खिलाफ जांच की नायडू ने शुरू की पहल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राज्यसभा के पूर्व महासचिव के साथ पूर्व में हुई ऐसी घटनाओं का किया विश्लेषण
- कार्रवाई का स्वरूप तय करने के लिए एक विशेष जांच समिति का किया जा सकता है गठन

राज्यसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे की जांच कराने के विकल्पों पर गौर किया जा रहा है। इस क्रम में सभापति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को विशेष बैठक कर बुधवार शाम सदन में हुए घटनाक्रमों का विस्तार से अध्ययन व विश्लेषण किया। संकेत हैं कि सदन में धक्का-मुक्की व तोड़फोड़ की घटना की जांच करके इसमें शामिल सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का स्वरूप तय करने को विशेष जांच समिति का गठन किया जा सकता है। सरकार की तरफ से आठ मंत्रियों ने मैदान में उतरकर गुरुवार को इस घटना में शामिल विपक्षी सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी तो विपक्ष ने सड़क पर उतरकर अपने सदस्यों के साथ मारपीट की बात उठाई और एकजुट लड़ाई जारी रखने की ताल ठोंकी थी।

राज्यसभा में हुए घमासान से जुड़े विपक्षी सदस्यों पर कार्रवाई की इन तैयारियों को देखते हुए मानसून सत्र का यह प्रकरण बड़े सियासी विवाद की ओर बढ़ता दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार, बुधवार को सदन में हुए घटनाक्रम से जुड़े पहलुओं पर नायडू ने राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों से बातचीत की और पूर्व में हुई ऐसी घटनाओं को खंगाला। पहले हुई ऐसी घटनाओं को लेकर किस तरह की जांच व कार्रवाई की गई, इसका भी विश्लेषण किया गया। नायडू ने चर्चा के लिए रास के पूर्व महासचिव विवेक अग्निहोत्री को विशेष रूप से बुलाया था।

वेंकैया नायडू। फाइल/ इंटरनेट मीडिया

इस मुद्दे पर विपक्ष भी आक्रामक है, इसीलिए कार्रवाई करने के लिए कानूनी एवं विधायी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। घटना की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जा सकता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही इस संग्राम में दोषी पाए जाने वाले विपक्षी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की पहल होगी। मानसून सत्र के दौरान संसद में सदस्यों के हंगामाखेज व्यवहार पर नायडू की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी बातचीत हुई है जिसमें दोनों ने संसदीय मर्यादा में गिरावट को लेकर चिंता जताई।

बोले, सत्ता पक्ष व विपक्ष उनकी दो आंखें पेज>>3

असम में मंदिरों के पांच किमी दायरे में पशु वध प्रतिबंधित

गुवाहाटी, प्रेट्र: असम में अब मंदिरों के पांच किमी के दायरे में पशु वध नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में असम विधानसभा ने पशु वध, उपभोग एवं परिवहन नियमन करने के लिए लाया गया विधेयक पारित कर दिया। विपक्षी दलों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की जिसे सरकार ने ठुकरा दिया। विरोध में विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया।

विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमरे ने शुक्रवार को जैसे ही असम पशु संरक्षण विधेयक 2020 पारित होने की घोषणा की, सत्ताधारी भाजपा सदस्यों ने 'भारत माता की जय' और 'जय श्रीराम' के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिस समय विधेयक विचार के लिए लाया गया उसी समय एकमात्र निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई सदन से उठकर चले गए। कांग्रेस, एआइयूडीएफ व माकपा ने सरकार से बिल को प्रवर समिति के पास विचार के लिए भेजने का आग्रह किया, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते समय प्रस्ताव ठुकरा दिया। सरमा ने कहा, इस विधेयक को लेकर हमारी कोई बुरी मंशा नहीं है। इससे सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत होगा। उन्होंने कहा, विधेयक का उद्देश्य किसी को गोमांस खाने से रोकना नहीं है, बल्कि जो लोग खाते हैं वे दूसरे की धार्मिक भावनाओं का भी आदर करें।

सरमा ने कहा, 'सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए केवल हिंदू ही जवाबदेह नहीं हैं, मुस्लिम भी उतने ही उत्तरदायी हैं।' विपक्ष की आपत्ति का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कई-कई किमी ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई मंदिर नहीं हैं। राज्य में 70 से 80 हजार ऐसी बस्तियां हैं जहां एक भी हिंदू नहीं है। उन्होंने हालांकि एआइयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम द्वारा लाया गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस्लाम ने विधेयक में परिभाषा से भैंसे को हटाने का प्रस्ताव किया था।

हिमंता बिस्व सरमा। फाइल

असम विधानसभा ने पारित किया पशु संरक्षण विधेयक

बदलता कश्मीर

अलगाववाद के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा श्रीनगर पुलिस का जज्बा

पुलिस ने ट्विटर व होर्डिंग में लालचौक के घंटाघर और उस पर लहराते तिरंगे की तस्वीर की शामिल, 74 वर्षों में यह पहला अवसर है जब पुलिस ने अपने प्रतीक चिह्न में राष्ट्रध्वज को शामिल किया है, अब तक सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को सरकारी इमारतों पर नजर आता था तिरंगा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर के माहौल में बदलाव का असर साफ नजर आने लगा है। जगह-जगह लहराते राष्ट्रध्वज और विभिन्न होर्डिंग में तिरंगे की तस्वीरें जनभावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। राष्ट्रवाद और मुख्यधारा में शामिल होने की भावना से पुलिस भी अछूती नहीं है। श्रीनगर पुलिस ने ट्विटर पर अपने नाम में शुक्रवार को लालचौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर के शिखर पर लहराते तिरंगे की तस्वीर को शामिल किया है। बता दें कि श्रीनगर स्थित लालचौक पिछले 30 वर्षों से राष्ट्रवाद और आतंकवाद, अलगाववाद के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बना रहा था। कहा जाता है कि घंटाघर पर जिसका झंडा होता है, उसका ही यहां श्रीनगर में दबदबा होता है। ऐसे में श्रीनगर पुलिस का यह कदम अलगाववाद के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा।

पिछले 74 वर्षों में यह पहला अवसर है, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस की किसी विंग या किसी जिला पुलिस ने अपने प्रतीक चिह्न अथवा लोगो में इस तरह से राष्ट्रध्वज को शामिल किया हो। पांच अगस्त, 2019 से पूर्व कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों के डर से कोई सार्वजनिक रूप से राष्ट्रध्वज नहीं फहराता था। राष्ट्रध्वज सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही वादी में सरकारी इमारतों या कुछ अन्य स्थानों पर कुछेक लोग ही फहराते नजर आते थे। इसके विपरीत कश्मीर में आए दिन अलगाववादियों और आतंकियों के समर्थक पाकिस्तानी झंडे लेकर गली-बाजारों में निकल आते थे। उनके डर से आम लोग भी पाकिस्तानी झंडा उठाकर भीड़ का हिस्सा बन जाते थे। लोग आतंकियों व अलगाववादियों के फरमान पर स्वतंत्रता दिवस समारोह से भी दूर रहते और राष्ट्रध्वज को थामने से बचते थे। मगर अब परिस्थितियां बदल गई हैं। घाटी के विभिन्न इलाकों में आमजन अब अपने-अपने स्तर पर तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। सभी सरकारी इमारतों और कार्यालयों में राष्ट्रध्वज लहराया जा रहा है। लोगों में इसी भावना को जगाने के लिए श्रीनगर पुलिस ने भी शहर में विभिन्न जगहों पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं जनता को भेंट करते हुए होर्डिंग्स लगाए हैं। इन होर्डिंग्स और अपने ट्विटर हैंडल में श्रीनगर पुलिस ने लालचौक के घंटाघर को शामिल किया है और उसके शिखर पर तिरंगा भी है।

कश्मीर मामलों के जानकार शब्बीर ने कहा कि आज से तीन साल पहले तक श्रीनगर में इस तरह चारों तरफ होर्डिंग्स में तिंरगे की कल्पना नहीं की जा सकती थी। अगर कहीं ऐसा होर्डिंग होता तो उसे कब कौन फाड़ गया, पता नहीं चलता था। पुलिस ने जिस तरह से घंटाघर के शिखर पर तिरंगे को अपने लोगो में शामिल किया है उससे यह साबित होता है कि कश्मीर से अलगाववाद व राष्ट्रविरोधी तत्वों का प्रभाव खत्म हो गया है। अब यहां सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा और नारा चलेगा।

श्रीनगर पुलिस ने ट्विटर में अपने नाम में आइ की जगह लाल चौक और उस पर लहराता तिरंगा शामिल किया है। सौजन्य : पुलिस

हारि पर्वत पर भी लहराएगा राष्ट्रध्वज : डाउन टाउन स्थित हारि पर्वत किले के प्राचीर पर 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज लहराया जाएगा। 100 फीट के ऊंचे स्तंभ पर 24 फीट चौड़ा और 36 फीट लंबा राष्ट्रध्वज होगा। हारि पर्वत में ही मां शारिका भवानी का पौराणिक मंदिर है। मां शारिका जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी पुकारा जाता है, श्रीनगर शहर की ईष्ट देवी भी हैं।

आम्रपाली के बिना दावे वाले 9,538 फ्लैटों की नीलामी को कोर्ट की मंजूरी

- दावा करने के लिए खरीदारों को 15 दिनों का समय देने का भी दिया निर्देश

नई दिल्ली, आइएएनएस : आम्रपाली की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं के 9,538 खरीदार अपने फ्लैटों पर दावा करने के लिए आगे नहीं आए हैं। शीर्ष अदालत ने इस जानकारी के बाद कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर की उस याचिका को अनुमति प्रदान कर दी कि इन फ्लैटों को बिना बिके फ्लैट माना जाए और अगर कोई भी उन पर दावा करने के लिए आगे न आए तो अगला कदम उनका आवंटन रद करना और उनकी नीलामी करने का होना चाहिए ताकि बाकी बचीं अधूरी परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन जुटाया जा सके।

जस्टिस यूयू ललित व अजय रस्तोगी की पीठ को बताया गया कि अदालत से नियुक्त रिसीवर व वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमानी और एनबीसीसी ने संयुक्त रूप से ऐसे सभी खरीदारों से संपर्क करने की कोशिश की जिन्हें विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में कथित रूप से फ्लैट बेचे गए हैं। रिसीवर की ओर से कोर्ट में दाखिल नोट के मुताबिक, 9,538 फ्लैट खरीदारों ने न तो रिसीवर कार्यालय के उपभोक्ता डाटा में पंजीकरण कराया है और न ही जुलाई, 2019 में अदालत के फैसले के बाद से कोई भुगतान किया है। पीठ ने कहा कि इन खरीदारों को अंतिम नोटिस दिया जाना चाहिए और अगर 15 दिनों में वे इन फ्लैटों पर दावा करने के लिए आगे नहीं आते तो रिसीवर आवंटन रद करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

कोर्ट से नियुक्त फोरेंसिक आडिट रिपोर्ट के मुताबिक, ये फ्लैट बेनामी या फर्जी बुकिंग के हो सकते हैं। वेंकटरमानी ने कोर्ट को यह भी बताया कि उपभोक्ता डाटा में पंजीकृत 6,210 खरीदार कोई भी भुगतान नहीं कर रहे हैं।

0.07 फीसद कोरोना की संक्रमण दर राजधानी में है। लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। लेकिन 50 नए मामले सामने आए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 अगस्त, 2021

कड़वी यादें भुला लालकिला भी जश्न मनाने को तैयार

वी के शुक्ला, नई दिल्ली

देश की शान लालकिले पर गत 26 जनवरी को कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान जो तोड़फोड़ की थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्वतंत्रता दिवस पर उसे ठीक करा लिया है। यहां तक कि लालकिले के मुकुट से उतार लिए गए दो ऐतिहासिक कलश भी फिर से स्थापित कर दिए गए हैं। इस तरह गणतंत्र दिवस की कड़वी यादें भुलाकर लालकिले भी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है।

गणतंत्र दिवस को हुए उपद्रव में 400 साल पुराने स्मारक लालकिले को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। उपद्रवियों ने लालकिले के टिकट काउंटर को तहस-नहस कर दिया था। वहां लगा पूरा कांच, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे। पर्यटकों के किला में प्रवेश के लिए लगाए गए सभी सात टर्नस्टाइल गेट (टोकन डालने पर खुलने वाले आटोमेटेड गेट) तोड़ दिए थे।

वहां की लाइट भी तोड़ दी गई थी। गत 26 जनवरी को हुई शर्मसार कर देने वाली वह घटना देश के लोगों को अब भी याद है, जब उपद्रवियों ने लालकिले पर कब्जा कर लिया था। लालकिले के मुकुट कहे जाने वाले यानी सबसे ऊपरी भाग में लाहौरी गेट पर सात गुंबदों पर कलशों के बीच हर समय लहराने वाले तिरंगे के साथ उपद्रवियों ने अपना झंडा लगा दिया था। इन सात कलशों में से तिरंगा के दोनों ओर वाले दो गुंबदों से उपद्रवियों ने कलश भी उतार लिए थे। तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने भी उस समय मौके पर पहुंचकर घटना पर दुख व्यक्त किया था। इस मामले की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने गृह मंत्रालय को सौंपी थी।

अब सभी तरह की तोड़फोड़ एएसआइ ने ठीक करा ली है। टर्नस्टाइल गेट ठीक करा लिए हैं। लाइटें व सीसीटीवी ठीक हो चुके हैं। निकाले गए दोनों कलश भी कुशल कारीगरों से लगवा दिए गए हैं।

▸ गणतंत्र दिवस पर हुई थी तोड़फोड़, स्वतंत्रता दिवस पर ठीक हुई

26 जनवरी को कृषि सुधार कानूनों के विरोध में लाल किले पर प्रदर्शनकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त लाल किले के कलश को फिर से लगाया गया। ध्रुव कुमार

जश्ने आजादी के रंग से सराबोर होंगे दूरदर्शन-आकाशवाणी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत के मौके पर 15 अगस्त से दूरदर्शन और आकाशवाणी भी जश्ने आजादी के रंग से सराबोर होंगे। सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए जनभागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी ही नहीं मंत्रालय की दूसरी मीडिया यूनिटों के जरिये राष्ट्रीय भावना को जगाने वाले अनेक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। इनमें देशभक्ति का भाव जगाने वाली फिल्मों के प्रसारण से लेकर राष्ट्रीयता के रंग से सराबोर फिल्मों के समारोह का आयोजन भी शामिल है। इस पहल में इसका खास ख्याल रखा है कि लोग स्वतंत्रता की भावना के अनुरूप नए भारत के सफर में अपनी भागीदारी का अहसास कर सकें। आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और बलिदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी 15 अगस्त को एक विशेष कार्यक्रम की शृंखला 'आजादी का सफर, आकाशवाणी के संग' शुरू कर रही है। रोजाना एक स्वतंत्रता सेनानी के जीवन और योगदान पर पांच मिनट के एक कैप्सूल का प्रसारण होगा। इसी तरह बड़े ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर दूरदर्शन भी पांच मिनट का एक कैप्सूल रोज प्रसारित करेगा। लालकिले से स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे प्रसारण के बाद दो चर्चित देशभक्ति से जुड़ी फिल्में भी दिखाएगा।

सुरक्षा की गई चाक चौबंद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा आतंकी हमले के इनपुट को ध्यान में रखते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले व उसके आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हवाई हमले को लेकर अलर्ट जारी है। इसके चलते पुलिस ने एंटी एयरक्राफ्ट मशीनगन ऊंची इमारतों पर लगाई हैं। इसके अलावा पहली बार लालकिले के मुख्य गेट पर कंटेनर की छह मंजिला दीवार बनाई गई है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। लालकिले के पास कार्यक्रम के दौरान पांच हजार से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे।

इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के चलते लालकिले पर आने वाले मेहमानों की संख्या सीमित होगी। लेकिन सुरक्षा चक्र पहले से बेहद मजबूत रहेगा। पांच हजार से ज्यादा जवानों की तैनाती के साथ ही आसपास 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फेस रेकाग्निजेशन सुविधा से लैस कैमरे भी लगाए गए हैं जिनमें संदिग्ध आतंकियों का डाटा होता है। इनमें से कोई भी शख्स अगर कैमरे के सामने आएगा तो तुरंत यह कैमरे पुलिस को अलर्ट करेंगे। यहां वरिष्ठ अधिकारियों को छोटे-छोटे क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बल, एनएसजी, एसपीजी आदि भी सुरक्षा घेरे में रहेंगे। जमीन से आसमान तक पुलिस सहित विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों की नजर रहेगी।

पुलिस सूत्रों की माने तो इस बार लाल किला की सुरक्षा इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बार्डर पर बैठे कृषि सुधार कानूनों के विरोधी प्रदर्शनकारी गणतंत्र दिवस पर यहां उपद्रव कर चुके हैं। यही वजह है कि लालकिले के मुख्य प्रवेश द्वार पर बड़े-बड़े कंटेनर रखे गए हैं। किसान नेताओं ने भले ही लालकिले की तरफ आने की घोषणा नहीं की है लेकिन पुलिस हर स्थिति से निपटने की तैयारी कर चुकी है।

पुलिस के वेश में घुसपैठ कर सकते हैं खालिस्तान समर्थक: शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार, बैठक का एजेंडा स्वतंत्रता दिवस सुरक्षा और एजेंसियों द्वारा दी गई ताजा खुफिया अलर्ट है। असामाजिक तत्व और खालिस्तान समर्थक दिल्ली पुलिस के जवानों के वेश में लालकिले की सुरक्षा में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं।

न्यूज गैलरी

आनलाइन होंगी प्रायोगिक परीक्षाएं : सीबीएसई

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से जारी 12वीं के परिणाम में इस बार कुछ छात्रों की प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) परीक्षाओं में कंपार्टमेंट आई है। इन छात्रों के परिणाम में आरपी (रिपीट प्रैक्टिकल) लिखा हुआ है। बोर्ड के अनुसार इन छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा के साथ थ्योरी (सैद्धांतिक) परीक्षा भी अनिवार्य तौर पर देनी होगी। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया कि 25 अगस्त से सैद्धांतिक परीक्षाएं होने वाली हैं। साथ ही उन्हें प्रायोगिक परीक्षाएं आनलाइन माध्यम से ही आयोजित करानी होंगी। (जासं)

डीयू स्नातक पाठ्यक्रमों में सवा लाख से अधिक पंजीकरण

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन प्रक्रिया दो अगस्त से शुरू हुई थी। डीयू प्रशासन ने बताया कि शुक्रवार शाम पांच बजे तक स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 2 लाख 26 हजार 599 छात्रों ने पंजीकरण किया। इनमें 80 फीसद से अधिक छात्रों ने पंजीकरण शुल्क जमा कर आवेदन प्रक्रिया पूरी की। डीयू पोर्टल पर ईमेल के जरिये छात्र पंजीकरण करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन जरूरी होता है। छात्र 31 अगस्त तक पंजीकरण कर सकते हैं। (जासं)

स्वतंत्रता दिवस पर सात घंटे उड़ानों पर रहेगी रोक

नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा इंतजामों का असर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पर भी नजर आएगा। दो अलग- अलग चरणों में कुल सात घंटे एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पर रोक रहेगी। डायल के मुताबिक 15 अगस्त को सुबह छह बजे से सुबह दस बजे तक विमानों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके बाद छह घंटे तक विमानों की आवाजाही सामान्य तरीके से होगी। लेकिन चार बजते ही एक बार फिर विमानों की आवाजाही रोक दी जाएगी। यह रोक शाम सात बजे तक रहेगी। (जासं)

तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली : जंतर-मंतर पर एक खास समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपितों की जमानत याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट उद्भव कुमार जैन ने कहा कि पेश किए गए वीडियो में मौजूद तथ्य अलोकतांत्रिक हैं और इस देश के नागरिक से इस तरह की नारेबाजी करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने प्रीत सिंह, दीपक सिंह व विनोद शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। (जासं)

अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रात में भी होंगे टेस्ट

सुविधा ▸ बढ़ रही वेटिंग के कारण सरकार ने लिया फैसला

ट्रैक पर लगाई जाएंगी उच्च क्षमता वाली लाइटें

वी.के.शुक्ला,नई दिल्ली

ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए बढ़ रही वेटिंग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रात में भी टेस्ट कराने का फैसला लिया है। अब सभी आटोमेटेड ट्रैक पर रात में भी टेस्ट लिए जाएंगे। इसके लिए सभी जोनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) के ट्रैक पर रोशनी की उच्च क्षमता वाली लाइटें लगाई जाएंगी। इन ट्रैक पर इतनी बेहतर रोशनी होगी कि दिन की तरह दिखेगा ट्रैक। लाइटें लगाने के बाद यह व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। अभी लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबी वेटिंग मिल रही है।

आने वाले समय में दिल्ली में लाइसेंस बनवाने के लिए रात में भी आटोमेटेड ट्रैक पर टेस्ट के लिए तैयारी चल रही है। इसे लेकर परिवहन मंत्री विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी कर चुके हैं। यह ऐसा प्रयोग होगा कि जिससे टेस्ट के लिए वेटिंग कम होगी। जिन लोगों को सुविधा होगी उन्हें रात में टेस्ट के लिए समय दिया जाएगा। योजना के अनुसार पहले चरण में इस व्यवस्था को रात नौ या दस बजे तक किए जाने पर विचार किया जा रहा है। अगर प्रयोग सफल रहा तो रात में टेस्ट को और आगे बढ़ाया जा सकेगा।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि ड्राइविंग टेस्ट की वेटिंग कम करने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों को ज्यादा दिन की वेटिंग न मिले। इसी के मद्देनजर रविवार को भी टेस्ट की अनुमति दी गई है। उससे काफी लाभ मिला है। अब हम रात में भी टेस्ट की अनुमति देने जा रहे हैं। इसके लिए सभी अथारिटी के ट्रैक पर उच्च क्षमता की रोशनी देने वाली लाइटें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द इस सेवा को शुरू कर दिया जाए।

दिल्ली में 13 ट्रांसपोर्ट अथारिटी चल रही हैं। यहां अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, पीएसवी (पब्लिक सर्विस व्हीकल) बैज, वाहनों का पंजीकरण व परिचालक लाइसेंस आदि जारी किए जाने का काम कार्यालय जाकर कराना पड़ता था। उसे अब आनलाइन कर दिया गया है। अब केवल लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट के लिए ही परिवहन विभाग जाना होगा। इसके अलावा वाहनों की फिटनेस के लिए भी कार्यालय जाना होगा।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। सौजन्य-दिल्ली सरकार

जुलाई में आए कुल आवेदन	90710
लर्निंग लाइसेंस	26167
ड्राइविंग लाइसेंस	62864
कंडक्टर लाइसेंस	1530
जुलाई में कुल टेस्ट	37789

डीडीए एसटीएफ ने दिए लंबित मामलों पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मास्टर प्लान और उससे संबंधित कानूनों के प्रविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर डीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की 70वीं बैठक हुई। इसमें लंबित मामलों के निस्तारण में देरी को लेकर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रति नाराजगी जताई गई। साथ ही इन मामलों पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

डीडीए मुख्यालय में शुक्रवार को हुई बैठक में बताया गया कि 31 जुलाई 2021 तक कुल 90 हजार 394 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसमें 86 हजार 246 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। वहीं एक जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 के बीच 4 हजार 178 एटीआर प्राप्त हुईं। इस दौरान एनडीएमसी द्वारा कनाट प्लेस, पालिका बाजार, गोल मार्केट, जनपथ, शंकर मार्केट, एलबीएन, सरोजनी नगर और चाणक्यपुरी, वीआइपी एरिया में अतिक्रमण रोधी बड़ा अभियान चलाया गया। एसडीएमसी द्वारा दो जुलाई को मालवीय नगर, पुष्प विहार में 16 जुलाई 2021 को वसंत कुंज, छतरपुर, सफदरजंग, चर्च रोड, आरकेपुरम में 26 जुलाई को वसंत विहार, अरबिंदो प्लेस मार्केट और 31 जुलाई 2021 को साकेत, डीडीए फ्लैट कालका जी, एम ब्लाक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-दो में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया। राजस्व विभाग द्वारा एक से 31 जुलाई के बीच एसएसएन रोड, इग्नू रोड, एमबी रोड और देवली से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

सीएम 23 को कर सकते हैं दिल्ली के पहले स्माग टावर का उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त को कनाट प्लेस में राष्ट्रीय राजधानी के पहले स्माग टावर का उद्घाटन कर सकते हैं। इसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसका उद्घाटन पहले 15 अगस्त को होना था, लेकिन अब 23 अगस्त को होगा। 20 मीटर से अधिक ऊंचा यह ढांचा लगभग एक किमी के दायरे में हवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि स्माग टावर के निर्माण में देरी की वजह कोरोना संकट बना है। पिछले साल अक्टूबर में इस पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। यह स्माग टावर प्रति सेकंड 1,000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करने में सक्षम होगा। यह टावर चालू होने के बाद उसकी प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए दो साल तक अध्ययन किया जाएगा।

वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिकारियों ने कहा कि आनंद विहार में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक और 25 मीटर ऊंचा स्माग टावर 31 अगस्त तक चालू होने की उम्मीद है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टीपीएल) आइआइटी-बांबे के तकनीकी समर्थन से दो स्माग टावरों का निर्माण कर रहा है, जो आइआइटी-दिल्ली के सहयोग से उनके प्रदर्शन को मान्य करेगा। इसके लिए एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

अरविंद केजरीवाल। फाइल फोटो

सीपीसीबी आनंद विहार में बन रहे टावर के लिए नोडल एजेंसी है, जबकि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति कनाट प्लेस में बनाए गए टावर की नोडल एजेंसी है। दोनों टावरों में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा विकसित 1,200 एयर फिल्टर होंगे- जिसने चीन के जियान में 100 मीटर ऊंचे स्माग टावर को डिजाइन करने में भी मदद की। प्रत्येक 22 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे स्माग टावरों से उनके आसपास के एक किलोमीटर के दायरे में पीएम 2.5 की सांद्रता को 70 फीसद तक कम करने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में केंद्र सरकार को आनंद विहार में प्रदूषण कम करने के लिए एक स्माग टावर बनाने और दिल्ली सरकार को तीन महीने में कनाट प्लेस में इस तरह की एक और टावर स्थापित करने का निर्देश दिया था। अगस्त में शीर्ष अदालत ने इन टावरों के निर्माण को पूरा करने में समय सीमा से चूकने पर केंद्र और राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी।

भारत का गौरव है उसकी ज्ञान परंपरा : भागवत

'भारत वैभव' पुस्तक का विमोचन करते सरसंघचालक डा मोहन भागवत, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सांसद डा सत्यपाल सिंह और न्यास के अध्यक्ष प्रो गोविन्द प्रसाद शर्मा (दाएं)। सौजन्य : एनबीटी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत का कहना है कि स्व गौरव से बड़ा कोई गौरव नहीं है और भारत का गौरव उसकी ज्ञान परंपरा है। भारत का जन्म ही पूरे विश्व में ज्ञान परंपरा को बांटने के लिए हुआ है। भागवत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'भारत वैभव' के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

शुक्रवार को न्यास के वसंत कुंज स्थित मुख्यालय में पुस्तक का विमोचन किया गया। भागवत ने कहा कि गागर में सागर भरने वाली इस पुस्तक का अनुवाद राष्ट्र की सभी भाषाओं में किया जाना चाहिए और व्यापक प्रचार होना चाहिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का मनोबल और आत्मविश्वास अपनी संस्कृति के सहारे ही जागृत हुआ है। भारतीय संस्कृति आज भी सनातन है और यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम इसे जानने की पूर्ण कोशिश करें। समारोह को सांसद डा. सत्यपाल सिंह, न्यास के अध्यक्ष प्रो. गोविन्द प्रसाद शर्मा व निदेशक युवराज मलिक ने भी संबोधित किया।

जातीय घृणा के चलते यौन शोषण के मामले में फंसाया गया व्यक्ति बरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जातीय घृणा के चलते चार बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में फंसाए गए एक दलित व्यक्ति को बरी करते हुए तीस हजारी अदालत ने कहा कि हमारे समाज में अच्छे और बुरे के बीच हमेशा लड़ाई रही है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं, जहां समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और सब कुछ संभव है। जिला सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि हमारा अनुभव रहा है कि लोग असंख्य कारणों से झूठे आरोप लगाते हैं और जातीय घृणा इसमें से एक है। अदालत ने इस तरह के संगीन आरोप लगाने वाले बच्चियों के पिता को भी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बेशर्म तरीके से बच्चियों का इस्तेमाल किया है।

साथ ही मामले की गंभीरता से जांच नहीं करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि जांच ढुलमुल तरीके से की गई और इसमें वस्तुनिष्ठता की कमी है। अदालत ने दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यह मुआवजा प्रतीकात्मक है।

हत्या से पहले दुष्कर्म की पुष्टि का नहीं है कोई सुबूत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में कोर्ट में पुलिस का जवाब

▸ अदालत ने पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रुपये का अंतरिम राहत देने का दिया आदेश

दिल्ली कैंट में नौ वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने पटियाला हाउस अदालत में कहा कि अब तक ऐसा कोई सुबूत नहीं मिल सका है जिससे पुष्टि की जा सके कि हत्या से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था या नहीं। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार को जांच अधिकारी ने बताया कि चारों आरोपितों के बयान से पता चला है कि इनमें से दो आरोपित श्मशान घाट के 55 वर्षीय पुजारी राधे श्याम और उसके कर्मचारी कुलदीप सिंह ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं, अन्य दो आरोपित सलीम अहमद व लक्ष्मी नारायण ने बच्ची के शव का अंतिम संस्कार करने में मदद की थी। अदालत ने चारों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

हालांकि, जांच अधिकारी ने कहा कि अब तक ऐसा कोई चश्मदीद गवाह, बयान, वैज्ञानिक या चिकित्सकीय साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे पुष्टि हो सके कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था या नहीं। जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपितों के बयानों के सापेक्ष अगर कोई अन्य सुबूत न हों तो अदालत इसे स्वीकार नहीं करती है।

विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने एक आवेदन पर सुनवाई के बाद बेटी के जीवन के नुकसान के लिए बच्ची की मां को 2.5 लाख रुपये की अंतरिम राहत देने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने जांच अधिकारी के बयान को देखते हुए पीड़िता की मां को अतिरिक्त अंतरिम राहत नहीं दी, क्योंकि जांच एजेंसी खुद सुनिश्चित नहीं है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं। अदालत ने कहा कि ऐसे में इस स्तर पर अंतरिम मुआवजे की अनुमति नहीं है।

इजरायली दूतावास के निकट विस्फोट मामले में एनआइए के हाथ खाली

नई दिल्ली, आइएएनएस : इजरायली दूतावास के निकट विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को उन दो संदिग्धों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिनकी पहचान बताने वालों को जांच एजेंसी ने 15 जून को 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

बता दें कि 29 जनवरी को राजधानी दिल्ली के विजय चौक से लगभग दो किमी दूर डा. एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के निकट बम विस्फोट हुआ था। एजेंसी ने विस्फोट मामले में सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए थे, जिसमें बम रखने वाले दो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। वे लोग अपना चेहरा ढककर सड़क पर चलते दिख रहे हैं। एजेंसी ने लोगों से अपील की थी कि यदि किसी को इन संदिग्धों के बारे में कुछ पता चलता है तो वे उसकी अधिकृत वेबसाइट और फोन नंबरों पर जानकारी दे सकते हैं।

एजेंसी ने कहा कि इतने दिन बाद भी उसे उन संदिग्धों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जम्मू-कश्मीर के कुछ छात्रों से पूछताछ की गई, लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं मिली।

जबाव तलब

केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ डीसीपीसीआर व दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

भीख मांगने की प्रथा खत्म करने की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बच्चों द्वारा भीख मांगने पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

याचिकाकर्ता अजय गौतम ने अधिकारियों को भिखारी बच्चों का पुनर्वास करने और बच्चों, किशोर लड़कियों और छोटे बच्चों भीख मांगने के अपराध में धकेलने वालों की पहचान कर गिरफ्तार करने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के हर हिस्से में भिखारियों की मौजूदगी के बावजूद इस दिशा में कोई कदम उठाने में सरकार व प्रशासन नाकाम हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि इसके पीछे एक माफिया गिरोह सक्रिय है और वे वास्तव में भीख मांगने के लिए मासूम बच्चों का अपहरण, प्रशिक्षण और अत्याचार करते हैं। लोगों ही सहानुभूति लेने के लिए सर्दियों में जानबूझकर बच्चों को बिना कपड़ों के रखा जाता है।

छह सितंबर से हाई कोर्ट में शुरू होगी फिजिकल सुनवाई

कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट व निचली अदालतों में एक बार फिर फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए निर्णय के बाद रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन द्वारा जारी आदेश के तहत हाई कोर्ट में छह सितंबर से फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। वहीं, निचली अदालतों में 31 अगस्त से ही भौतिक सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसे तभी लागू किया जाएगा जब कोरोना महामारी नियंत्रण में रहेगी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल द्वारा तय कुछ ही पीठ फिजिकल रूप से सुनवाई करेंगी, जबकि अन्य पीठ पूर्व की तरह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई जारी रखेंगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अदालतों का रोस्टर इस तरह से तैयार किया जाएगा कि सप्ताह में प्रत्येक अदालत एक बार फिजिकल रूप से सुनवाई करे। फिजिकल सुनवाई के दौरान में हाईब्रिड वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई की अनुमति रहेगी। इसके तहत अगर कोई भी पक्ष या उनके वकील चाहे तो वीडियो कांफ्रेंसिंग या फिजिकल रूप से सुनवाई में शामिल हो सकता है।

एम्स ट्रामा सेंटर में हादसा पीड़ितों का इलाज शुरू करने की मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : एम्स ट्रामा सेंटर पिछले करीब डेढ़ साल से कोरोना के अस्पताल में तब्दील है। इस वजह से ट्रामा सेंटर में कोरोना का ही इलाज होता रहा है। इससे वहां हादसा पीड़ितों का इलाज बंद है। एम्स के रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने अब ट्रामा सेंटर में दोबारा हादसा पीड़ितों के इलाज की सुविधा शुरू करने के लिए आवाज उठाई है। इस बाबत आरडीए ने एम्स के निदेशक डा. रणदीप गुलेरिया को पत्र लिखकर ट्रामा सेंटर में पहले की तरह हादसा पीड़ितों के इलाज की सुविधा शुरू करने व किसी दूसरे सेंटर में कोरोना के इलाज की व्यवस्था करने की मांग की है। क्योंकि हादसा पीड़ितों का इलाज प्रभावित हो रहा है।

आरडीए ने अपने पत्र में कहा है कि पिछले साल 28 मार्च को ट्रामा सेवाओं को मुख्य अस्पताल की ओपीडी में स्थानांतरित किया गया था।

सात वर्षीय छात्र की हत्या पर बनी फिल्म के प्रसारण पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में 2017 में सात वर्षीय बच्चे की हत्या पर आधारित फिल्म 'ए बिग लिटिल मर्डर' के प्रसारण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पीठ ने कहा कि गुरुग्राम की सत्र अदालत ने आठ जनवरी, 2018 को स्कूल का नाम व इमारत को दिखाने पर रोक लगाई थी और इस तरह से फिल्म में इसे दर्शा कर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया है। स्कूल से जुड़े संदर्भ हटाकर फिल्म का प्रसारण किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं।

पीठ ने नेटफ्लिक्स, चैनल न्यूज एशिया और अन्य को स्कूल के भवन, गेट या अन्य किसी तरह के पहचान को हटाने के बाद ही प्रसारण करने को कहा है। पीठ ने इसके साथ ही सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 21 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

2017 में गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में की गई थी दूसरी कक्षा के बच्चे की हत्या

जेवियर एजुकेशन ट्रस्ट ने याचिका दायर कर फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। ट्रस्ट की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव विरमानी ने कहा कि फिल्म सीएनए की वेबसाइट और नेटफ्लिक्स पर इस माह की शुरुआत में लोगों के देखने के लिए उपलब्ध थी। उन्होंने फिल्म के प्रसारण, स्ट्रीमिंग और किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम में फिल्म या इसके ट्रेलर या संक्षिप्त संस्करणों पर भी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामला अभी गुरुग्राम कोर्ट में विचाराधीन है और अदालत ने आदेश दिया था कि मामले से जुड़े पक्षकारों के नाम किसी भी माध्यम से सार्वजनिक नहीं किए जाएं।

152 पुलिस कर्मियों को इस साल जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। सम्मान पाने वालों में सीबीआइ के 15, एमपी व महाराष्ट्र के 11-11, उप्र के 10, केरल व राजस्थान के नौ-नौ, तमिलनाडु के आठ पुलिस अफसर शामिल हैं।

अगले 25 वर्षों में हमें बनाना होगा एक भारत, श्रेष्ठ भारत : राजनाथ

नई दिल्ली, एएनआइ : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले 25 वर्षों में हमें भारत को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' एक समृद्ध, आत्म-निर्भर और आत्म-सम्मान वाला देश बनाना होगा। भारत किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन दूसरा जो कोई भी बुरी नजर से देखेगा उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

रक्षा मंत्री ने कहा, 'आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 में किस तरह का भारत हम बनाएंगे? हमें 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत', समृद्ध, आत्म-निर्भर, आत्म-सम्मान से पूर्ण भारत- जो किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन हम पर बुरी निगाह रखने वाले को मुंहतोड़ जवाब देता है- बनाना होगा। आने वाले समय में हम और मजबूत भारत बनाएंगे।' राजनाथ ने कहा, 'आज हम 'अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। स्वतंत्रता, संप्रभुता और अमरता की भावना भारत के लिए नई या आधुनिक

नई दिल्ली में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ से जुड़े राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

नहीं है। मैं कैप्टन विक्रम बत्रा का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने मौत को सामने देख कहा था 'यह दिल मांगे मोर।' यह भावना क्या है? मैं उन सभी अमर सपूतों के लिए सिर झुकाता हूं जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए।'

कई बड़े कार्यक्रमों की वर्चुअली शुरुआत की : प्रेट्र के मुताबिक, रक्षा मंत्री ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कई बड़े कार्यक्रमों की वर्चुअली शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों से न केवल राष्ट्रीय भावना में, बल्कि देश के आत्म सम्मान में भी वृद्धि होती है। एक कार्यक्रम सीमा सड़क संगठन का है जिसके तहत सीमा क्षेत्र के 75 रिमोट स्थानों के लिए 75 टीमें रवाना हुई हैं। ये टीमें वहां 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी।

देश की दिशा तय करेगा फिट इंडिया : अनुराग ठाकुर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0
- अभियान के तहत 7.5 करोड़ लोगों को जोड़ने की कोशिश

मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत के मौके पर दौड़ लगाते केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व खेल राज्यमंत्री निसिथ प्रामाणिक (दाएं)। ध्रुव कुमार

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की कड़ी में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से हुई। केंद्रीय युवा मामलों व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व खेल राज्यमंत्री निसिथ प्रामाणिक ने इस दौड़ को झंडी दिखाई व खुद भी दौड़ लगाई।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्वस्थ रहने की शपथ दिलाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में अगले 25 वर्षों में हमारा राष्ट्र क्या आकार और दिशा लेगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि हम कितने फिट हैं। उन्होंने कहा कि एक युवा मन, शरीर और आत्मा स्वस्थ और फिट इंडिया के प्रमुख तत्व हैं। केवल 'फिट इंडिया' ही हिट इंडिया बनाएगा। हर नागरिक को फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। खेल मंत्री ने असम के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कार्मिकों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि 75 स्थानों के लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति तक यह पहुंचेगा। ठाकुर ने बताया कि यह अभियान 75 ऐतिहासिक स्थानों से शुरू किया गया है, जो देशभर के सभी जिलों तक पहुंचेगा। इसके बाद 75 गांवों में जाकर 'फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज' अभियान को बढ़ावा देगा। फ्रीडम रन 15 अगस्त से शुरू होगा और दो अक्टूबर, 2021 तक चलेगा। हमारा लक्ष्य अभियान के माध्यम से देश भर में 7.50 करोड़ से अधिक युवाओं और नागरिकों तक पहुंचना है।

हमें अपनी एकता, अखंडता कायम रखनी है : सीडीएस

नई दिल्ली, एएनआइ : चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उन संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे जो हमारी एकता पर आघात का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी एकता और अखंडता कायम रखनी है।

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रावत ने कहा कि आजादी हासिल करने के बाद भारत को हमलों के आलोक में अपने सशस्त्र बलों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा बलों के आधुनिकीकरण का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र के रूप में भारत ने दूसरे देशों को राह दिखाई है। देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दी और आश्वस्त किया कि सशस्त्र बल उन्हें सुरक्षित रखेंगे।

देश की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा ट्विटर : राहुल

लगाए आरोप ▸ कांग्रेस नेता ने कहा, राजनीतिक मुकाबले में कंपनी का पक्षपाती होना खतरनाक

खुद के ट्विटर अकाउंट को लाक करने को देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर बताया हमला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लगाए आरोप : राहुल गांधी। जागरण आर्काइव

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर मनमानी का अरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कंपनी देश की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है जो लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है। राहुल ने अपना अकांउट लाक किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक मुकाबले में ट्विटर का पक्षपाती होना खतरनाक ही नहीं देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला भी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक कंपनी भारत के करोड़ों लोगों की आवाज दबाने में सरकार की मदद कर रही है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के इस तीखे हमले के बाद अकांउट लाक करने के मुद्दे पर ट्विटर के साथ कांग्रेस नेताओं की जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक वीडियो बयान जारी कर केंद्र सरकार के दबाव में ट्विटर के ऐसा कदम उठाने की बात कही। कांग्रेस नेता ने कहा कि 'मेरे ट्विटर हैंडल पर रोक लगा कर वे हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक कंपनी हमारी राजनीति को परिभाषित करने का कारोबार कर रही है और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर मुझे यह पसंद नहीं है।'

राहुल ने आगे कहा, 'ट्विटर का यह कदम उन पर नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। यह बात केवल राहुल गांधी को चुप कराने तक सीमित नहीं है। मेरे करीब दो करोड़ फालोअर्स हैं। आप उन्हें अपने विचार रखने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं।'

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह कदम न केवल पूरी तरह से अनुचित है, बल्कि यह ट्विटर के एक तटस्थ मंच होने की अवधारणा के भी प्रतिकूल है। इस लिहाज से निवेशकों के लिए भी यह अत्यधिक खतरनाक बात है, क्योंकि राजनीतिक मुकाबले में पक्ष लेने से ट्विटर पर असर पड़ता है।

संसद में भी बोलने नहीं दिया जाता : ट्विटर अकाउंट लाक किए जाने और संसद में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलने की घटनाओं को जोड़ते हुए राहुल ने कहा, 'हमारे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। मीडिया नियंत्रित है। मुझे लगा था कि ट्विटर एक ऐसी प्रकाश की किरण है, जहां हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि ट्विटर वास्तव में एक तटस्थ मंच नहीं, बल्कि पक्षपात से ग्रसित मंच है और यह वही सुनता है, जो सरकार कहती है।'

सरकार के दबाव में ट्विटर : राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर के इस तरह के बर्ताव पर देश को गौर करने की जरूरत है और भारतीय के रूप में हमें यह प्रश्न पूछना होगा कि क्या हम कंपनियों को सिर्फ इसलिए अनुमति देने जा रहे हैं, क्योंकि वे हमारी राजनीति को परिभाषित करने के लिए भारत सरकार के समक्ष नतमस्तक हैं? क्या यही होता रहेगा या देश के नागरिक अपनी राजनीति को स्वयं परिभाषित करेंगे, यही असली सवाल है।

क्यों बंद हुआ राहुल का अकाउंट : बता दें कि दिल्ली में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के बाद पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। उन्होंने बच्ची के स्वजन से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा की। भाजपा नेताओं और राष्ट्रीय बाल आयोग ने इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग उठाई तो ट्विटर ने राहुल ही नहीं कांग्रेस के आधिकारिक अकांउट के साथ ही करीब पांच हजार से ज्यादा कांग्रेस नेताओं- कार्यकर्ताओं-समर्थकों के अकांउट बंद कर दिए हैं।

राहुल के समर्थन में आई प्रियंका : प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर राहुल के बयानों का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, 'सबसे गंभीर बात ये है कि एक कंपनी अपने व्यापार के लिए इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रही है, भारत के करोड़ों लोगों की आवाज दबाने में सरकार की मदद कर रही है।'

ट्विटर अकाउंट बंद होने पर भाजपा का राहुल गांधी पर तंज

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट बंद होने पर भाजपा ने तंज किया है। भाजपा सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी को उस इकलौती जगह से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जहां वह सक्रिय थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपना अकाउंट बहाल कराने के लिए मोदी सरकार द्वारा इंटरनेट मीडिया के लिए लाए गए नए कानून का उपयोग करना चाहिए। सूर्या ने कहा कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए सरकार जब नए आइटी कानून लेकर आई थी, तब कांग्रेस ही सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी। राहुल गांधी दुष्कर्म के बाद मार दी गई बच्ची के परिजनों के साथ फोटो साझा कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ नहीं ले सकते।

सदन में तोड़फोड़ विपक्ष की बिना जमीन की जमींदारी : नकवी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

मुख्तार अब्बास नकवी। जागरण आर्काइव

राज्यसभा में पिछले दिनों जिस तरह विपक्षी दल के लोग मार्शल से भिड़े, तोड़फोड़ और हिंसा की वह लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। इससे समूचा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की सियासी सनक, लोकतंत्र पर हमले की सामंती साजिश तक पहुंच गई है। वास्तव में यह घटना बिना जमीन की जमींदारी और विपक्ष की चौधराहट है। यह कहना है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। वह शुक्रवार को प्रयागराज हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। यहां से अल्पसंख्यक मंत्री अपने पैतृक गांव भदारी के लिए रवाना हो गए। वह हर साल मोहर्रम के समय अपने पैतृक गांव जाते हैं।

विपक्ष सदन को वाश आउट करने की वाशिंग मशीन लेकर घूम रहा : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष मानसून सत्र के पहले दिन से ही सदन को वाश आउट करने की वाशिंग मशीन लेकर घूम रहा था। वह नियमों, सिद्धांतों और परंपराओं की बलि चढ़ा रहा है। कांग्रेस सहित सभी दलों ने मांग की कि प्रधानमंत्री कोरोना के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराने के लिए मीटिंग बुलाएं, लेकिन जब उनकी मांग पर अमल हुआ तो उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार किया।

राहुल गांधी को भूलने की बीमारी

राहुल गांधी के प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह सुबह क्या सोचते हैं, शाम को भूल जाते हैं। उन्हें भूलने की बीमारी है। दिक्कत उनसे नहीं उन लोगों के आचरण से है जो वर्षों सदन में रहे और वह मर्यादा को जानते हैं। वह भी इस सामंती सियासत के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं।

दोनों सदनों की पीठ उतनी निष्पक्ष नहीं थीं, जितनी होनी चाहिए : चिदंबरम

- हंगामे के लिए सरकार पर लगाया अपनी बात से मुकरने का आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद के मानसून सत्र में हंगामे और अशोभनीय दृश्यों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि दोनों सदनों की पीठ उतनी निष्पक्ष नहीं थीं, जितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में अंतिम दिन हंगामा इसलिए शुरू हुआ था, क्योंकि सरकार ने अपनी बात से मुकरते हुए चुपके से विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी।

एक साक्षात्कार में चिदंबरम ने सत्र के दौरान चर्चाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दो व्यक्तियों की सेना वाली भाजपा सरकार के मन में संसद के लिए सम्मान बेहद कम है, अगर दोनों महानुभावों की चली तो वे संसद को ताला लगा देंगे। चिदंबरम ने यह भी कहा कि वह इस बात के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 2024 में भाजपा से मुकाबले के लिए विपक्ष को एकजुट करने की राह में मुश्किलों से धैर्य, आगे की बातचीत और बैठकों के जरिये पार पा लिया जाएगा और चुनावों से काफी पहले यह हकीकत होगी।

सत्र के अंतिम दिन सरकार पर अपनी बात से मुकरने का आरोप लगाते हुए चिदंबरम ने कहा कि ओबीसी पर संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना था, लेकिन फिर भी सरकार ने बीमा संशोधन और कुछ अन्य विधेयक पारित कराने की कोशिश की।

राहुल के फेसबुक व इंस्टाग्राम अकाउंट पर कार्रवाई की मांग

जासं, नई दिल्ली : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के फेसबुक व इंस्टाग्राम अकाउंट पर कार्रवाई की मांग की है। आयोग ने इस संबंध में दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट को पत्र भी लिखा है। इसमें कहा कि राहुल ने अपने फेसबुक व इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो पोस्ट किया है उससे नाबालिग पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर हो रही है। ऐसा कर उन्होंने पाक्सो कानून और जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने कार्रवाई की रिपोर्ट को तीन दिन में जमा करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि एनसीपीसीआर ने चार अगस्त को ट्विटर को पत्र लिखकर राहुल के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद उनके ट्विटर अकाउंट को लाक कर दिया गया था।

ट्विटर के भारत प्रमुख मनीष माहेश्वरी का अमेरिका ट्रांसफर

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर ने अपने भारत प्रमुख मनीष माहेश्वरी का अमेरिका ट्रांसफर कर दिया है। नफरत फैलाने वाले एक कथित अपराध के वीडियो से संबंधित जांच के सिलसिले में उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआइआर भी दर्ज की गई थी।

ट्विटर ने माहेश्वरी के ट्रांसफर का कोई कारण नहीं बताया है। कंपनी का कहना है कि वह सीनियर डायरेक्टर (रिवेन्यू स्ट्रैटजी एंड आपरेशंस) के तौर पर अमेरिका जाएंगे और अपनी नई भूमिका में नए बाजार पर फोकस करेंगे। ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट (जापान एंड एशिया पैसिफिक) यू सासामोटो ने एक ट्वीट में यह जानकारी साझा की। कंपनी ने यह भी नहीं बताया कि माहेश्वरी के अमेरिका ट्रांसफर के बाद भारत में उनका स्थान कौन लेगा। ट्विटर से पहले माहेश्वरी

मनीष माहेश्वरी। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

नेटवर्क18 डिजिटल के सीईओ थे। वह फ्लिपकार्ट और पी एंड जी जैसी कंपनियों में भी काम कर चुके हैं।

बता दें कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुपालन में देरी और हाई प्रोफाइल यूजर्स के ट्वीट्स व अकाउंट्स पर विभिन्न कार्रवाइयों को लेकर ट्विटर को पिछले कई महीनों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

वायुसेना प्रमुख ने मेंटीनेंस कमान कमांडर कांफ्रेंस में भाग लिया

नागपुर, एएनआइ : वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने नागपुर के वायुसेना नगर में मेंटीनेंस कमान कमांडर कांफ्रेंस में भाग लिया। यह कांफ्रेंस 11-12 अगस्त को आयोजित की गई। बेस रिपेयर डिपो, इक्विपमेंट डिपो और मेंटीनेंस कमान के तहत आने वाले अन्य स्टेशनों और इकाइयों के कमांडरों ने यह दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें जारी परियोजनाओं और आगामी वर्ष में मेंटीनेंस कमान के लिए तय लक्ष्यों एवं जवाबदेही की समीक्षा की गई। कमांडरों को संबोधित करते हुए भदौरिया ने वायुसेना के विशाल एवं विभिन्न इन्वेंटरी के कुशल प्रबंधन में मेंटीनेंस कमान की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया।

'आतंकी घटना के लिए भारत को जिम्मेदार बता दुष्प्रचार कर रहा पाक'

- भारत ने पाकिस्तान के आरोपों पर कड़ा विरोध जताया

नई दिल्ली, प्रेट्र : खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नौ चीनी इंजीनियरों समेत 13 लोगों की मौत के मामले में भारत ने पाकिस्तान के आरोपों पर कड़ा विरोध जताया है। कहा है कि पाकिस्तान अपनी करतूतों से अस्थिरता का शिकार है और आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। अब जब उसके पाले-पोसे आतंकी उस पर ही हमले कर रहे हैं तब पाकिस्तान अन्य देशों पर झूठा दोषारोपण कर रहा है।

सिंधु नदी पर बन रही पनबिजली परियोजना पर कार्य कर रहे लोगों को लेकर जा रही बस विस्फोट के बाद खाई में जा गिरी थी जिससे उसमें सवार 13 लोगों की मौत हो गई थी। गुरुवार को इस्लामाबाद में प्रेस कान्फ्रेंस कर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने उक्त घटना को आत्मघाती आतंकी हमला करार दिया। कहा कि भारत और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने साजिश रचकर हमले

अरिंदम बागची। जागरण आर्काइव

को अंजाम दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान के दुष्प्रचार का हिस्सा है। पूरी दुनिया जानती है कि आतंक की धुरी कहां पर है। ऐसे में पाकिस्तान की बातों पर किसी को विश्वास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

'सत्ता पक्ष और विपक्ष मेरी दो आंखें'

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

विपक्ष ने मानसून सत्र में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए सभापति, स्पीकर व उपसभापति की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। इस बारे में नायडू ने कहा कि सदन में विपक्ष और सत्ताधारी बेंच मेरी दो आंखों की तरह हैं और दोनों ही मेरे लिए एक समान हैं। दोनों आंखों से ही एक उचित दृष्टि संभव है। सभापति ने कहा, दोनों पक्षों को बराबर सम्मान दिया जाता है और कई अवसरों पर उन्होंने कहा भी कि सदन को चलाने की सामूहिक जिम्मेदारी दोनों पक्षों की थी। सदन में बढ़ते गंभीर गतिरोध के सवाल पर सभापति ने कहा कि सदन बहस और चर्चा के लिए है। बाहर की राजनीतिक लड़ाई सभा पटल पर नहीं लड़ी जानी चाहिए। सत्र के आखिरी दो दिन हुए घमासान से जुड़े मामले में कार्रवाई के बारे में सभापति ने कहा कि इसका अध्ययन किया जा रहा और जल्द ही उचित फैसला हो जाएगा।

स्कूल खोलने के लिए छात्र पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

मांग

12वीं के छात्र ने याचिका दायर कर की देशभर में स्कूल खोलने की मांग, कहा- स्कूल न जाने से बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा असर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के एक छात्र ने याचिका दाखिल कर देशभर में स्कूल खोले जाने की मांग की है। दिल्ली के रहने वाले अमर प्रेम प्रकाश ने याचिका में कहा है कि कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वे तय समय में अपने यहां स्कूल खोलने और आफलाइन फिजिकल पढ़ाई कराने के बारे में विचार कर निर्णय लें।

अमर प्रेम प्रकाश ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार व सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। उसने कहा है कि केंद्र सरकार, विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल खोलने को लेकर अनिर्णय की स्थिति के चलते उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता) तथा अनुच्छेद 21ए (शिक्षा) के अधिकार की दुहाई देते हुए कहा गया है कि कोर्ट सरकार को आदेश दे कि वे स्कूल खोलने के बारे में समग्रता के साथ शीघ्र निर्णय लें। अमर प्रेम प्रकाश ने कहा है कि वह दिल्ली के एक स्कूल में 12वीं का छात्र है। उसने 20 मार्च, 2020 को रेगुलर स्कूल अटेंड किया था। उसके बाद कोरोना संक्रमण के कारण देशभर में लाकडाउन लग गया और सभी स्कूल बंद हो गए। इसके बाद कक्षाएं आनलाइन शुरू हो गईं। महामारी की स्थिति ठीक होने के बाद दिल्ली में मार्च 2021 में कुछ दिनों के लिए स्कूल खुले थे। उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई और अप्रैल के पहले सप्ताह में स्कूल बंद हो गए।

कहा गया है कि इस बीच जनवरी 2021 से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया और धीरे-धीरे इसने रफ्तार पकड़ ली। जून, जुलाई में धीरे-धीरे लाकडाउन में ढील जी जाने लगी। कोरोना से बचाव के उपायों के साथ स्पोर्ट्स सेंटर और जिम समेत बहुत से सार्वजनिक स्थल खोल दिए गए, लेकिन स्कूल खोलने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। कुछ राज्यों ने अपने यहां स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक स्कूल खोलने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। केंद्रीय विद्यालय भी नहीं खुले हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसका उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता और अन्य बहुत से छात्रों को आनलाइन पढ़ाई में कई दिक्कतें हैं। विशेषतौर से यह उसका स्कूल का अंतिम वर्ष है वह 12वीं का छात्र है। आनलाइन पढ़ाई और आनलाइन टेस्ट बहुत अच्छे और प्रभावी नहीं होते। इसमें ध्यान लगाने और इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत रहती है। यह अच्छा विकल्प नहीं है। इसे सिर्फ थोड़े समय के लिए अपनाया जा सकता है। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसके पास आनलाइन पढ़ाई के साधन नहीं हैं। यह भी कहा है कि जिन राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है, वहां हाईब्रिड मोड में स्कूलिंग होनी चाहिए, जिसमें छात्रों के पास आनलाइन और आफलाइन दोनों का विकल्प रहे।

मद्रास हाई कोर्ट ने जवाबी हलफनामे के लिए केंद्र को दिया और समय

चेन्नई, प्रेट्र : मद्रास हाई कोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र को और 10 दिनों का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी एवं जस्टिस पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने 15 दिनों बाद सुनवाई तय कर दी है।

कर्नाटक के गायक टीएम कृष्णा, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स आफ इंडिया, दि हिंदू के पूर्व संपादक एन. राम और एक वरिष्ठ पत्रकार ने याचिका दायर कर हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियम को संविधान का उल्लंघन और 2000 में पारित मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के खिलाफ बताया है। अन्य चीजों के अलावा याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि केंद्र का नया कानून संविधान के अनुच्छेद 19(एक)(ए) के तहत दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

15 अगस्त के बाद 14 राज्यों के किसान प्रतिनिधि संयुक्त मीटिंग कर बड़े संघर्ष का एलान करेंगे। यह बात भाकियू (राजेवाल) अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कही है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 अगस्त, 2021

उचित समय के भीतर एमएलसी सीटों पर निर्णय राज्यपाल का दायित्व : कोर्ट

अहम मामला ▶ बांबे हाई कोर्ट ने कहा-सीटों को अनिश्चित काल के लिए खाली नहीं रखा जा सकता

राज्य ब्यूरो, मुंबई

बांबे हाई कोर्ट ने कहा है कि विधान परिषद सदस्यों को नामित करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए नामों को उचित समय के भीतर स्वीकार या अस्वीकार करना राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने कहा कि विधान परिषद की सीटों को अनिश्चित काल तक खाली नहीं रखा जा सकता।

हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने यह बात एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कही। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को विधान परिषद में नामित करने के लिए 12 लोगों की सूची भेजे हुए आठ महीने हो चुके हैं।

अदालत ने कहा कि एक कहावत है कि हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। यदि इस कहावत पर विश्वास किया जाए तो इस प्रस्ताव पर अब तक कुछ नहीं कहने का भी कोई कारण हो सकता है। यदि ऐसा है तो राज्यपाल का यह कर्तव्य भी है कि वह मुख्यमंत्री से बात करके उन्हें उन कारणों से अवगत कराएं ताकि विधान परिषद की 12 सीटों के नामांकन पर जल्द फैसला हो सके। विधान परिषद की इन सीटों को अनिश्चित काल तक खाली नहीं रखा जा सकता।

> एक राज्यपाल अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन हम उम्मीद और विश्वास करते हैं कि संवैधानिक दायित्व पूरा हो और चीजें जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।
> -हाई कोर्ट की टिप्पणी

बता दें कि यह जनहित याचिका नासिक निवासी रतन सोली लूथ द्वारा दायर की गई थी। याचिका में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को करीब आठ महीने पहले मंत्रिमंडल द्वारा तय कर विधान परिषद में नामांकन के लिए भेजे गए 12 नामों पर फैसला करने का निर्देश देने की अपील की गई थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते। लेकिन यह भी कहा कि मेरे हिसाब से आठ महीने पर्याप्त समय होता है।

यह जरूरी है कि इस मामले में बिना देरी किए राज्यपाल के दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए। बता दें कि पिछले वर्ष छह नवंबर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों की ओर से चार-चार नाम विधान परिषद में नामित करने के लिए राज्यपाल को भेजे थे। ये नामांकन संविधान की धारा 171(5) के तहत साहित्य, कला, संस्कृति, सहकारिता आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाले लोगों के होने हैं। लेकिन पिछले आठ महीनों से राज्यपाल की ओर से इस सूची पर कोई फैसला नहीं किया गया है, जिसे लेकर कई बार सत्ता पक्ष की ओर से राज्यपाल पर तीखी टिप्पणियां भी की जा चुकी हैं।

पंजाब के उद्योग मंत्री अरोड़ा को लोकपाल का नोटिस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▶ मोहाली में 32 एकड़ जमीन मात्र 90 करोड़ में बेचने के आरोप

▶ पूर्व डिप्टी स्पीकर ने शिकायत की, 12 अक्टूबर तक मांगा जवाब

पूर्व डिप्टी स्पीकर व शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के वरिष्ठ नेता बीर दविंदर सिंह की शिकायत पर पंजाब के लोकपाल जस्टिस विनोद कुमार शर्मा ने उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को नोटिस जारी किया है। उन्हें 12 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है।

बीर दविंदर सिंह ने मोहाली में जेसीटी इलेक्ट्रानिक्स की 32 एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव जीआरजी डेवेलपर्स को 90 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था। इससे सरकारी खजाने को 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जमीन को बेचने के लिए वित्त विभाग से एनओसी नहीं ली गई और न ही एडवोकेट जनरल दफ्तर से पूछा गया। विभाग ने केवल कुछ प्राइवेट वकीलों से ही सलाह ली है। ऐसा मंत्री के कहने पर ही किया गया था। पूर्व डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ऐसा उस समय किया गया, जब कोरोना के कारण पंजाब में कर्फ्यू लागू था और कोई भी आधिकारिक गतिविधि

सुंदर शाम अरोड़ा फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

नहीं हो रही थी। जब राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर यह मुद्दा उठाया तो सरकार ने एडवोकेट जनरल से इसके बारे में राय मांगी और एडवोकेट जनरल ने भी कहा कि डील गलत हुई है और इससे खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। लोकपाल ने मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा व पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन के डायरेक्टर और सीजीएम एसपी सिंह को 12 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया है।

अब खुद सरकार हैं सिद्धू, वादे पूरे करें : चड्ढा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब मामलों के सह प्रभारी और दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पत्र लिखकर 2017 में कांग्रेस द्वारा किए गए सभी चुनावी वादों को तुरंत पूरा करने की मांग की है। उन्होंने पत्र के साथ 2017 में कांग्रेस का 129 पन्नों का चुनावी घोषणा पत्र भी भेजा और कहा कि कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है। सिद्धू को बधाई देते हुए राघव चड्ढा ने कहा, 'सीट और सत्ता के लिए लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत की बधाई। हाईकमान आपके साथ है। आपको कांग्रेस के सभी विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अब आप कांग्रेस हैं और आप पंजाब सरकार भी हैं। इसलिए, 2017 में कांग्रेस के सभी 129 अधूरे चुनावी वादों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है।' चड्ढा ने कहा कि सिद्धू को अब विपक्ष के नेता के रूप में काम करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि सिद्धू न केवल सत्तारूढ़ कांग्रेस का हिस्सा हैं बल्कि अब वह अध्यक्ष भी हैं और पूरी राज्य सरकार उनके अधीन है। सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, सिद्धू को अगले चुनाव से पहले अपने सभी वादों को पूरा करना होगा, क्योंकि कांग्रेस साढ़े चार साल में अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है।

अब सुवेंदु अधिकारी के भाई को केंद्र ने दी जेड श्रेणी की सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : केंद्र सरकार ने बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी के छोटे भाई सौमेंदु अधिकारी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने को मंजूरी दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान सौमेंदु अधिकारी की कार पर हमला किया गया था। सौमेंदु भी इसी साल जनवरी में भाजपा में शामिल हुए थे।

बंगाल में सौमेंदु के अलावा ग्रेटर कूचबिहार पीपल्स एसोसिएशन (जीसीपीए) के नेता अनंत महाराज को भी वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। महाराज की राजवंशी समुदाय में खासी लोकप्रियता है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों नेताओं को सशस्त्र वीआइपी सुरक्षा कवर को मंजूरी दी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को दोनों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने को कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सिफारिश की गई थी कि उन दोनों नेताओं को उचित सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए उन्हें सुरक्षा कवर मुहैया कराया गया।

उल्लेखनीय है कि सुवेंदु को 'जेड प्लस' श्रेणी की सुरक्षा पहले से प्राप्त है और उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के 20-22 कमांडो लगे रहते हैं।

दरवाजा तोड़कर भाजपा नेता को कोलकाता पुलिस ने किया गिरफ्तार

दबंगई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▶ सजल का दावा बिना अपराध के हुई गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद घसीटकर थाने तक ले गई पुलिस

तोड़फोड़ के आरोप में एक भाजपा नेता को गिरफ्तार करने गई कोलकाता पुलिस का शुक्रवार को दबंग रूप देखने को मिला। मोचीपाड़ा थाने के प्रभारी ने मध्य कोलकाता के एक मकान में घुसकर कथित तौर पर अपने पैर से दरवाजा तोड़कर भाजपा नेता सजल घोष को गिरफ्तार किया। यही नहीं आरोप है कि भाजपा नेता को गिरफ्तार करने के बाद घसीटकर थाने ले जाया गया।

वीडियो फुटेज में थानेदार की यह दबंगई साफ देखी जा सकती है। भाजपा नेता की गिरफ्तारी के दौरान इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। घटना के बाद सजल के पिता प्रदीप घोष समेत परिवार के लोग घर पर ही थे। वहीं, सजल घोष ने दावा किया कि बिना अपराध के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। सजल के पिता ने भी कहा कि सजल को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन के साथ धरना भी दिया। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि सजल व उनके साथियों ने पार्टी के एक स्थानीय युवा नेता की पत्नी से भी छेड़छाड़ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सजल और उनके साथियों के खिलाफ तोड़फोड़ और छेड़खानी के दो अलग-अलग आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, सजल और भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है।

आतंकवादी की तरह किया गिरफ्तार : दिलीप घोष

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी नेता सजल घोष की गिरफ्तारी पर कहा कि उनके दल के नेता को पुलिस ने आतंकवादियों की तरह दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया। कोलकाता के हर वार्ड में आतंकवादी छुपे हैं, उन्हें पकड़ने की हिम्मत पुलिस में नहीं है और घर का दरवाजा तोड़कर आतंकवादी की तरह सजल घोष को पकड़ा गया। पंजाब, मणिपुर, असम से आतंकवादी कोलकाता आकर छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पकड़कर भाजपा नेता को पकड़ा जा रहा है। ये कैसी कानून-व्यवस्था है। हम पूरी तरह सजल के साथ हैं।

सरकारी अधिकारियों के देरी से अपील करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : समयसीमा की परवाह किए बिना सरकारी अधिकारियों द्वारा देर से अदालत आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा, अगर सरकार को लगता है कि यह समयसीमा बेहद अपर्याप्त है तो वह अपील दायर करने की समयसीमा बढ़ाने के लिए विधायिका से संपर्क कर सकती है। केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जुलाई, 2017 के आदेश के खिलाफ 1,356 दिनों की देरी से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश राय की पीठ ने याचिका को समयबद्ध बताते हुए खारिज कर दिया और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। पीठ ने कहा, उन्होंने ऐसे मामलों को प्रमाणपत्र केसों के रूप में वर्गीकृत किया है जो खारिज होने का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए ही शीर्ष अदालत में लाए जाते हैं ताकि दोषी अधिकारियों को बचाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ट्रिब्यूनलों के आदेशों पर वाटरमार्क उन्हें अपठनीय बना देते हैं। एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की ई-कमेटी ट्रिब्यूनलों से संपर्क करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेशों पर ऐसे लोगो का इस्तेमाल न किया जाए।

तृणमूल के मुकुल राय ने फिर कहा- बंगाल उपचुनाव में भाजपा की होगी जीत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीतने के कुछ दिन बाद ही तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले मुकुल राय ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सीट पर अगर उपचुनाव होता है तो भाजपा की ही जीत होगी। एक हफ्ते में दूसरी बार राय ने ऐसा कहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2023 में होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तापस राय ने मुकुल के बयान पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया, जबकि भाजपा ने कहा कि जनता ऐसे बयानों पर फैसला करेगी।

गौरतलब है कि मुकुल ने गत छह अगस्त को नदिया जिले के कृष्णानगर में संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि भाजपा राज्य में होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। हालांकि, जैसे ही उन्हें गलती का अहसास हुआ, उन्होंने भूल सुधार करते हुए कहा कि उनका अभिप्राय तृणमूल से था। तृणमूल जीत दर्ज करेगी। अब शुक्रवार को विधानसभा परिसर में लोकलेखा समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से मुकुलने कहा कि अगर कृष्णानगर उत्तर सीट पर उपचुनाव होते हैं तो भाजपा जीतेगी। मुकुल से जब पूछा गया कि वह किस पार्टी के विधायक हैं तो उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का विधायक हूं।

गौरतलब है कि मुकुल 2017 में तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन पिछले दिनों दो मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब एक महीने बाद वह तृणमूल में वापस शामिल हो गए थे। हालांकि, आधिकारिक रूप से वह अब भी कृष्णानगर उत्तर सीट से भाजपा के विधायक हैं और उन्हें विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

सुवेंदु बोले-जनता करेगी आकलन

भाजपा विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा के टिकट पर जीतकर मुकुल तृणमूल कार्यालय गए तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। अब अगर वह ऐसे बयान दे रहें हैं तो यह लोगों पर है कि वह उनका कैसे आकलन करते हैं। राज्य सरकार ने उन्हें भारी सुरक्षा मुहैया कराई है। उन्हें लोकलेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है।

त्रिपुरा में वामपंथियों के साथ गठबंधन नहीं करेगी तृणमूल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: माकपा भले ही अपनी धुर विरोधी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से बंगाल के बाहर हाथ मिलने के संकेत दे रही हो पर टीएमसी इसके लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि बंगाल के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले ब्रात्य बसु ने शुक्रवार को कहा कि त्रिपुरा में वामपंथियों के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा में तीसरी बार जीत से उत्साहित टीएमसी की नजर अब त्रिपुरा पर है। वहां भाजपा को शिकस्त देने के लिए टीएमसी जोर लगा रही है। भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए गठबंधन की अटकलों के बीच बासु ने कहा कि बंगाल की वामपंथी पार्टियों के नेताओं और त्रिपुरा के वामपंथी नेताओं में काफी अंतर है, बावजूद इसके उनके साथ किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा।

अभियानों के जरिये कार्यकर्ताओं का दमखम परख रही कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ जनता में पैठ बढ़ाने के साथ दमदार उम्मीदवारों की पहचान भी कर रही पार्टी

▶ सक्रियता और जनता से जुड़ाव की कसौटी पर परखे जा रहे नेता व कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश में खोया जनाधार वापस पाने के लिए संघर्षरत कांग्रेस पार्टी अपने अभियानों के जरिये एक तीर से दो निशाने साधना चाहती है। पार्टी की ओर से चलाये जा रहे अभियानों का मकसद लोगों के बीच अपनी पैठ बढ़ाना तो है ही, इसका उद्देश्य विधानसभा चुनाव के लिए दमदार उम्मीदवारों की पहचान करना भी है।

हाल ही में कांग्रेस की ओर से चलाये गए 'भाजपा गद्दी छोड़ो' अभियान को भी इसी नजरिये से देखा गया। उप्र में तीन दशक से ज्यादा समय से सियासी वनवास भोग रही कांग्रेस की हालत के लिए पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता और अन्यमनस्कता को भी जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। लिहाजा पार्टी इन अभियानों के जरिये अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आमजन के बीच सक्रिय करने के साथ उन्हें संगठन में सक्रियता, पब्लिक कनेक्ट और चुनाव लड़ने के दमखम की कसौटी पर भी परख रही है। पार्टी ने 'भाजपा गद्दी छोड़ो' अभियान से पहले यह कहते हुए इसका संदेश भी दे दिया था कि इस अभियान में पूर्व विधायकों व सांसदों और कार्यकर्ताओं की अनिवार्य भूमिका की भी समीक्षा होगी। इससे पहले हुए ब्लाक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यह साफ कर दिया था कि पार्टी के अभियानों और कार्यक्रमों में सक्रियता और जनता से जुड़ाव भी विधानसभा चुनाव के टिकट देने का पैमाना होगा। कांग्रेस की एक कमजोरी यह भी मानी जाती रही है कि उसके पास सभी विधानसभा क्षेत्रों में उतारने के लिए मजबूत प्रत्याशियों का अभाव है। भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान को विधानसभा क्षेत्रों में चलाकर पार्टी ने इसके माध्यम से संभावित प्रत्याशियों को चिन्हित करने की कोशिश भी की है। पार्टी की ओर से 19 से 21 अगस्त तक चलाये जाने वाले जय भारत महासंपर्क अभियान के दौरान भी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता और दमखम पर नजर रहेगी।

जातिगत जनगणना के लिए राजद ने बढ़ाया राजग पर दबाव

राज्य ब्यूरो, पटना

▶ प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किया जातिगत जनगणना कराने का आग्रह

▶ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 27 फीसद करने की मांग

जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजद ने भाजपा-जदयू पर दबाव बढ़ा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने के नौ दिन बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी पत्र लिखकर केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग की है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री द्वारा नीतीश कुमार को अभी तक मिलने का समय नहीं देने को अपमान से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान बंगाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन बिहार को अभी तक समय देना जरूरी नहीं समझा गया।

अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव और अशोक कुमार सिंह के साथ शुक्रवार को राजद कार्यालय पहुंचे तेजस्वी मीडिया से बात कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री को अगर समय नहीं मिलता है तो जातिगत जनगणना के समर्थक सभी दल दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना दें या राज्य सरकार अपने स्तर से जातिगत जनगणना कराए। तेजस्वी ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसद आरक्षण को बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि पिछड़ी जातियों का दायरा जब बढ़ाया जा रहा है तो आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई जाए। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने चार अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मिलने के लिए समय मांगा था, जो अभी तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री को इसे समझना चाहिए कि विलंब क्यों हो रहा है। कहीं न कहीं यह उनका अपमान है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बिहार के मुख्यमंत्री को समय नहीं दिया जा रहा है। विधानसभा से सर्वसम्मति से दो-दो बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है।

राजद कार्यालय से दूर रहे जगदानंद सिंह

तेजप्रताप यादव के बयान से आहत जगदानंद सिंह ने छठे दिन भी राजद कार्यालय से दूर रहे। इससे संबंधित मीडिया के सवालों पर भी तेजस्वी ने चुप्पी साध ली। उन्होंने दोनों के बीच किसी तरह के मतभेद से इन्कार किया और इतना ही कहा कि उनकी जानकारी में नहीं हैं। राजद में सब एक हैं।

जातिगत जनगणना की मांग का मतलब जातपात नहीं

तेजस्वी ने सफाई भी दी। कहा कि जातिगत जनगणना हमारी पुरानी मांग है। इसका मतलब यह नहीं कि हम जातपात करते हैं। पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक विकास की बातें नहीं हो सकती हैं। इसलिए किस जाति की कितनी आबादी है, गिना जाए और उसे पब्लिक डोमेन में डाला जाए। बैकलाग के पदों को भी भरा जाए। ये लगभग 50 फीसद खाली हैं।

केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्राएं 16 से शुरू होंगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले प्रदेश के सात सांसद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जनता का आशीष हासिल करने के लिए प्रदेश के अलग-अलग जगहों से जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेंगे। जन आशीर्वाद यात्राओं की शुरुआत 16 अगस्त से और समापन 20 अगस्त को होगा। इन यात्राओं के जरिये केंद्रीय मंत्री परोक्ष रूप से यह संदेश भी देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्र सरकार में उन्हें मंत्री का ओहदा देकर उनकी बिरादरी को महत्व देने के साथ उसका सम्मान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में प्रदेश के अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के तीन-तीन और एक ब्राह्मण सांसद को राज्य मंत्री बनाया गया है।

केंद्रीय मंत्रियों को जनता का आशीर्वाद दिलाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश पर जन आशीर्वाद यात्रा की व्यापक योजना बनाई गई है। जन आशीर्वाद यात्राएं प्रदेश के लगभग तीन दर्जन लोकसभा और 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए साढ़े तीन हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगी। यात्रा के दौरान जगह-जगह स्वागत सभाएं होंगी। कई जगहों पर जनसभाएं भी होंगी।

केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा की जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त को वृंदावन-मथुरा से प्रारंभ होगी। यात्रा मथुरा जिले व महानगर की कुछ विधानसभाओं से होते हुए आगरा जिले व महानगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व बुलंदशहर होते हुए 19 को बदायूं में समाप्त होगी। एसपी सिंह बघेल की यात्रा 16 को मध्यप्रदेश के दतिया, ग्वालियर, 17 को राजस्थान के धौलपुर, 18 से 20 तक प्रदेश के फीरोजाबाद, मथुरा और आगरा में निकलेगी। भानु प्रताप वर्मा जनता का आशीर्वाद लेने के लिए 17 को ललितपुर से यात्रा प्रारंभ करेंगे। उनकी यात्रा झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट होते हुए 19 को फतेहपुर में समाप्त होगी।

कौशल किशोर 16 की सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसी दिन मोहान, उन्नाव से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए 18 को सीतापुर में समाप्त होगी।

बदलाव

> भाजपा के 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' के जवाब में कांग्रेस ने कहा-'हमें तुमसे प्यार कितना, ये सब जानते हैं', भाजपा की ओर से पलटवार- 'कांग्रेस में आ देखें जरा, किसमें- कितना है दम...' वाली स्थिति

मप्र की राजनीति में फिल्मी गीतों के जरिये लगाए जा रहे दांव-पेच

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप नई बात नहीं है, लेकिन इन दिनों अंदाज में रोचक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक पार्टी में 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...' गीत क्या गाया, गीतों के माध्यम से वार-पलटवार की शुरुआत भी हो गई। कांग्रेस की ओर से 'वफा-बेवफाई' के गीतों से पलटवार किया गया। अब अपनी बात कहने के लिए मौके के अनुसार भूले-बिसरे गीत तलाशे जा रहे हैं। फिल्म शोले के पात्रों के हिसाब से भी किरदारों पर तंज कसे जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया इसका माध्यम बना हुआ है।

गत बुधवार को शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय का एक-दूसरे का हाथ थामकर फिल्म शोले का गीत 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...' गाते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। इसी वीडियो को अपलोड करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव (मीडिया) केके मिश्रा ने ट्वीट किया 'चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों...'। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने लिखा 'हमें तुमसे प्यार कितना, ये सब जानते हैं। क्या-क्या जतन करते हैं, ये सबको पता है।...' इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने फिल्म शोले के किरदारों के हिसाब से भाजपा नेताओं को भूमिका दी और इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि नए जय-वीरू की जोड़ी। पुराने वीरू अब ठाकुर बन गए...। देखना है गब्बर सिंह के निशाने पर कौन रहता है। जेलर कहेंगे आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे, लेकिन पीछे कोई नहीं दिखेगा।

भोपाल : भुट्टा पार्टी में 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...' गीत गाते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। नईदुनिया

भाजपा की ओर से भी उसी अंदाज में आया जवाब

कांग्रेस नेताओं के ट्वीट के जवाब में भाजपा की ओर से भी उसी शैली में जवाब दिया गया है। भाजपा नेता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि हम भाजपा के लोग गा रहे हैं कि 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...' तो कांग्रेस के नेताओं का राग है 'आ देखें जरा किसमें-कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया...' क्योंकि पीछे से कांग्रेस के दूसरे कबीले का आदमी धक्का देने वाला है। भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने जवाब दिया कि 'दोस्त-दोस्त ना रहा, प्यार-प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा...' गाने वाली कांग्रेस हताशा-निराशा और कुंठा से भर गई है। इसलिए सच्ची दोस्ती ये देख नहीं सकते।

जगदानंद-तेजप्रताप के मुद्दे पर तेजस्वी ने साधी चुप्पी

राज्य ब्यूरो, पटना

राजद विधायक तेजप्रताप यादव के बयान से आहत पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह छठे दिन भी कार्यालय से दूर रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बीच-बचाव की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने मीडिया के सवाल लेने से भी बचने की कोशिश की। सवालों की झड़ी के बीच उन्होंने दोनों में किसी तरह के विवाद से इन्कार किया। इतना ही कहा कि उनकी जानकारी में नहीं हैं। राजद में सब एक हैं।

जगदानंद को तेजस्वी का घोर समर्थक माना जाता है। उनके ही आग्रह पर जगदानंद ने 2019 में प्रदेश राजद की कमान संभाली थी। पटना में रहने के दौरान दोनों को प्रत्येक कार्यक्रम और प्रेस वार्ता में एक साथ देखा जाता था। किंतु राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा पहली बार देखा गया जब जगदानंद के बिना तेजस्वी राजद कार्यालय पहुंचे और मीडिया को संबोधित किया। इसका साफ मतलब है कि पार्टी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजप्रताप के बयान से जगदानंद की भावना को धक्का पहुंचा है। विवाद से संबंधित मीडिया के सवालों पर तेजस्वी ने बचते हुए कहा कि प्रेस वार्ता जातीय जनगणना पर बुलाई गई है। सवाल का फोकस उसी पर रखिए। फिर भी जब लगातार सवाल आने लगे तो तेजस्वी असहज हो गए और बीच में ही वार्ता को खत्म कर चले गए।

तेजस्वी यादव। जागरण आर्काइव

15 अगस्त से उत्तराखंड के पांच पर्वतीय जिलों के लिए मोबाइल ई कोर्ट की शुरुआत होगी। दूसरे चरण में शेष आठ जिलों को भी जोड़ लिया जाएगा। इन अदालतों में महिला व बच्चों को गवाही दर्ज कराने में प्राथमिकता दी जाएगा।

न्यूज गैलरी

जेपी नड्डा के पिता को दिल्ली एम्स में ले जाया गया

बिलासपुर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के पिता प्रो. नारायण लाल नड्डा को शुक्रवार को स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया। नड्डा के पिता तीन दिन से बीमार थे तथा उनका इलाज यहां एक निजी अस्पताल में चल रहा था। नारायण लाल नड्डा को पेट में दर्द होने के कारण अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। इसके बाद शुक्रवार को तीन बजे स्वास्थ्य सुधार के लिए उन्हें दिल्ली एम्स में ले जाया गया है। उन्हें बिलासपुर से सड़क के माध्यम से एंबुलेंस में चंडीगढ़ ले गए जहां से उन्हें हेलीकाप्टर से दिल्ली ले जाया जाएगा। हालांकि जेपी नड्डा अपने पिता को दिल्ली ले जाने के लिए स्वयं आने वाले थे, लेकिन अति व्यस्तता के कारण वह नहीं पहुंच सके। उनके स्टाफ के सदस्य उनके पिता को दिल्ली ले गए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुदेश ठाकुर ने यह जानकारी दी। (जासं)

परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस

मुंबई : मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली के एक मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने कहा, 'परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है।' 23 जुलाई को परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे सिटी पुलिस कमिशनरेट के कोपरी थाने में जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था। जबरन वसूली का यह दूसरा ऐसा मामला है जिसमें परमबीर सिंह नामजद किए गए हैं। 28 जुलाई को मुंबई पुलिस ने पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी की अगुआई में सात सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया था। यह टीम मामले में नामजद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त एवं पांच अन्य के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए गठित की गई है। (एएनआइ)

छग में स्वतंत्रता दिवस पर काले झंडे नहीं फहरा पाएंगे नक्सली

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगे की जगह काला झंडा फहराने वाले नक्सलियों को इस बार यह मौका नहीं मिलने वाला है। नक्सलियों की करतूत को रोकने फोर्स ने खास तैयारी की है। इस बार जवान जंगल में लगातार गश्त कर रहे हैं। 14 अगस्त की रात जवान नक्सलगढ़ के जंगलों में गुजारेंगे। अगले दिन सुबह 15 अगस्त को वह उन गांवों में जाएंगे, जो कभी नक्सलियों के प्रभाव में थे। जवान ग्रामीणों के साथ मिलकर तिरंगा फहराएंगे, सलामी देंगे। (नईदुनिया)

साजिश नाकाम : कश्मीर में 20 घंटे चली मुठभेड़, पाकिस्तानी आतंकी ढेर

काजीगुंड मुठभेड़ ▶ आतंकी से आरपीजी और राकेट लांचर बरामद, बड़े हमले की थी तैयारी

सुरक्षाबलों ने इमारत में और आसपास के इलाकों में फंसे 22 नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलगाम जिले के काजीगुंड में करीब 20 घंटे चली मुठभेड़ शुक्रवार सुबह पाकिस्तानी आतंकी उस्मान की मौत के साथ खत्म हो गई। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस से पूर्व कश्मीर में पुलवामा कांड दोहराने की आतंकी साजिश भी नाकाम हो गई। मारे गए आतंकी के इरादों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मुठभेड़ के दौरान उसने पुलिस के दो ड्रोन भी उड़ा दिए। उसके पास राकेट प्रोपेल्ड गन (आरपीजी) और राकेट लांचर भी बरामद किए। अगर आतंकी ने आरपीजी बीएसएफ काफिले पर दागा होता या मुठभेड़ के दौरान इस्तेमाल कर लिया होता तो बड़ा नुकसान होता। मुठभेड़ के दौरान बच निकले दूसरे आतंकी को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाना बनी इमारत और आसपास के इलाकों में फंसे 22 नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला। इनमें 12 दुकानदार, छह महिलाएं और चार अन्य राज्यों के श्रमिक हैं।

गुरुवार दोपहर बाद मलपोरा (काजीगुंड) में दो आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में बीएसएफ जवान बाल-बाल बच गए थे। सीआरपीएफ जवानों ने त्वरित कार्रवाई की। वहां से भागे आतंकियों ने निकटवर्ती इमारत में शरण ले ली थी। सुरक्षाबलों ने तुरंत इमारत को घेर लिया। उसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। गुरुवार रात तक दो सुरक्षाकर्मी और दो नागरिक गोली लगने से जख्मी हुए थे। पुलिस महानिरीक्षक (आइजीपी) कश्मीर विजय कुमार और सेना की विक्टर फोर्स के जीओसी मेजर जनरल रशिम बाली खुद मौके पर अभियान की लगातार निगरानी कर रहे थे।

आतंकी ठिकाना बनी इमारत को उड़ाने के लिए सुरक्षाबलों ने भी राकेट लांचर दागा था। इससे इमारत का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। सुबह करीब साढ़े सात बजे आतंकियों की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। इस पर जवानों ने इमारत में तलाशी ली तो गोलियों से छलनी एक आतंकी का शव और हथियार मिले। माना जा रहा है कि दूसरा आतंकी भाग निकला था। समझा जा रहा है कि एक आतंकी ने सुरक्षाबलों को मुठभेड़ में उलझाते हुए दूसरे साथी को भागने का अवसर दिया होगा।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मोर्चा संभालते सुरक्षा बल। प्रेट्र

> हमने स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम बनाया है। मारा गया आतंकी पाकिस्तान का उस्मान छह माह से कश्मीर में सक्रिय था। वह बीते दिनों त्राल में मारे गए जैश कमांडर लंबू का भी करीबी था।
> – विजय कुमार, आइजीपी कश्मीर

बीएसएफ काफिले में 500 से अधिक जवान और अधिकारी थे

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकी बीएसएफ काफिले पर आरपीजी का इस्तेमाल करते तो 14 फरवरी, 2019 से पुलवामा हमले से बड़ा हमला होता। बीएसएफ का जो काफिला गुरुवार को आ रहा था, उसमें करीब 507 जवान व अधिकारी शामिल थे।

आधुनिक हथियारों से सरहद पर ही ड्रोनों को मार गिराएगी सेना

राज्य ब्यूरो, जम्मू

1800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन को मारने में सक्षम हुई भारतीय सेना

अगर पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तो सुरक्षाबल उसे सीमा पर ही मार गिराएंगे। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की ड्रोन साजिश से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम तो लगाए ही हैं, अब ऐसे आधुनिक विदेशी हथियारों को भी शामिल किया गया है जो आसमान में डेढ़ किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम हैं।

स्वतंत्रता समारोह में खलल डालने के लिए आतंकी हर साजिश रच रहे हैं। गत जून में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से बम धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों को नए सिरे से सुरक्षा तैयारियां की हैं। जम्मू संभाग में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक आए दिन ड्रोनों की घुसपैठ के मामले सामने आ रहे हैं। इससे निपटने के लिए सेना ने जम्मू से लेकर पुंछ तक निगरानी के स्तर को और बेहतर बनाया है। जम्मू के अखनूर के सीमावर्ती प्लांवाला सेक्टर में सेना की क्रास्ड स्वार्ड्स डिवीजन के बेड़े में ऐसे आधुनिक हथियार शामिल किए गए हैं, जिनसे पाकिस्तानी ड्रोनों का बच पाना संभव नहीं है। पाकिस्तान के ड्रोनों को मार गिराने के लिए भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर अमेरिका की नाइट विजन एवं बड़ी टेलीस्कोप से लैस स्नाइपर गन तैयार रखी हैं। यह गन 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक ड्रोन पर एक साथ पांच गोलियां दागने में सक्षम है। इससे ड्रोन का बच पाना नामुमकिन है। इसके साथ ही एक साथ 200 गोलियां दागने वाली मशीनगन और एक साथ ड्रोन पर फायरिंग करने में सक्षम तीन असाल्ट राइफलयुक्त प्रणाली भी बेड़े में शामिल की गई है।

फेंसिंग पर हाई डेफिनेशन के कैमरे से दुश्मन की हर गतिविधि पर दिन रात नजर रखी जा रही है। सेना ने नियंत्रण रेखा के पास इलाकों में अतिरिक्त नाके लगाए हैं।

पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराने के लिए जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना ने सरहद पर एंटी ड्रोन हथियार तैनात कर रखे हैं। सौ. पीआरओ डिफेंस

पुंछ को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम, चार आइईडी पकड़ी

जासं, पुंछ : स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी साजिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया। मेंढर में चार इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईइडी) के साथ एक आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया। पुलिस, सेना व सुरक्षा एजेंसियां आतंकी मददगार से पूछताछ कर रही हैं।

सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि आतंकी पुंछ जिले में बड़ी वारदात करने की फिराक में हैं। इसे नाकाम करने के लिए कई स्थानों पर नाके लगाकर आने-जाने वालों पर नजर रखी जाने लगी। कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाए गए। सेना, पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की 72वीं बटालियन के जवानों का मेंढर के कोटन में संयुक्त नाका लगा था। दोपहर को महमूद हुसैन निवासी कस्सबलाड़ी, मेंढर जब वहां से गुजर रहा था तो सुरक्षाबलों को उस पर शक हुआ। तलाशी के दौरान उससे चार आईइडी और 10,500 रुपये नकद बरामद किए।

भाजपा नेता की हत्या के गम व गुस्से से सुलगता रहा राजौरी

जागरण संवाददाता, राजौरी

ग्रेनेड हमला

- लोगों ने राजौरी शहर बंद रखकर, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया
- आतंकियों ने भाजपा के शहरी मंडल अध्यक्ष के घर किया था ग्रेनेड हमला
- तीन साल के बच्चे की मौत व परिवार के छह सदस्य हो गए थे घायल

भाजपा के शहरी मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के अगले दिन शुक्रवार को राजौरी गम और गुस्से से सुलगता रहा। जिले का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो, जहां लोगों ने इस हमले के विरोध में प्रदर्शन न किया हो। राजौरी शहर भी पूरा बंद रहा और लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए हमलावर आतंकियों को पकड़ने की मांग की। इस बीच, जसवीर सिंह की मां की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें से राजकीय मेडिकल कालेज (जीएमसी) अस्पताल जम्मू रेफर कर दिया गया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी राजौरी पहुंचे और जसवीर के परिवार के सदस्यों से मिलकर संवेदना प्रकट की। उन्होंने राजौरी अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। वहीं, डिवकाम जम्मू राघव लंगर व आइजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह भी राजौरी पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। दोनों अधिकारी जसवीर सिंह के घर गए और परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस बीच, खांडली पुल क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया।

बता दें कि आतंकियों ने गत गुरुवार रात राजौरी नगर के खांडली पुल क्षेत्र में भाजपा के शहरी मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह के घर पर छत पर चढ़कर आंगन में बैठे परिवार के सदस्यों पर ग्रेनेड फेंका था। इस हमले में जसवीर सिंह के तीन वर्षीय भतीजे की मौत हो गई थी, जबकि खुद जसवीर, उनके माता-पिता, भाई और दो भतीजों समेत परिवार के छह सदस्य बुरी तरह घायल हो गए थे।

पुलिस की घेराबंदी तोड़ आगे बढ़ गए प्रदर्शनकारी : प्रदर्शनकारी पंजा चौक की तरफ बढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोग पुलिस की घेराबंदी तोड़कर पाकिस्तान व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। प्रदर्शनकारी पंजा चौक पर पहुंच गए और वहां पर फिर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदर्शन कर रहे नवल गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता, नवीन महाजन आदि ने कहा कि पहले भी यहां इस तरह की कई वारदात हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी मामले को हल नहीं किया है।

एसएसपी शीमर नबी, जिला आयुक्त राजेश कुमार शवन पंजा चौक में पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि हमले में शामिल तत्वों को जल्द बेनकाब किया जाएगा। इसके साथ सुरक्षा को और पुख्ता किया जाएगा। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया।

राजौरी में भाजपा के शहरी मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के विरोध में शुक्रवार को पंजाचौक में पाकिस्तान व प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग। जागरण

> पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने यह कायराना हरकत की है। इस हमले में तीन वर्ष का बच्चा मारा गया है, जिसने अभी ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं। इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी जसवीर सिंह व उनके परिवार के साथ खड़ी है।
> –रविंद्र रैना, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष

> हमारा अभियान जारी है। आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे जवान व अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
> –विवेक गुप्ता, डीआइजी, राजौरी-पुंछ रेंज

मेरे पोते के कातिल आतंकियों को फांसी मिले

जसवीर सिंह के पिता रमेश सिंह ने कहा कि यह हमला सुरक्षा में ढील का नतीजा है। उन्होंने कहा कि चौक पर काफी संख्या में पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहते है, फिर भी आतंकी ग्रेनेड दागकर भाग निकले। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के कुछ लोग भी आतंकियों के साथ मिले हो सकते हैं। पुलिस जल्द कार्रवाई करे और मेरे पोते के कातिलों को फांसी मिले।

सहारनपुर में फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने की एसटीएफ करेगी जांच

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सहारनपुर में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में घुसपैठ कर फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने की जांच स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) करेगी। अगले वर्ष यूपी सहित पांच राज्यों में चुनाव होने हैं और उससे पहले वेबसाइट में घुसपैठ के इस मामले को बेहद गंभीर माना जा रहा है। इसके तार कई राज्यों से जुड़े होने के कारण सहारनपुर के जिलाधिकारी ने इसकी जांच किसी विशेषज्ञ एजेंसी से कराने के लिए गोपनीय पत्र चुनाव आयोग को लिखा था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी शुक्रवार को इस पत्र को गृह विभाग भेजकर विशेषज्ञ एजेंसी से जांच कराने के लिए कहा था। पत्र मिलने के कुछ घंटे बाद ही राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसकी पुष्टि की है।

सहारनपुर की इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इस तरह फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाए जाने का गैंग सक्रिय होने की आशंका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि सहारनपुर मामले की जांच हो रही है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच में ही यह साफ हो सकेगा कि इन लोगों ने किस तरह से चुनाव आयोग के डाटा बेस तक अपनी पहुंच बनाई है।

सहारनपुर में पकड़े गए विपुल सैनी ने 10 हजार से अधिक मतदाता पहचान पत्र बनाए हैं। उसने वेबसाइट में सेंधमारी कर वह पीडीएफ प्राप्त कर लिया, जिससे मतदाता पहचान पत्र प्रिंट होते हैं। चुनाव आयोग यह पीडीएफ अपने वेंडर को ही मतदाता पहचान पत्र प्रिंट करने के लिए देता है।

आयोग यह भी देख रहा है कि इस मामले में उसके यहां के किसी कर्मचारी व अधिकारी की मिलीभगत तो नहीं है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र बनाने वाले ईआरओ-नेट साफ्टवेयर में यदि कोई कमी है तो उसे भी जल्द दूर किया जाएगा।

विपुल को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस

जागरण संवाददाता, सहारनपुर : चुनाव आयोग की वेबसाइट में घुसपैठ करने के आरोपित सहारनपुर निवासी विपुल सैनी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए जल्द ही पुलिस कोर्ट में प्रार्थना पत्र देगी। उधर, चर्चा यह भी रही कि विपुल के साथी अरमान मलिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कहीं से भी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट से छेड़छाड़ मामले में बुधवार को सहारनपुर के गांव माच्छरहेड़ी निवासी विपुल सैनी को गरफ्तार किया था। गुरुवार शाम उसे अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस अभी विपुल से पूछताछ नहीं कर सकी है। अरमान मलिक से मिलकर उसने क्या कुछ किया, उसके एकाउंट में 60 लाख रुपये कहां से आए, आखिर वह वोटर कार्ड क्यों, कैसे और किसके लिए बना रहा था, यह सब पता लगाना बाकी है। सूत्रों के अनुसार इस बीच विपुल के कंप्यूटर डाटा से सामने आया है कि वेबसाइट से छेड़छाड़ कर लगभग 10 हजार वोटर आइडी कार्ड बनाए गए हैं।

प्रेमिका ने फौजी से तोहफे में मांगे बच्चों के हाथ

जागरण संवाददाता, मेरठ : पति-पत्नी और वो के मामले में बच्चे दांव पर लग गए हैं। प्रेमिका ने फौजी को मैसेज भेजकर तोहफे में बच्चों के हाथ मांगे हैं। यह बात जब पत्नी को पता चली तो उसने एसएसपी कार्यालय में शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि चार दिन से अनजान लोग उसके घर पर पत्थर भी फेंक रहे हैं।

मेरठ की हरिनगर निवासी संतोष सोम ने बताया कि करीब दो साल पहले उनके पति राजीव की तैनाती देहरादून में थी। वहां किसी महिला से उसके संबंध हो गए। इसकी जानकारी जब उसे हुई तो विरोध किया। इसके बाद उसने घर आना बंद कर दिया। कुछ समय पहले पति की तैनाती गोवा हो गई। एक माह पहले वह छुट्टी पर आये तो उसने पति का मोबाइल फोन चेक किया। उसमें देहरादून निवासी महिला ने मैसेज भेजकर उसके दोनों बेटों के हाथ गिफ्ट में मांगे थे। संतोष सोम के अनुसार पति ने हाथ देने का वादा भी कर दिया। इसको लेकर दोनों में खूब झगड़ा हुआ तो पति अपने गांव चला गया। संतोष सोम शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचीं और शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। संतोष ने आरोप लगाया है कि पुलिस अब जानलेवा हमले की धारा हटाने के चक्कर में है। उसने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बंगाल में सरकारी पोर्टल हैक कर निकाले गए अनेक जन्म प्रमाण-पत्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- विभिन्न जिलों में तीन महीने से चल रहा था हैकिंग का दौर, जुलाई में चला पता
- ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं, जिनका जन्म सरकारी अस्पतालों में नहीं हुआ

आधिकारिक जन्म और मृत्यु पंजीकरण पोर्टल हैक करके बंगाल के कई जिलों में जन्म प्रमाण-पत्र निकालने का मामला प्रकाश में आया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने दिल्ली में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को भी इस बारे में सूचित किया है। पता चला है कि पिछले तीन महीने से हैकिंग का दौर चल रहा था।

जुलाई माह के आखिरी में राज्य के स्वास्थ्य विभाग को हैकिंग के बारे में पता चला। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी अजय चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य के मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी जिले में इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जहां आधिकारिक जन्म और मृत्यु पंजीकरण पोर्टल हैक करके जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं, जिनका जन्म सरकारी अस्पतालों में नहीं हुआ है। यह खबर जब स्वास्थ्य विभाग के स्टेट ब्यूरो आफ हेल्थ इंटेलिजेंस तक पहुंची तब अधिकारियों के कान खड़े हुए।

> राज्य की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी मामले को देख रहे हैं और पुलिस के संपर्क में हैं। कितने प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं, यह कहना मुश्किल है। पुलिस जांच कर रही है।
> –नारायणस्वरूप निगम, स्वास्थ्य सचिव, बंगाल

यह भी जताई जा रही आशंका : स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि इससे देश की सुरक्षा जुड़ी है। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि सरकारी पोर्टल में प्रवेश कर प्रमाण-पत्र निकाल लिए गए हैं। नतीजतन उन्हें नकली साबित करना मुश्किल हो सकता है। आशंका है कि पिछले तीन महीने से हैकिंग का दौर चल रहा है, इस दौरान अनेक प्रमाण-पत्र निकाले गए होंगे। सूत्रों का कहना है कि इनमें कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके माता-पिता दूसरे राज्य या दूसरे देश से बिना वैध दस्तावेजों के आए हों।

आसान है पोर्टल का हैक करना : कोलकाता के जाने-माने साइबर विशेषज्ञ सम्पाजीत मुखर्जी का कहना है कि सरकारी विभागों के पोर्टलों की हालत बेहद खस्ता है। सरकारी मानकों के अनुसार पोर्टलों की नियमित देखरेख नहीं की जाती है, जिस कारण हैकरों के लिए इस तरह के पोर्टलों को हैक करना काफी आसान रहता है। इस तरह की हैकिंग सामान्यता डिजिटल आडिटिंग के दौरान ही पता चलती है, क्योंकि यह अमूमन गैप होल्स, आसान शब्दों में कहें तो पिछले दरवाजे के जरिये की जाती है, जिसके कारण कर्मचारियों को इसका पता भी नहीं चलता है। दूसरी बात यह है कि मानकों के अनुसार पोर्टलों की नियमित जांच नहीं होती है, जिससे हैकिंग के बारे में पता नहीं चलता।

रिकार्ड के देखरेख की यह है व्यवस्था : केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय में जन्म और मृत्यु पंजीकरण का कार्यालय है। जिस तरह प्रत्येक राज्य में केंद्र के जनगणना संचालन निदेशालय का एक अलग कार्यालय होता है, उसी तरह प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों को जन्म और मृत्यु रिकार्ड की देखरेख का काम सौंपा गया है।

बाढ़ से मोर्चा लेने को ग्राउंड जीरो पर डटे योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जिलों में जाकर सदी की सबसे भयावह महामारी पर काबू पाने में कामयाबी हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ से मोर्चा लेने के लिए निकल पड़े हैं। आपदा के दौरान ग्राउंड जीरो पर टीम लीडर के तौर पर डटे रह कर हालात से पार पाने के संकल्प के तहत वह बाढ़ से निपटने की तैयारियों को परखने और इसकी विभीषिका से प्रभावित जनता की मदद के लिए पिछले एक हफ्ते के दौरान बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक का दौरा कर चुके हैं।

बारिश से गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों में आए उफान के कारण प्रदेश के दो दर्जन जिले बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। बाढ़ की स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के साथ बचाव व राहत कार्यों की निगरानी और आपदा से प्रभावित लोगों को संबल देने के लिए योगी बुंदेलखंड के जालौन व हमीरपुर जिलों के अलावा इटावा और औरैया का दौरा कर चुके हैं। गुरुवार को वह पूर्वांचल के वाराणसी जिले में थे, जहां बाढ़ की स्थिति जानने के लिए जोखिम की परवाह किए बगैर वह नाव पर सवार होकर उफनाती गंगा में निकल पड़े। शुक्रवार को उन्होंने बलिया और गाजीपुर जिलों का दौरा किया।

हर जिले के दौरे में योगी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण, आपदा पीड़ितों के लिए किए जा रहे राहत व बचाव कार्यों का जमीनी सत्यापन, स्थानीय प्रशासन के साथ बाढ़ के हालात, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के साथ जरूरी निर्देश भी देते हैं। वाराणसी दौरे के दौरान उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मीरजापुर, भदोही और चंदौली में बाढ़ की स्थिति व राहत कार्यों की समीक्षा की।

बाढ़ से प्रदेश के 24 जिलों के 1171 गांव प्रभावित हैं। शुक्रवार को गंगा नदी कचलाब्रिज बदायूं, प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, गाजीपुर व बलिया, यमुना प्रयागराज, शारदा पलियाकलां खीरी और क्वानो चंद्रदीपघाट गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। बचाव व राहत कार्यों के लिए नौ जिलों में एनडीआरएफ, 12 जिलों में एसडीआरएफ और 39 जिलों में पीएसी तैनात की गई है।

गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद गहमर इंटर कालेज में प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के दौरान बच्चे को टाफी देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

चंद्रभागा नदी में गिरा पहाड़, ढाई घंटे अटकी रहीं सांसें

जागरण संवाददाता, केलंग

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहुल स्पीति के नाल्डा में शुक्रवार सुबह पहाड़ दरकने से गिरे मलबे से चंद्रभागा नदी का बहाव करीब ढाई घंटे रुके रहने से लोगों की सांसें अटकी रहीं। नदी ने झील का आकार ले लिया, जिससे हुए जलभराव से जुंडा व जसरथ गांव के चार घर व सैकड़ों बीघा उपजाऊ भूमि डूब गई। पानी की चपेट में आने से घर में फंसी दो महिलाएं घायल हो गईं।

चंद्रभागा का बहाव रुकने से लाहुल से लेकर चंबा के पांगी और जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ तक हड़कंप मचा रहा। करीब ढाई घंटे बाद तेज बहाव से मलबा बहने लगा। पानी की निकासी के बाद प्रशासन व लोगों ने राहत की सांस ली। चंद्रभागा का बहाव रुकने की सूचना मिलते ही सरकार भी हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहुल स्पीति के विधायक एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय के साथ मुख्य सचिव रामसुभाग सिंह व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू को जायजा लेने के लिए हेलीकाप्टर के माध्यम से शिमला से भेजा। उन्होंने जुंडा पहुंचकर प्रभावित परिवारों का हाल जाना। हालात का जायजा लेने के बाद मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को रिपोर्ट सौंप दी है। प्रवाह दोबारा शुरू होने से फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं।

घटना को पहले हल्के में लिया था लोगों ने : सुबह नौ बजे जब पहाड़ दरका तो ज्यादातर ग्रामीण खेतों में काम कर रहे थे। कुछ लोग अपने कार्य से जा रहे थे। पहाड़ दरकने की घटना को पहले तो लोगों ने हल्के से लिया। मगर नदी का बहाव रुकते ही जब झील बननी शुरू हुई तो जुंडा व जसरथ के ग्रामीणों की सांसें अटक गईं।

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहुल स्पीति में शुक्रवार को नाल्डा में पहाड़ दरकने के बाद मलबे से रुका चंद्रभागा नदी का बहाव। जागरण

> पहाड़ दरकने से रुका चंद्रभागा का प्रवाह सामान्य शुरू हो गया है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता की जाएगी।
> –डा. रामलाल मार्कंडेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश

गले तक डूब गई थी पानी में, रुकने लगी थी सांस

जासं, केलंग : हिमाचल में पहाड़ दरकने से चंद्रभागा का बहाव रुकने का अहसास जुंडा गांव की सुमन व दमयंती को उस समय हुआ, जब उनके घर पानी में डूबने लगे। एकदम से घर पानी में डूबने लगे तो अंदर बैठी महिलाओं सुमन व दमयंती की जान पर बन आई। देखते ही देखते वे गले तक पानी में डूब गईं। सांस रुकने लगी थी। ग्रामीणों को उनका घर के अंदर फंसे होने का पता देरी से चला। इसके बाद ग्रामीणों ने जान पर खेलते हुए दोनों को बाहर निकाला। जुंडा गांव की सुमन और दमयंती ने आपबीती साझा करते हुए बताया कि कुछ पल के लिए तो उन्हें लगा कि अब वे जिंदा नहीं बचेंगी। वे घर में ही डूब जाएंगी। थोड़ी हिम्मत कर शोर मचाते हुए उन्होंने अपने फंसे होने की सूचना ग्रामीणों तक पहुंचाई। भाई सुशील को उनके घर के अंदर फंसे होने का पता चला तो उन्होंने ग्रामीणों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। सुमन ने बताया कि इस दौरान उनकी बाजू में चोट लगी है। बाजू में फ्रैक्चर हुआ है। दोनों महिलाओं ने बताया कि मदद में पलभर की भी देरी हो जाती तो वे जिंदा नहीं बचतीं।

मुंबई में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट से पहली मौत

चिंताजनक ▶ टीके की दोनों डोज लेने के बाद महिला हुई थी संक्रमित

लगातार दूसरे दिन 40 हजार से अधिक नए मामले

जेएनएन, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट के बाद अब उसी से पैदा हुए डेल्टा प्लस वैरिएंट के भी खतरनाक होने की आशंका पैदा हो गई है। मुंबई में डेल्टा प्लस वैरिएंट से पहली मौत हुई है। चिंता की बात यह है कि जिस महिला की जान गई है, उसने कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज भी लगवा ली थी। महाराष्ट्र में इस वैरिएंट से तीन लोगों की जान जा चुकी है और 65 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 40 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि उससे पहले नए मामले 40 हजार से नीचे आ गए थे। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने कहा कि कोरोना से संक्रमित 63 साल की महिला की 24 जुलाई को मौत हो गई थी। घाटकोपर की रहने वाली इस महिला की जांच रिपोर्ट गुरुवार को मिली तब इसके डेल्टा प्लस वैरिएंट से संक्रमित होने का पता चला। डेल्टा प्लस वैरिएंट से मुंबई में यह पहली मौत है। महिला ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ली थी और उसके बाद 21 जुलाई को उसे कोरोना से संक्रमित पाया गया था। महिला के संपर्क में आए दो और लोग भी इस वैरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रायगढ़ में 69 साल के कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की 22 जुलाई को मौत हो गई थी, बाद में उसके डेल्टा प्लस वैरिएंट से संक्रमित होने की रिपोर्ट आई थी। इससे पहले 13 जून को रत्नागिरी में 80 साल की एक मरीज की मौत हुई थी। बाद में उस महिला के डेल्टा प्लस वैरिएंट से संक्रमित होने का पता था। महिला ने कोरोना रोधी वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में 40,120 नए केस मिले हैं, 585 की मौत हुई है और 42,295 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामले घटकर 3,85,227 रह गए हैं।

शुक्रवार शाम छह बजे तक किस राज्य में कितने टीके

राज्य	टीके
उत्तर प्रदेश	6.70 लाख
गुजरात	5.52 लाख
राजस्थान	4.86 लाख
बिहार	4.31 लाख
महाराष्ट्र	2.72 लाख
हिमाचल	1.89 लाख
हरियाणा	1.64 लाख
पंजाब	1.49 लाख
दिल्ली	1.20 लाख
उत्तराखंड	0.95 लाख
छत्तीसगढ़	0.86 लाख
मध्य प्रदेश	0.58 लाख
जम्मू-कश्मीर	0.56 लाख
झारखंड	0.53 लाख

(कोविन प्लेटफार्म के आंकड़े)

देश में कोरोना की स्थिति

24 घंटे में नए मामले	40,120
कुल सक्रिय मामले	3,85,227
24 घंटे में टीकाकरण	57.31 लाख
कुल टीकाकरण	52.95 करोड़

शुक्रवार सुबह 08 बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	40,120
कुल मामले	3,21,17,826
सक्रिय मामले	3,85,227
मौतें (24 घंटे में)	585
कुल मौतें	4,30,254
ठीक होने की दर	97.46 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.04 फीसद
सा.पाजिटिविटी दर	2.13 फीसद
जांचें (गुरुवार)	19,70,495
कुल जांचें (गुरुवार)	48,94,70,779

स्वतंत्रता के सारथी — **महामारी से आजादी**

मुश्किल समय में बने मदद के चैंपियन

विश्व जूनियर गोल्फ चैंपियन ने सैकड़ों किमी दूर बैठकर भी कोरोना संक्रमितों की जान बचाई

मनीष तिवारी • ग्रेटर नोएडा

छोटी उम्र में बड़ा नाम और बड़ा काम। यही पहचान है विश्व जूनियर गोल्फ चैंपियन अर्जुन भाटी की। कोरोना काल में अर्जुन ने देश व समाज के प्रति जिम्मेदारी समझते हुए इंटरनेट मीडिया पर सैकड़ों किलोमीटर दूर संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की मदद कर एक मिसाल कायम की है। 17 साल के अर्जुन ने दूसरी लहर के दौरान लगभग डेढ़ माह तक देश के विभिन्न हिस्सों के 600 से अधिक अनजान लोगों तक मदद पहुंचा कर उनकी जान बचाई।

कुछ ऐसे भी रहे जिनकी जान वह नहीं बचा सके, उनकी मौत का दर्द अर्जुन को आज भी कचोटता है। अर्जुन के पिता बाबी व मां अमृता भाटी भी संक्रमण की गिरफ्त में आ गए थे। दोनों होम आइसोलेट थे। नियमित रूप से माता-पिता की सेवा के साथ अर्जुन अन्य लोगों की मदद में भी रात-दिन जुटे रहे। अर्जुन एफसीजी कैलअवे विश्व जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप 2019 में विजेता रहे हैं।

अर्जुन भाटी • सौ. स्वयं

ट्राफियां बेचकर दिया लाखों का दान

कोरोना संक्रमण की पहली लहर में अर्जुन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीती विभिन्न ट्राफियों को नीलाम कर लगभग साढ़े आठ लाख रुपये एकत्र किए थे। इस पैसे को कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए पीएम केयर्स फंड में दान कर दिया था। उनकी अपील पर लोगों ने भी 76 लाख रुपये राहत कोष में जमा कराए थे। रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने अर्जुन के प्रयास को सराहा था, साथ ही पत्र भेजकर उनको बधाई दी थी।

फिल्मी सितारों से लेकर राजनेताओं तक से कराई मदद: राजस्थान के उदयपुर निवासी हेमेंद्र ने ट्वीट कर अर्जुन से मदद मांगी कि परिवार के कोरोना पीड़ित सदस्य का आक्सीजन लेवल 32 पर आ गया है। वह अस्पताल में भर्ती हैं, वेंटिलेटर बेड की आवश्यकता है। अर्जुन ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को ट्वीट कर हेमेंद्र की मदद की गुहार लगाई। कुछ देर बाद उनकी टीम की सदस्य सौम्या ने ट्वीट कर अर्जुन को बताया कि मदद हो गई है। अस्पताल में वेंटिलेटर बेड उपलब्ध करा दिया गया है। दो दिन बाद हेमेंद्र ने आभार व्यक्त किया कि आप की मदद से आक्सीजन लेवल 32 होने के बावजूद जान बच गई।

विशाखापटनम तक की सहायता: अर्जुन को पता चला कि विशाखापटनम के वेदमरुता अस्पताल में 30 कोरोना संक्रमित भर्ती हैं। अस्पताल में मात्र आधे घंटे की ही आक्सीजन बची है। अर्जुन ने ट्वीट कर तत्काल फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगी। कुछ मिनट बाद ही सोनू सूद ने ट्विटर पर जवाब दिया कि अस्पताल के लिए आक्सीजन टैंकर रवाना हो गया है। अर्जुन के एक अन्य ट्वीट पर सोनू सूद ने करनाल में 30 लोगों के लिए प्लाज्मा की व्यवस्था कराई।

स्मृति ईरानी से मांगी मदद: इंटरनेट मीडिया का सदुपयोग करते हुए अर्जुन ने फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी व सोनल चौहान से ट्वीट कर मदद मांगी और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, आक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कराई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ट्वीट कर उप्र के अमेठी में चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की।

स्थानीय लोगों तक भी पहुंचे: सेलेब्रिटी के जरिये ही अर्जुन ने संक्रमितों की मदद नहीं की बल्कि स्वयं भी नोएडा निवासी सिद्धार्थ तिवारी, सोनीपत निवासी राज पुरोहित व अन्य को रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे। कई लोगों की आर्थिक मदद की। दिल्ली-एनसीआर में कई को आक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। अर्जुन बताते हैं कि वह लखनऊ निवासी कंचन की जान नहीं बचा सके। जिसका उन्हें बहुत दुख है।

समीक्षा करने केरल जाएंगे मांडविया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केरल में कोरोना के बेकाबू होते हालात को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य का दौरा करने का फैसला किया है। वह सोमवार को केरल में होंगे। इसके अगले दिन गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। केरल व पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमण दर ज्यादा है जो चिंता का विषय बना हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले दो हफ्ते से देश में आने वाले कुल संक्रमित मरीजों में से आधे से अधिक केरल से हैं। यही नहीं, केरल के अधिकतर जिलों में संक्रमण दर 10 फीसद से अधिक है। पिछले दिनों विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम ने केरल का दौरा कर रिपोर्ट दी थी, कोरोना के बेकाबू होने के लिए कई कमियों को रेखांकित किया था। अब मांडविया केरल का दौरा कर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वह आने वाले त्योहारों को देखते हुए कोरोना प्रोटोकाल की सख्ती के साथ पालन करने को भी कहेंगे।

लक्षद्वीप ने यात्रा पर प्रतिबंध लगाया

करवत्ती, प्रेट्र : लक्षद्वीप प्रशासन ने पड़ोसी राज्यों खास तौर से केरल में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए द्वीप से लोगों के बाहर जाने की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। लक्षद्वीप जिला कलेक्टर एस अस्केर अली द्वारा जारी आदेश में कहा गया, 'परिस्थितियों पर विचार करते हुए लक्षद्वीप के स्थानीय निवासियों को द्वीप से बाहर अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है।' प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को मुख्य भूमि की केवल आवश्यक यात्रा की अनुमति देने का निर्देश दिया है। मुख्य भूमि से द्वीप के तीन प्रवेशद्वार केरल में कोच्चि और कोझिकोड और कर्नाटक में मंगलुरू हैं। प्रशासन के अनुसार, कोविड-19 की स्थिति स्थिर है और 12 अगस्त तक द्वीप में केवल 40 सक्रिय मामले हैं।

प्रशासन ने कहा कि जो लोग मुख्य भूमि से या अन्य द्वीप से आए हैं उन्हें अनिवार्य रूप से सात दिनों तक प्रशासन द्वारा उपलब्ध संस्थागत क्वारंटाइन सुविधा में या अपने घर में जहां बाथरूम के साथ एक अलग कमरा उपलब्ध होगा उसमें क्वारंटाइन रहना होगा।

साइरस पूनावाला का बड़ा बयान, वैक्सीन निर्यात पर प्रतिबंध बहुत बुरा कदम

▶ सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ने कहा, बेटे ने इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा था

▶ मोदी सरकार में लाल फीताशाही और लाइसेंस राज बहुत कम, पहले पकड़ने पड़ते थे नौकरशाहों के पैर

पुणे, प्रेट्र: दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (एसआइआइ) के चेयरमैन डा. साइरस पूनावाला ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना रोधी वैक्सीन के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को बहुत बुरा कदम करार दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि इस कदम ने उनकी कंपनी को बहुत मुश्किल में डाल दिया है।

उन्होंने कहा कि कहा कि उनके बेटे और सीआइआइ के सीईओ अदार पूनावाला ने उनसे इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलने को कहा था। सीरम कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन कर रही है।

पूनावाला ने कहा, 'मोदी सरकार का यह कदम बहुत ही बुरा है। मेरे पुत्र ने मुझसे इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोलने को कहा था। लेकिन मेरा मानना है कि निर्यात को खोलना चाहिए।' साइरस पूनावाला यहां लोकमान्य तिलक अवार्ड प्राप्त करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 150 से ज्यादा देश वैक्सीन के लिए एसआइआइ पर निर्भर हैं और अग्रिम भुगतान भी किया है, लेकिन कंपनी पाबंदियों के चलते उन्हें वैक्सीन की सप्लाई नहीं कर पा रही है। इसके लिए कंपनी को आरोपित ठहराया जा रहा है।

अब मस्का पालिश की जरूरत नहीं: पूनावाला ने कहा कि मोदी सरकार में लाल फीताशाही और लाइसेंस राज में बहुत कमी आई है। अब मस्का पालिश की जरूरत नहीं। हमारे पास एक ऐसा दवा नियंत्रक है जो आफिस का समय खत्म होने के बाद भी जवाब देता है। यही कारण है कि कंपनी कोरोना रोधी वैक्सीन जल्द लांच करने में सफल रही। 50 साल पहले सरकारी मंजूरी के लिए नाको चने चबाने पड़ते थे और दवा नियंत्रक एवं नौकरशाहों के पैरों में गिरना पड़ता था। बिजली और पानी के कनेक्शन लेना तक में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आवागमन के साधन भी बढ़िया नहीं थे।

मिक्स कोरोना वैक्सीन का किया विरोध: साइरस पूनावाला ने कहा कि वह मिक्स कोरोना वैक्सीन के उपयोग के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मिक्स वैक्सीन लगाई जाती है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो एसआइआइ कहेगी कि दूसरी कंपनी की वैक्सीन खराब है और दूसरी कंपनी कहेगी कि एसआइआइ की वैक्सीन खराब है। इससे वांछित नतीजे नहीं मिलेंगे।

गौरतलब है कि मिक्स डोज से मतलब एक ही व्यक्ति को एक डोज एक टीके की और दूसरी डोज दूसरे टीके की लगाने से है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गलती से पहली डोज कोविशील्ड की और दूसरी कोवैक्सीन की लगा दी गई थी, जिसके नतीजे बेहतर आए हैं। इसके बाद ही दवा नियंत्रक ने मिक्स डोज पर अध्ययन को मंजूरी दी है।

स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने को केंद्र ने राज्यों को 7,500 करोड़ दिए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों से सीख लेते हुए सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती के लिए घोषित 23 हजार करोड़ रुपये के दूसरे पैकेज के तहत राज्यों की कार्ययोजना को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने न सिर्फ मंजूरी दे दी है, बल्कि इसके लिए अपने हिस्से की 50 फीसद रकम यानी 7,500 करोड़ रुपये राज्यों को जारी भी कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार वे खुद पैकेज के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहे हैं।

आठ जुलाई को कैबिनेट ने 23 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूरी दी थी, जिसमें 15 हजार करोड़ रुपये केंद्र व आठ हजार करोड़ रुपये राज्य सरकारों को मुहैया कराना था। पैकेज की घोषणा के तत्काल बाद मांडविया राज्यों के साथ मिलकर उसकी कार्ययोजना तैयार करने में जुट गए थे। राज्यों की कार्ययोजना की तैयारी के दौरान ही केंद्र ने 22 जुलाई को अपने हिस्से की राशि में से 15 फीसद एडवांस में जारी कर दिया था। मांडविया के अनुसार शुक्रवार को सभी राज्यों की कार्ययोजना को मंजूर करते हुए उन्हें 35 फीसद राशि और जारी कर दी गई।

स्वास्थ्य ढांचे के लिए जारी दूसरे पैकेज के तहत ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में तीसरी लहर के पहले आक्सीजन रखने के लिए भंडार, पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था, जिसमें बच्चों के लिए 20 फीसद बेड आरक्षित रहेंगे और हर ब्लाक में कम से कम एक एंबुलेंस का प्रविधान शामिल है। साथ ही हर जिले में कोरोना के इलाज में प्रयक्त होने वाली दवाओं का भंडारण भी किया जाएगा। मांडविया ने कहा कि हर जिले में एक करोड़ रुपये की ऐसी दवाओं के भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जिला अस्पतालों को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने का भी प्रविधान है। इसके अलावा ई-संजीवनी को मजबूत कर कोरोना काल में लोगों को टेलीमेडिसिन की मदद से भी इलाज उपलब्ध कराने का विकल्प भी तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय फलक

कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के दवा नियामक ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहली नेजल (नाक के जरिये दी जाने वाली) वैक्सीन के दूसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक यह वैक्सीन विकसित कर रही है।

शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने कहा कि पहले चरण का क्लीनिकल ट्रायल 18 से 60 वर्ष आयुवर्ग के लोगों पर किया गया था। इसमें दवा का कोई प्रतिकूल प्रभाव नजर नहीं आया था। डीबीटी ने कहा कि भारत बायोटेक की यह पहली नेजल वैक्सीन है जिसके दूसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल को दवा नियामक से मंजूरी मिली है। इससे पहले जारी बयान में डीबीटी ने कहा था कि नेजल वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल को मंजूरी दी गई है।

यह वैक्सीन नाक के जरिये दी जाएगी। अगर इस परीक्षण सफल रहता है तो भारत के लिए बहुत ही अहम होगा, क्योंकि इससे टीकाकरण में बहुत तेजी आ जाएगी।

फैमिली डाक्टर व्यवस्था को पुनर्जीवित करें : डा. रघु राम

हैदराबाद, आइएएनएस: भारत समेत पूरा विश्व इस समय कोरोना की चपेट में है। देश में पहले से ही नाजुक स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को इस महामारी ने उजागर कर दिया है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक पी. रघु राम ने फैमिली डाक्टर/सामान्य चिकित्सक (जीपी) व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की वकालत की है।

पद्म श्री से सम्मानित जाने माने ब्रेस्ट कैंसर सर्जन डा. रघु राम ने कहा कि फैमिली डाक्टर/जीपी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मरीज किसी भी बीमारी के लिए सबसे पहले इन्हीं के पास जाएं। इससे अस्पतालों पर बोझ कम होगा और उनके महंगे संसाधनों का उपयोग उन लोगों के लिए हो सकेगा, जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी।

हाल ही में आर्डर आफ ब्रिटिश एंपायर (ओबीई) से सम्मानित डा. रघु राम ने कहा कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) में किसी विशेषज्ञ के पास जाने से पहले फैमिली डाक्टर/जीपी से दिखाने की मान्य व्यवस्था है। मरीज को देखने के बाद फैमिली डाक्टर/जीपी ही मरीज को जरूरी होने पर विशेषज्ञ डाक्टर के पास भेजता है। उन्होंने कहा कि एक समय सर्वव्यापी रही फैमिली डाक्टर/जीपी की व्यवस्था अब लगभग खत्म हो गई है। सबसे चिंता की बात है कि मामूली बीमारी पर भी लोग अस्पताल भागे चले जाते हैं जो पहले से ही गंभीर मरीजों से भरे होते हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) की 2020 की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए डा. रघु राम ने कहा कि इसके मुताबिक हर साल 55 हजार निकलने वाले डाक्टरों के लिए पोस्टग्रेजुएट की 44 हजार सीटें उपलब्ध हैं यानी बड़ी संख्या में ग्रेजुएट डाक्टर स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। लेकिन विडंबना है कि 890 पन्ना की इस रिपोर्ट में नए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में फैमिली डाक्टर/जीपी की अवधारणा के बारे में उल्लेख भी नहीं है।

किशोरी से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म

जासं, सोनीपत : सदर थानाक्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ युवकों ने चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया। युवक रात में किशोरी को घर के बाहर से जबरन कार में डाल ले गए। चलती कार में तीन युवकों ने किशोरी से बारी-बारी से दुष्कर्म किया। 16 वर्षीय किशोरी पांच घंटे तक आरोपितों के कब्जे में रही। इसके बाद युवक उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गए। जांच अधिकारी डीएसपी सतीश गौतम ने बताया कि अपहरण कर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। किशोरी का मेडिकल कराया गया है। अब न्यायालय में बयान कराकर काउंसलिंग कराई जाएगी।

सदर थानाक्षेत्र के एक गांव में गुरुवार रात करीब 11 बजे प्रदीप नाम के युवक ने किशोरी को उसके घर के बाहर से कार में अगवा कर लिया। कार में गांव के ही विक्की और हरीश भी मौजूद थे। पिस्तौल से डराकर तीनों ने चलती कार में बारी-बारी से उससे दुष्कर्म किया। वह किशोरी को कार में लेकर घूमते रहे। वह किशोरी को सुबह चार बजे घर के पास छोड़ गए।

'खर्च कम करने पर विचार करे अस्पताल'

▶ पति के इलाज के लिए पीएम केयर्स और सीएम फंड से मदद दिलाने का मामला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना के बाद फेफड़ों में फाइब्रोसिस के कारण जीवन और मौत के बीच झूल रहे पति के इलाज के लिए पीएम केयर्स फंड और सीएम फंड से मदद दिलाए जाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल से कहा है कि वह इलाज का खर्च कम करने पर विचार करे। कोर्ट ने अस्पताल के वकील से कहा कि वह सोमवार तक बताएं कि क्या खर्च में कमी हो सकती है? मामले में कोर्ट सोमवार को फिर सुनवाई करेगा।

मध्य प्रदेश के रहने वाले साफ्टवेयर इंजीनियर मनीष को कोरोना संक्रमण के बाद फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो गई है। फाइब्रोसिस एक गंभीर बीमारी है, जिसमें फेफड़े के टिशू क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मनीष इस वक्त हैदराबाद के एक अस्पताल में ईसीएमओ सपोर्ट पर है। उसे फेफड़ों के ट्रांसप्लांट की जरूरत है। पत्नी शीला मेहरा ने पति के इलाज के लिए पीएम केयर्स फंड और सीएम फंड से मदद दिलाने की मांग की है। पत्नी भी साफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका कहना है कि अब तक पति के इलाज में एक करोड़ रुपये खर्च हो चुका है और एक करोड़ की और जरूरत है।

मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एलएन राव की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने अस्पताल की ओर से पेश वकील से पूछा कि ईसीएमओ में प्रतिदिन कितना खर्च आता है? वकील ने कहा कि अस्पताल ने उन्हें खर्च का चार्ट बनाकर दिया है। पीठ ने कहा कि याचिका में कहा गया है कि मरीज को फेफड़ों के ट्रांसप्लांट की जरूरत है। कोर्ट ने वकील से कहा कि अस्पताल से कहिए कि थोड़ी दया दिखाए। इलाज का खर्च थोड़ा कम करे। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल से पूछ कर सोमवार तक बताएं कि क्या इलाज का खर्च कम हो सकता है? पीठ ने कहा कि अगर वह सरकार से कहेगी कि याचिकाकर्ता के ज्ञापन पर विचार किया जाए, तो इससे उसकी कोई मदद नहीं होने वाली।

अस्पताल के वकील ने कहा कि अगर मरीज की हालत में सुधार होता है तो थोड़े दिन में ईसीएमओ से हटाया जा सकता है। हो सकता है हालत और सुधरे तो फेफड़ों के ट्रांसप्लांट की जरूरत न पड़े। कोर्ट ने कहा कि वह अस्पताल से पूछ कर बताएं कि क्या अस्पताल खर्च में कुछ कमी कर पाएगा? पीठ ने कहा कि वह सात-आठ लाख तक की मदद को कह सकती है। अस्पताल के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी तक मरीज के इलाज का कुल 44 लाख से ज्यादा रुपये का बकाया है। कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी।

याचिकाकर्ता का पति अस्पताल में ईसीएमओ (एक्स्ट्राकारपोरियल मेम्बरेन आक्सीजेनेशन) सपोर्ट पर है। ईसीएमओ एक तरह की मशीन होती है। फेफड़ों व दिल के ठीक से काम नहीं करने पर इसका प्रयोग मरीज के शरीर में बाहर से खून और आक्सीजन पंप करने में किया जाता है। मनीष ईसीएमओ सपोर्ट पर है, जिस पर रोजाना दो लाख का खर्च आता है। 15 से 20 दिन में जब आक्सीजेनेटर बदला जाता है, उस दिन चार लाख का खर्च आता है। मंहगे इलाज में सारे पैसे और बीमा खत्म होने के बाद परिवार ने इलाज में आर्थिक मदद के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद की गुहार लगाई।

उपयोगी तकनीक

हवा में ही रोगाणुओं को खत्म करने की तैयारी

आइआइटी मद्रास ने ब्रिटिश शोध संस्थान संग मिलकर सस्ती तकनीक पर शुरू किया काम, अल्ट्रावायलेट-सी रेडियेशन के इस्तेमाल पर हो रहा काम, कोरोना के साथ टीबी से बचाव में भी मिलेगी मदद, दफ्तरों, अस्पतालों व भीड़ वाली जगहों के लिए उपयोगी होगी यह तकनीक

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

कोरोना वायरस और क्षयरोग यानी टीबी (ट्यूबरक्लोसिस) जैसी गंभीर बीमारियों का फैलाव जिस तरह से हवा के जरिए हो रहा है, उसे देखते हुए विज्ञानियों ने अब हवा में ही रोगाणुओं को खत्म करने की तकनीक विकसित करने पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), मद्रास ब्रिटेन के उच्च शिक्षण संस्थान की मदद से इस दिशा में शोध कर रहा है। एक ऐसे सशक्त और किफायती बायो-एरोसोल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है, जो बंद कमरों, दफ्तरों और अस्पतालों आदि के लिए काफी उपयोगी होगा।

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस प्रोजेक्ट में आइआइटी, मद्रास की मदद कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत अल्ट्रावायलेट-सी रेडिएशन के इस्तेमाल से हवा को साफ करने में बहुत हद तक सफलता मिली है, लेकिन अभी इस को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अब तक के शोध यह साफ हो गया है, कि इसके इस्तेमाल से वायरस और हवा में फैलने वाले दूसरे रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रचुर क्षमता है। भारत जैसे देश के लिए फिलहाल इसे काफी उपयोगी माना जा रहा है, क्योंकि हवा को साफ करने के लिए अभी जो तकनीक है, वह काफी मंहगी है। मौजूदा तकनीक का रखरखाव भी महंगा है, जबकि जिस तकनीक पर काम हो रहा है वह सस्ती होने के साथ ही उसका रखरखाव भी किफायती होगा। यह सिस्टम बंद कमरों, दफ्तरों और अस्पताल आदि के लिए काफी उपयोगी होगा।

कोरोना संक्रमण ने दिखाई राह

प्रोजेक्ट से जुड़े आइआइटी, मद्रास के प्रोफेसर अब्दुल समद के मुताबिक कोरोना संकट के दौरान हम सभी इस बात से डर गए थे कि हवा में मौजूद रोगाणुओं से कैसे बचा जाए। इसके बाद ही इस दिशा में काम शुरू किया गया था। इसमें प्रोजेक्ट में तकनीकी मदद के लिए ब्रिटेन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी और चेन्नई स्थित बेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान (वीआइटी) के साथ भी करार किया गया है।

उपभोक्ताओं का बढ़ेगा भरोसा

प्रोफेसर समद ने कहा, इस प्रोजेक्ट के जरिये ऐसा सिस्टम बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है जो उपभोक्ताओं के भरोसे को मजबूती दे। मौजूदा समय में बाजार में हवा में मौजूद रोगाणुओं से बचाव को लेकर कई तकनीक हैं जिसे लेकर उपभोक्ता भ्रम में ही रहते हैं, यानी यह सुरक्षा दे रही है यह नहीं, लेकिन इस नई तकनीक में उपभोक्ता खुद देख सकेंगे कि उन्हें सुरक्षा मिल रही है।

हर साल टीबी से होती हैं लाखों मौतें

गौरतलब है कि कोरोना महामारी में अब तक देश में चार लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं टीवी से भी हर साल के देश को लाखों को लोग दम तोड़ देते है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में देश में 4.45 लाख लोगों की टीबी की गंभीर बीमारी से जान गंवानी पड़ी। टीबी के रोगाणु हवा से ही फैलते हैं।

पुजारियों का आरोप-गेट पर ताले लगे होने से भस्मारती में हुई देरी

▶ पुजारियों ने कहा - भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय व अन्य नेताओं की वजह से आई बाधा

▶ मंदिर प्रशासन ने कहा- भस्मारती में नहीं हुई कोई देरी, सबकुछ तय समय पर हुआ

नईदुनिया, उज्जैन

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नागपंचमी पर शुक्रवार तड़के तीन बजे भस्मारती में कुछ अव्यवस्था हो गई। मंदिर के कुछ पुजारियों का आरोप है कि गेट पर ताले लगे होने से भस्मारती में देरी हुई है। हालांकि, पुजारियों के आरोप को मंदिर प्रशासन ने खारिज कर दिया है। प्रशासन ने कहा कि सब कुछ तय समय पर हुआ है।

मंदिर के कुछ पुजारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय स्वजन सहित मंदिर पहुंचे तो उनके प्रवेश के बाद मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया गया। इस कारण महाकाल का श्रृंगार करने वाले पंडित अजय पुजारी और अन्य पंडित समय से मंदिर में नहीं पहुंच पाए। इस कारण भस्मारती में देरी हो गई। हालांकि आरती करने वाले पंडित संजय पुजारी कैलाश विजयवर्गीय के पहले ही मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। दूसरी ओर मंदिर प्रशासक व कलेक्टर आशीष सिंह ने भस्मारती में देरी की बात को खारिज कर दिया। सहायक मंदिर प्रशासक व तहसीलदार पूर्णिमा सिंगी ने बताया कि श्रावण मास में सोमवार को छोड़ आम दिनों में रात्रि तीन से सुबह पांच बजे तक भस्मारती होती है। शुक्रवार को भी निर्धारित समय पर आरती हुई। इधर, कोरोना के चलते भस्मारती व गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी के बावजूद विजयवर्गीय के पहुंचने के मामले में कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है।

टाटा पावर ने 100 मेगावाट की सौर परियोजना चालू की

नई दिल्ली: टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के राघनेस्दा सोलर पार्क में 100 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली एक सौर परियोजना शुरू की है। इस परियोजना से प्रत्येक वर्ष कार्बन उत्सर्जन में दो लाख टन की कमी आएगी। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित राघनेस्दा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े सौर उद्यानों में से एक है। (प्रेट्र)

घरेलू निर्यातकों को कृषि उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह अभी भी देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।

– विजय राघवन, सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार

सेंसेक्स	55,437.29	▲ 593.31
निफ्टी	16,529.10	▲ 164.70
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 45,586	▲ ₹222
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹61,045	▲ ₹100
डॉलर	₹74.28	▲ ₹0.03
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 71.24	

एक नजर में

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 889 मिलियन डालर की वृद्धि

मुंबई: छह अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 889 मिलियन डालर की वृद्धि दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 620.576 अरब डालर से बढ़कर 621.464 अरब डालर हो गया है। (आइएएनएस)

ग्रोफर्स में हिस्सेदारी के लिए जोमैटो को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने जोमैटो द्वारा आनलाइन ग्रासरी कंपनी ग्रोफर्स में 9.3 फीसद हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी प्रदान कर दी। इस अधिग्रहण पर जोमैटो 750 करोड़ रुपये खर्च करेगी। (आइएएनएस)

नए उत्सर्जन मानक लागू हुए तो कारों की कीमत में होगा इजाफा : भार्गव

नई दिल्ली: मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआइ) के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि अगर अगले साल से नए उत्सर्जन मानक लागू होते हैं तो वाहन कंपनियां कीमत बढ़ाने के लिए बाध्य होंगी। ऐसी स्थिति में पहले से ही गंभीर मंदी का सामना कर रहे वाहन उद्योग की बिक्री में और गिरावट आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कारों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई और इससे लोगों के लिए नई कार खरीदना मुश्किल हो रहा है। (प्रेट्र)

जुलाई में निर्यात में 50 फीसद की वृद्धि

नई दिल्ली: जुलाई माह के दौरान देश का निर्यात 49.85 फीसद बढ़कर 35.43 अरब डालर हो गया। सबसे ज्यादा तेजी पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग और रत्न और आभूषण क्षेत्र में दिखाई दी। इस समयावधि में व्यापार घाटा बढ़कर 10.97 अरब डालर पर पहुंच गया। (प्रेट्र)

घर खरीदने के लिए कर्ज देगा आइसीआइसीआइ

नई दिल्ली: स्वरोजगार करने वाले ऐसे लोग, जिनके पास अपनी कमाई दिखाने के लिए आयकर रिटर्न नहीं है, उन्हें अपना सपनों का घर खरीदने के लिए आइसीआइसीआइ होम फाइनेंस कर्ज देगा। (प्रेट्र)

अगले साल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, परिभाषित भी किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पर्यावरण के लिए खतरा बने सिंगल-यूज प्लास्टिक से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। एक जुलाई 2022 के बाद से देश में इसका इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। इसी के साथ सरकार ने प्लास्टिक बैग की मोटाई को लेकर तैयार किए गए नए नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। यह 30 सितंबर के बाद लागू होगी। पहले चरण में प्लास्टिक की मोटाई को 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन करने का प्रस्ताव है, जबकि अगले चरण में इसे 75 माइक्रोन से बढ़ाकर 100 माइक्रोन या उससे ज्यादा किया जाएगा।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में बदलाव करते हुए नया नोटीफिकेशन जारी किया है। इसके तहत 'सिंगल यूज प्लास्टिक' के इस्तेमाल को एक जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पाली स्टाइनिग व एक्सपैंडेड पालीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध होगा। सरकार ने पहली बार सिंगल यूज प्लास्टिक को भी परिभाषित किया है। वह वस्तुएं इस श्रेणी में आएंगी, जिसे डिस्पोजल या रीसाइकिल के पहले एक काम के लिए एक बार ही प्रयोग में लाया जाना है। मंत्रालय ने यह कदम पीएम मोदी के उस एलान के बाद उठाया जिसमें उन्होंने 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने की बात कही थी।

इन पर पड़ेगा असर

प्रतिबंध अमल में आने के बाद आइसक्रीम और गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, सजावट में इस्तेमाल किए जाने थर्मोकोल, प्लास्टिक के कप-प्लेट, ग्लास, चम्मच, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट पर लपेटी जाने वाली प्लास्टिक आदि का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

गांवों की भी बढ़ेगी जिम्मेदारी

प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल के लिए अब ग्राम पंचायतों को भी व्यवस्था बनानी होगी। इस नए नोटीफिकेशन में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करने सहित सभी इकाईयों को प्लास्टिक कचरे को अलग करने, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल आदि कार्यों को पूरा करना होगा।

आदि गोदरेज ने दिया गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पद से इस्तीफा

नई दिल्ली, प्रेट्र: जाने-माने उद्योगपति और गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आदि गोदरेज ने शुक्रवार को कंपनी के चेयरमैन पद और निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने एलान किया है कि नादिर गोदरेज (आदि के छोटे भाई) एक अक्टूबर को चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। नादिर फिलहाल कंपनी के एमडी हैं। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आदि गोदरेज गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन और जीआइएल के मानद चेयरमैन बने रहेंगे। इस्तीफा देने के बाद 79 वर्षीय आदि गोदरेज ने कहा, 'चार दशक से अधिक समय से गोदरेज इंडस्ट्रीज की सेवा करना सौभाग्य की बात है। इस दौरान ना केवल अच्छे वित्तीय नतीजे सामने आए बल्कि कंपनी में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़े।'

आदि गोदरेज • फाइल फोटो

उचित मूल्य और खरीद की गारंटी से निकलेगा तिलहनों से तेल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्लीः खाद्य तेलों की घरेलू खपत में हो रही वृद्धि के मद्देनजर तिलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके लिए जहां तिलहनी फसलों की खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर है तो दूसरी तरफ उन्नतशील प्रजातियों से उत्पादकता बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तिलहनी फसलों की उपज की खरीद गारंटी देने के साथ पाम के बागान लगाने पर भारी-भरकम सब्सिडी का प्रविधान किया जाएगा। इतना ही नहीं खाद्य तेलों की आयात-निर्यात नीति की भी समय-समय पर समीक्षा होती रहेगी।

पाम के बागान के लिए किसानों के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी की धनराशि जमा कराई जा सकती है। जल्दी ही पाम की खेती को प्रोत्साहन देने वाले पाम आयल मिशन को लांच किया जाएगा। मिशन को सफल बनाने के लिए इसके पहले चरण में 11 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसकी घोषणा पिछले दिनों किसानों से सीधी बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अगले पांच सालों में मिशन के नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल पाम बागान लगाने वाले किसानों को पेड़ों के तैयार होने और फल लगने तक तक चार से पांच सालों तक उसमें उपयोग होने वाली खाद पर शत प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। लांच होने वाले पाम आयल मिशन में सब्सिडी को और विस्तार मिल सकता है, जिसमें पाम किसानों को बाग लगाने और दूसरे खर्चों की भरपाई भी की जा सकती है। पाम की उपज के मूल्य का निर्धारण अन्य तिलहनी फसलों के फार्मूले पर ही की जाएगी, यानी खेती की कुल लागत से 50 फीसद अधिक मूल्य दिया जा सकता है।

उन्नत बीजों की आपूर्ति, रकबा बढ़ाने के साथ उत्पादकता पर जोर • फाइल फोटो

60 हजार करोड़ रुपये के खाद्य तेलों का होता है आयात : फिलहाल सालाना 60 हजार करोड़ रुपये मूल्य के खाद्य तेलों का आयात होता है। खाद्य तेलों के बढ़ते आयात पर चिंता जताते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि विदेशों में जाने वाली यह धनराशि किसानों की जेब में पहुंचनी चाहिए।

रिकार्ड पैदावार के बावजूद नहीं कम हुए दाम : खुदरा बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें 70 फीसद तक बढ़ चुकी हैं। इसी सप्ताह तिलहनी फसलों की पैदावार के अनुमान का ताजा आंकड़ा जारी किया गया है। इसके मुताबिक 3.61 करोड़ टन तिलहनी फसलों की पैदावार हुई है। पिछले फसल वर्ष के मुकाबले इस बार 73 लाख टन अधिक पैदावार हुई है। सोयाबीन को छोड़कर बाकी सभी तिलहनों की रिकार्ड पैदावार हुई है। हालांकि खाद्य तेलों की महंगाई पर इसका असर नहीं हो रहा है।

कुल्हड़ की खुशबू को अब घर-घर फैलाने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : इस स्वतंत्रता दिवस पर देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस खास मौके पर टाटा टी देश की कुल्हड़ परंपरा के प्रचार-प्रसार के लिए नई पहल करने जा रही है। कंपनी का मानना है, कुल्हड़ के प्रसार से कुम्हारों को आर्थिक मदद मिलेगी व हैंडीक्राफ्ट उद्योग प्रोत्साहित होगा। अलग-अलग राज्यों के लिए उनकी स्थानीय कला एवं परंपरा का कुल्हड़ पर चित्रण किया गया है ताकि उस राज्य के लोग आसानी से कुल्हड़ से कनेक्ट हो सकें। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पैकेज्ड बेवरेजेज (भारत और दक्षिण एशिया) के प्रेसिडेंट पुनीत दास ने बताया, भारतीय कारीगरों के काम को बढ़ावा देने वाला स्टार्टअप रेयर प्लैनेट के साथ मिलकर यह पहल की गई है। इन विशेष कुल्हड़ पर हर क्षेत्र के विशिष्ट कला रूपों के चित्र हाथों से रंगे गए हैं। जैसे बिहार की मधुबनी लोककला, महाराष्ट्र की वारली चित्रकला, पंजाब के फुलकारी पैटर्न, उड़ीसा के पटचित्र तो उप्र की सांझी कला। दिल्ली की शान में विशेष कुल्हड़ बनाए गए हैं। हर कलाकार ने अपने हाथों से बनाए हुए चित्रों से इन कुल्हड़ों को सजाया है। देश के कुल्हड़ कलेक्शन में 26 प्रकार के अलग-अलग कुल्हड़ शामिल हैं। इस पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के एक डिजिटल फिल्म भी जारी की गई है। कुल्हड़ों की बिक्री से मिलने वाली राशि के अलावा भी टाटा टी की तरफ से कुल्हड़ बनाने वाले कारीगरों की मदद की जा रही है। कुल्हड़ की बिक्री पूरी तरह से आनलाइन होगी।

टाटा टी द्वारा तैयार किया गया कुल्हड़ • सौ. टाटा कंपनी

चीन के निन्बो पोर्ट के बंद होने से बढ़ सकती है निर्यात की लागत

राजीव कुमार • नई दिल्ली

कोरोना संक्रमण के नए मामले मिलने के बाद चीन में स्थित दुनिया के तीसरे बड़े निन्बो पोर्ट को बंद कर दिया गया है। इससे भारतीय निर्यात की लागत बढ़ने की आशंका है। विश्व भर के लगभग 25 फीसद कंटेनर के इस पोर्ट पर जमा होने से कंटेनर की लागत भी बढ़ जाएगी। इस पोर्ट से भारत आने वाले कई प्रकार के कच्चे माल की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। पोर्ट से आने वाले माल को दूसरे रूट से भेजने पर लागत बढ़ेगी। भारत में इस पोर्ट से टेक्सटाइल उत्पाद से जुड़े कच्चे माल के साथ इलेक्ट्रानिक्स आइटम से संबंधित माल आता है। बता दें कि इससे पहले शिनजिन से आर्थिक गतिविधियां बंद करने से कई प्रकार के कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हो गई थी।

दूसरे मार्ग से माल भेजने पर बढ़ेगी कीमत • फाइल फोटो

निर्यातकों का कहना है कि निन्बो पोर्ट के बंद होने से दुनिया भर की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। कन्फेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सिटी) के पूर्व अध्यक्ष संजय जैन कहते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि यह पोर्ट कितने दिनों तक बंद रहता है। अगर अगले एक-दो दिनों में खुल जाता है तो खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे समय के लिए बंद रहने पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। निर्यातकों ने बताया कि जनवरी 2021 में मुंबई के नावा शेवा से 40 फुट के कंटेनर में कैलिफोर्निया के लांग पोर्ट पर माल भेजने की लागत 5500 डालर थी जो अब 11,500 डालर है। निन्बो पोर्ट के बंद होने से कंटेनर किल्लत होगी और लागत निश्चित रूप से बढ़ेगी। भारत में कंटेनर का निर्माण नहीं होने से निर्यातकों को पूरी तरह से विदेश से आने वाले कंटेनर पर माल भेजने के लिए निर्भर रहना पड़ता है।

निर्यातक शरद कुमार सराफ ने बताया कि निन्बो पोर्ट के बंद होने से चीन में भारतीय माल को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जा रहा है और उसका खर्च भी हमें ही उठाना पड़ रहा है। चीन में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और वहां कारोबार की स्थिति खराब हो रही है।

और महंगी होगी विमान यात्रा

नई दिल्ली, प्रेट्रः नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराये की निचली व ऊपरी सीमा में 9.83 से 12.82 फीसद तक की वृद्धि की है। इससे घरेलू हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी। इससे पहले पिछले साल पांच मई को विमान सेवाओं के बहाल होने के साथ सरकार ने उड़ान अवधि के आधार पर हवाई किराये पर निचली और ऊपरी सीमाएं लगाई थीं। यात्रा प्रतिबंधों के चलते आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहीं एयरलाइनों की मदद के लिए निचली सीमा लगाई गई थी। जबकि ऊपरी सीमा इसलिए लगाई गई थी ताकि सीटों की मांग अधिक होने पर यात्रियों से ज्यादा शुल्क ना वसूला जा सके।

> सरकार ने घरेलू सेवा के किराये की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 से 12.82 फीसद तक की वृद्धि की है

मंत्रालय ने 40 मिनट की अवधि की उड़ानों के किराये निचली सीमा को 2,600 रुपए से बढ़ाकर 2,900 रुपए कर दिया, यानी 11.53% की वृद्धि हुई है। वहीं 40 मिनट की अवधि की उड़ानों के लिए ऊपरी सीमा को 12.82% बढ़ाकर 8,800 रुपए कर दिया गया। इसी तरह, 40-60 मिनट की अवधि वाली उड़ानों के लिए निचली सीमा अब 3,300 रुपए के बजाय 3,700 रुपये होगी। गुरुवार को इन उड़ानों के किराये की ऊपरी सीमा 12.24 प्रतिशत बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दी गई। 60-90 मिनट की अवधि वाली उड़ानों के किराये की निचली सीमा 4,500 रुपए होगी, यानी इसमें 12.5% की वृद्धि की गई है। गुरुवार को इन उड़ानों के किराये की ऊपरी सीमा 12.82% बढ़ाकर 13,200 रुपए कर दी गई। अब 90-120, 120-150, 150-180 और 180-210 मिनट की अवधि की घरेलू उड़ानों के किराये के लिए क्रमशः 5,300 रुपए, 6,700 रुपए, 8,300 रुपए और 9,800 रुपए की निचली सीमा होगी। जबकि 120-150 मिनट की अवधि की उड़ानों के किराये की निचली सीमा 9.83% बढ़ाकर 6,700 रुपये कर दी गई है।

राष्ट्रीय फलक

सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी में मरम्मत के दौरान तीन श्रमिकों की मौत

राज्य ब्यूरो, अहमदाबादः पोरबंदर के पास स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी में मरम्मत कार्य के दौरान हादसा हो गया। इसमें तीन श्रमिकों की मौत हो गई। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने जिलाधिकारी से फोन पर बात कर घायल श्रमिकों की आवश्यक मदद करने का निर्देश दिया है।

पोरबंदर के पास राणावाव स्थित हाथी सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी में गुरुवार को मरम्मत का काम चल रहा था। यह सीमेंट फैक्ट्री अभिनेत्री जूही चावला के पति की है। घटनास्थल पर 48 श्रमिक काम कर रहे थे। चिमनी में 45 मीटर की ऊंचाई पर रंग रोगन का काम चल रहा था। श्रमिक जिस पर खड़े होकर काम कर रहे थे, अचानक वह टूट गया। इससे मजदूर नीचे आकर गिर गए। इसके चलते तीन मजदूरों की मौत की खबर है। हादसे में अन्य श्रमिकों के भी जख्मी होने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे तथा फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी राहत एवं बचाव कार्य के लिए बुलाया गया।

200 हत्याओं का आरोपित छैमार गैंग का सरगना गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा

▸ उप्र समेत कई राज्यों में डकैती, हत्या की वारदात कर चुका है

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में दर्जनों लोगों की हत्या करने वाले छैमार गिरोह के सरगना फाती उर्फ कदीम को उप्र एसटीएफ की आगरा इकाई ने गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ का दावा है कि फाती गिरोह द्वारा विभिन्न राज्यों में 200 लोगों की हत्याएं कर चुका है। कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका पर्दाफाश नहीं हुआ। वह कन्नौज के थाना तिर्वा के गांव बिनौरा का रहने वाला है। वर्तमान में हापुड़ के थाना गढ़ के गांव दौतई में रह रहा था। सरगना ने पूछताछ करने पर बताया कि उसे खुद नहीं पता कि वह अब तक कितनों को मार चुका है। एसटीएफ को शुरुआती छानबीन में उसके खिलाफ 15 मुकदमे मिले हैं। इनमें आधा दर्जन डकैती के दौरान हत्या के हैं।

एसटीएफ आगरा इकाई के इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह ने बताया कि छैमार गिरोह के सरगना फाती का नाम 1997 में जयपुर में डकैती के दौरान सात लोगों की हत्या में सामने आया था। जिन लोगों की हत्या हुई, उनमें दो बच्चे भी थे। मौके से पकड़े गए एक बदमाश ने फाती और उसके तीन भाइयों के डकैती में शामिल होने की जानकारी दी थी। सरगना ने बताया कि वह 15 दिन में गैंग बना सकता है। अन्य राज्यों व जिलों से सरगना के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी गई है।

इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह ने बताया कि छैमार गिरोह के सरगना के आगरा में डेरा डालने की जानकारी मिली थी। एसटीएफ ने उसे टीपी नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। सरगना ने बताया कि वह जगह बदलने के साथ ही नाम भी बदल देता था। उसके फाती उर्फ कदीम उर्फ अशद खान उर्फ पहलवाान उर्फ बबलू उर्फ मोनिस आदि नाम हैं। गिरोह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका है। उसे 2016 में एसटीएफ की लखनऊ इकाई ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। वह फर्जी जमानत पर बाहर आ गया था। एसटीएफ के अनुसार सरगना फाती के खिलाफ जौनपुर थाने के शाहगंज थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। सरगना पर 25 हजार रुपये का इनाम था।

महिलाओं से कराते हैं रेकी: पुलिस को पूछताछ में सरगना कदीम ने बताया कि जिस शहर में वारदात करनी होती है, वहां पर कई महीने पहले डेरा डालते हैं। इसके बाद महिलाओं से कालोनियों में रेकी करवाते हैं। महिलाएं भीख मांगने के बहाने रेकी करती हैं। इसके लिए वह हर दिन अलग-अलग देवी-देवताओं की तस्वीरें अपने पास रखते हैं। घरों में डकैती के दौरान विरोध करने वाले की हत्या करने में नहीं हिचकते हैं। वह खुद भी लोगों की हत्याएं कर चुका है।

बिरयानी के प्रचार में हिंदू संत का चित्र इस्तेमाल करने पर आक्रोश

बेलगावी (कर्नाटक), आइएएनएस : यहां के एक होटल ने बिरयानी के प्रचार में हिंदू संत के चित्र का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई। इनका कहना है कि मांस और चावल के इस पकवान को बेचने के लिए जिस तरह होटल ने हिंदू संत के चित्र का सहारा लिया, वह निंदनीय है।

यहां के नियाज होटल ने इंटरनेट मीडिया में पोस्टर अपलोड किया जिसमें एक हिंदू संत का चित्र इस्तेमाल किया गया और वे भक्तों से कहते हैं कि उन्हें बलिदान नहीं, बिरयानी चाहिए। उन्हें बिरयानी की तारीफ करते हुए दिखाया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने इसे हिंदू परंपरा का अपमान बताया। उन्होंने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन दिया और होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनके समर्थन में भाजपा के स्थानीय नेता भी उतरे। पुलिस ने आनन-फानन में सभी होटलों को बंद करा दिया। बाद में होटल प्रबंधन ने विवादास्पद पोस्टर के लिए माफी मांगी।

सात साल की मासूम की 24 साल के युवक से करा दी शादी

संवाद सूत्र, उदयपुर

▸ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का मामला, दूल्हा और पंडित सहित छह गिरफ्तार

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सात साल की मासूम की शादी 24 साल के एक युवक से कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने दूल्हे व पंडित सहित छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

जिले के कपासन थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि मामले की जांच में पता चला कि राजसमंद जिले के सरदारगढ़ निवासी राकेश माली की शादी नहीं हो रही थी। भूपालसागर निवासी पंडित बसंतीलाल ने उसे सलाह दी थी कि उसकी शादी नाता प्रथा के जरिये ही संभव है, लेकिन इसके लिए उसका विवाहित होना जरूरी है। इसके लिए पंडित की सलाह पर उसके स्वजन ने एजेंटों के जरिये उसकी शादी किसी मासूम से कराने की कोशिश शुरू की। पिछले महीने 18 तारीख को राकेश के स्वजन ने चित्तौड़गढ़ जिले में एक गांव के दंपती को पैसों का लालच देकर उसकी शादी किसी मासूम से कराने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद आरोपितों ने मिलकर सात साल की बच्ची का अपहरण किया और मंदिर में ले जाकर उसकी शादी राकेश से करा दी। बाद में उन्होंने बालिका को गांव में लाकर छोड़ दिया। पीड़िता ने जब इस घटना की जानकारी अपने स्वजन को दी तो उसके दादाजी ने कपासन थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता के गांव के कालूराम तेली और उसकी पत्नी राधा देवी को नामजद करते हुए अन्य आरोपितों की तलाश शुरू कर दी। कालूराम और उसकी पत्नी के पकड़े जाने के बाद पुलिस दूल्हे और उसके स्वजन के साथ पंडित को भी गिरफ्तार करने में सफल रही। शुक्रवार को आरोपितों को अदालत में पेश किया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

घर के अंदर गोवध करना लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करना नहीं

जागरण संवाददाता, लखनऊ

▸ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया तीन आरोपितों पर लगा रासुका आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीतापुर के तीन लोगों के खिलाफ 14 अगस्त, 2020 को लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आदेश रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मान भी लिया जाए कि याचियों के घर के अंदर गाय के गोश्त के टुकड़े किए जा रहे थे तो उससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात तो मानी जा सकती है, किंतु लोक व्यवस्था बिगड़ने की बात नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि रासुका लगाने के लिए यह देखना जरूरी है कि अभियुक्तों के कृत्य से लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई हो। यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने इरफान, परवेज व रहमतुल्लाह की ओर से दाखिल तीन अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया।

पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपितों के घर पर गाय मार कर लाई गई है और वहां उसके मांस के टुकड़े किए जा रहे हैं। इस पर सीतापुर पुलिस ने छापा मारकर इरफान व परवेज को पकड़ा था। उन्होंने रहमतुल्लाह व दो अन्य के नाम बताए। बाद में रहमतुल्लाह भी पकड़ लिया गया। घटना की रिपोर्ट 12 जुलाई, 2020 को तालगांव थाने पर गोहत्या व अन्य अपराधों के आरोप में दर्ज की गई। बाद में याचियों पर गैंगस्टर भी लगा दिया गया। पुलिस व प्रशासन की रिपोर्ट पर 14 अगस्त 2020 को याचियों पर रासुका भी तामील करा दिया गया। इसी आदेश को याचीगणों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

कोर्ट ने याचिकाएं मंजूर करते हुए कहा कि किसी का अपने घर के अंदर चुपचाप गोवध करना कानून व्यवस्था का विषय तो हो सकता है, लेकिन इसकी ऐसी स्थिति से तुलना नहीं की जा सकती कि गोवध करने वाले आम लोगों पर हमला कर देते हों।

गुजरात के पूर्व डीजीपी समेत चार को जमानत

कोच्चि, एएनआइ : केरल हाई कोर्ट ने इसरो जासूसी मामले में गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार, केरल पुलिस के दो पूर्व अधिकारी एस. विजयन एवं थांपी एस. दुर्गा दत्त की जमानत मंजूर कर ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा दर्ज 1994 के इसरो जासूसी मामले में ये अधिकारी भी संलिप्त थे। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण की संलिप्तता वाले इस मामले में श्रीकुमार सातवें आरोपित हैं।

पिछले महीने 29 तारीख को सीबीआइ ने केरल हाई कोर्ट को सूचित किया था कि 1994 के इसरो जासूसी मामले में उसे पाकिस्तान समेत 'दुश्मन देशों' के शामिल होने का संदेह है। सीबीआइ ने पूर्व पुलिस अधिकारियों समेत 18 लोगों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में एफआइआर दर्ज की थी। जासूसी मामले के आरोपितों में जिन पुलिस अधिकारियों के नाम का उल्लेख किया गया है, उनमें विशेष जांच टीम (एसआइटी) के पूर्व प्रमुख सिबी मैथ्यू के साथ ही ए. विजयन, थांपी एस. दुर्गा दत्त, वीआर राजीवन और आरबी श्रीकुमार शामिल हैं।

लव जिहाद मामले में महिला ने बदला बयान

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

▸ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा, विवाह के लिए नहीं था कोई दबाव

▸ पति पर पहले लगाया था नाम बदलकर जान-पहचान बढ़ाने का आरोप

गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन (लव जिहाद) कानून के तहत दर्ज हुए एक मुकदमे में नया मोड़ आ गया है। शिकायतकर्ता महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है कि उस पर विवाह व मतांतरण का कोई दबाव नहीं डाला गया है। इसलिए उसकी ओर से 17 जून, 2021 को दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया जाए।

वडोदरा की एक महिला ने गौत्री पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने जबरदस्ती धमकी देकर फरवरी 2021 में विवाह करने तथा मतांतरण कराने का आरोप लगाया था। उसने यह भी बताया था कि आरोपित ने अपना असली नाम समीर कुरैशी छिपाकर सेम मार्टिन के नाम से इंटरनेट मीडिया पर उससे जान-पहचान बढ़ाई तथा उसके अश्लील चित्र भी खींच लिए। बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसने विवाह कर लिया। वडोदरा पुलिस ने इस मामले में कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया था तथा जिला सत्र अदालत ने आरोपित की जमानत याचिका ठुकरा दी थी। गुजरात में 15 जून, 2021 को अमल में आए गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन कानून के तहत दर्ज हुआ यह पहला मामला था। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में शिकायतकर्ता महिला ने अब यह एफआइआर रद करने की मांग की है। उसका कहना है कि उसके पति, ससुराल वालों व काजी पर लगाया गया आरोप गलत है। विवाह के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला गया तथा मतांतरण के लिए भी कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी।

अख्तर शेख ने खुद को महावीर गुप्ता बता की हिंदू महिला से शादी

श्रमिक परिवार की एक 22 साल की महिला ने लिंबायत सूरत में रहने वाले मुहम्मद अख्तर शेख (51) पर खुद के मुकेश महावीर गुप्ता होने व रेलवे में नौकरी की बात बताकर बरगलाने का आरोप लगाया है। वर्ष 2019 में इन दोनों ने हनुमान मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह कर लिया था। करीब डेढ़ माह पहले जब अख्तर का आधार कार्ड महिला के हाथ लगा तो उसने तुरंत उसे फोन लगाया। इस पर किसी मुन्नी नामक महिला ने फोन उठाया और खुद को अख्तर की पत्नी बताया। अख्तर इस पीड़ित महिला के साथ अलग फ्लैट लेकर रहने लगा था। महिला मोबाइल कंपनी में काम करती है तथा वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। अख्तर ने इस महिला को कुछ ग्राहक बनवाए, जिसके चलते उसने अपना निजी मोबाइल नंबर उसको दे दिया और इनके बीच करीबी बढ़ती गई। इन दोनों का एक बेटा भी है। पीड़िता का आरोप है कि अख्तर अब उसके बेटे को उससे दूर ले जाने की धमकी दे रहा है।

80 मीटर गहराई में गिरा है हेलीकाप्टर, निकालने में नहीं मिल रही सफलता

जागरण संवाददाता, कठुआ : रणजीत सागर झील में जहां सेना के हेलीकाप्टर गिरा है, उसका पता तो लगा लिया गया है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इसे निकालने में अब तक सफलता नहीं मिली है। गोताखोर या पानी में चलने वाला कोई भी उपकरण हेलीकाप्टर के मलबे तक नहीं पहुंच पा रहा है। सेना का यह हेलीकाप्टर तीन अगस्त को क्रैश होकर इसमें गिर गया था। हादसे के बाद से ही सेना का पायलट और सह पायलट लापता हैं। अभियान में शुक्रवार को एक बार फिर रणजीत सागर बांध परियोजना के दो जहाजों जय और विजय को झील में उतारा गया। सात स्टीमर भी उतारे गए। इसके बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ। शनिवार को भी तलाशी अभियान चलाया जाएगा।

रिमोट से संचालित वेहिकल्स से दो दिन पहले ही झील में गिरे हेलीकाप्टर का पता लगा लिया गया था। यह 80 मीटर नीचे गहराई में है। जहां भारी गाद है। सेना ने खुद इसका दावा किया था।

प्रतिभा और कुछ नहीं, सिर्फ कठिन परिश्रम है

बेतुका आरोप

राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को यह सामान्य समझ होनी ही चाहिए कि किसी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करना अनुचित है। ऐसा किया जाना किशोर न्याय अधिनियम के साथ-साथ जिस पाक्सो अधिनियम के तहत भी अनुचित है, वह तब बना था, जब केंद्र में कांग्रेस की ही सरैकार थी। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसियों को यह भी पता होना चाहिए कि किसी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में पहली बार कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा पहले भी किया जा चुका है और यदि कांग्रेसजन इससे अनभिज्ञ हैं तो यह उनकी नादानी ही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची के स्वजन की फोटो ट्वीट कर राहुल गांधी ने गलती की। कायदे से इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। कोई नहीं जानता कि उन्होंने गलती मानने के बजाय उस पर अड़ना क्यों बेहतर समझा? उनके अड़ियल रवैये के चलते ट्विटर के समक्ष उनके अकाउंट को लाक करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। उसने ऐसा ही किया। इसी के साथ पता नहीं कैसे कांग्रेसी नेताओं को यह आभास हो गया कि यह राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा जताने का सही समय है? उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के स्वजन की उसी फोटो के साथ धड़ाधड़ ट्वीट करने शुरू कर दिए। इसे हद दर्जे की चाटुकारिता और निम्न स्तर की मूर्खता के अलावा और कुछ कहना कठिन है।

किसी भी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी मूर्खता का भोंडा प्रदर्शन करने से बाज आना चाहिए, क्योंकि इससे वे हंसी के पात्र ही बनते हैं। हास्यास्पद यह है कि राहुल गांधी अब इस विचित्र आरोप के साथ सामने आ गए हैं कि ट्विटर ने सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसी तरह की बात प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेसी नेता भी कर रहे हैं और इससे परिचित होने के बाद भी कर रहे हैं कि कुछ दिनों पहले तक खुद केंद्रीय मंत्री ट्विटर को उसकी मनमानी के लिए कोस रहे थे। कुछ समय पहले जब ट्विटर ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लाक कर दिया था और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था, तब कांग्रेसजन मजे लेने के साथ सरकार पर तंज कस रहे थे। आखिर जो ट्विटर अपनी मनमानी से सरकार को तंग करता रहा हो, उसके बारे में कौन यह मानेगा कि वह सरकारी तंत्र के इशारे पर राहुल के खिलाफ काम कर रहा है? वास्तव में इससे बेतुका आरोप और कोई नहीं हो सकता कि सरकार के कहने पर ट्विटर ने राहुल और अन्य कांग्रेसियों का अकाउंट लाक किया।

सुधार की कोशिश

मध्याह्न भोजन योजना से शिक्षकों की मुक्ति का निर्णय लेकर बिहार सरकार ने सुधार की एक बेहतर कोशिश की है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन को पटना जिले के कुछ विद्यालयों के बच्चों के लिए मिड-डे मील तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रयोग सफल रहने पर इसे प्रदेशभर में लागू किया जाएगा। दरअसल सरकार को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि प्रदेश के 72 हजार प्रारंभिक विद्यालयों के एक करोड़ 70 लाख बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था में शिक्षकों के लगे होने से पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही थी, शिक्षा के स्तर में भी यथोचित सुधार नहीं हो रहा था। भोजन योजना के संचालन में तकरीबन 3.25 लाख शिक्षक जुड़े थे। स्थिति से चिंतित राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में व्याप्त खामियों को दूर करने और शिक्षकों को इससे अलग रखने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। इससे एक ओर जहां शिक्षकों का फोकस शिक्षण कार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सुनिश्चित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर बच्चों को बेहतर भोजन और पौष्टिक नाश्ता मिल सकेगा। अभी तक जिन राज्यों में यह प्रयोग किया गया है, वहां सफल रहा है। अक्षय पात्र रसोई में एक साथ 50 हजार बच्चों का खाना तैयार किया जाएगा। बच्चों को भी गर्म खाना दिया जाएगा। फाउंडेशन द्वारा फिलहाल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु में अक्षय पात्र रसोई का संचालन किया जा रहा है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की मंशा साफ है कि बच्चों को बेहतर भोजन मिले तथा शिक्षक अपने मूल कार्य पर ध्यान दे सकें। शैक्षिक स्तर के सुधार में गंभीरता से जुटी सरकार ने दूसरी तरफ प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बगैर सूचना दिए गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से गैरहाजिर शिक्षकों के बारे में प्रत्येक दिन का ब्योरा सभी जिलों से मांगा है। कोरोना महामारी के कारण लंबी अवधि के बाद स्कूल खुले हैं। ऐसे में शिक्षकों की सौ फीसद उपस्थिति सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। साफ है, ऐसे निर्णय हर हाल में बच्चों के लिए तभी लाभकारी साबित हो सकेंगे जब संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। शिक्षकों पर सिर्फ पढ़ाने का जिम्मा होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी।

आवश्यक मुद्दे पर भारत का ध्यानाकर्षण

विवेक काटजू

सुरक्षा परिषद बैठक की अध्यक्षता के दौरान मोदी ने न सिर्फ सामुद्रिक सुरक्षा के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि महासागरों की महत्ता भी समझाई

बीते नौ अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने 'सामुद्रिक सुरक्षा को बढ़ाना-अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक केस' विषय पर अपना अध्यक्षीय संबोधन दिया। वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में वैश्विक महत्व के इस विषय पर दुनिया के अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन, केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शामिल रहे। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का दायित्व अगस्त में भारत के पास रहेगा। परिषद के एजेंडे को निर्धारित करने में अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे अन्य सदस्यों विशेषकर पांच स्थायी सदस्यों को साधना पड़ता है।

अधिकांश भारतीयों के लिए सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना एक साझा चिंता है। विशेषकर उत्तरी सीमा से सटे राज्यों पर यह बात और प्रभावी ढंग से लागू होती है। ऐतिहासिक रूप से भारत में आक्रांताओं ने खैबर और बोलन दर्रों के जरिये ही घुसपैठ की है, जो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करते हैं। हमारे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पर इसकी छाप है। उन आततायियों की कटु स्मृतियां आज भी भारतीय मानस पटल पर अंकित हैं। वहीं अंग्रेज समुद्री मार्ग से व्यापारी के वेश में आए और बाद में आक्रांता बन गए। इसके बाद ही हमारी चेतना में यह बात बैठी कि समुद्री सीमाओं से भी देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यहां तक कि स्वतंत्रता के बाद भी भारत की सुरक्षा को स्थल सीमा से ही संकट झेलने पड़े। इन सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन हमें परेशान करते रहे। हम यह भी नहीं भूल सकते कि भारत 7,516 किमी लंबी तट रेखा वाला देश है। इस सीमा से लगे सागर अवसरों की खान होने के साथ ही चुनौतियों का सबब भी हैं।

मोदी को इसका श्रेय जाता है कि वह भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में सामुद्रिक मोर्चे की महत्ता पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने न केवल सामुद्रिक सुरक्षा के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि भारतीयों को भी देश के राष्ट्रीय जीवन में महासागरों की महत्ता समझाई। अपने संबोधन में वैश्विक सामुद्रिक सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मोदी ने पांच महत्वपूर्ण बिंदु गिनाए। उन्होंने समुद्री व्यापार की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा। उन्होंने आह्वान किया कि वैधानिक व्यापार की राह में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सभी देशों की समृद्धि वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही पर निर्भर करती है। एक

अवधेश राजपूत

बेहद उल्लेखनीय बिंदु की ओर संकेत करते हुए मोदी ने यथार्थ ही कहा कि देशों के बीच किसी भी सामुद्रिक विवाद का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, पर उनका इशारा उसकी ही ओर था, जो दक्षिणी चीन सागर में दूसरे देशों पर दबंगई दिखा रहा है। मोदी ने सभी देशों से आह्वान किया कि वे उन शरारती तत्वों के खिलाफ मुहिम छेड़ें, जो समुद्रों में खतरे पैदा करते हैं। इनमें खास तौर से वे समुद्री दस्यु शामिल हैं, जो न सिर्फ जहाजों से सामान चुरा लेते हैं, बल्कि फिरौती के लिए उनका अपहरण भी कर लेते हैं। मोदी ने महासागरों से उपजी प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अहमियत का भी उल्लेख किया। एक अन्य बिंदु सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर केंद्रित था, जिसके लिए सामुद्रिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से बचना होगा। उन्होंने महासागरों में तेल के रिसाव और प्लास्टिक के जमावड़े से जुड़े खतरों की ओर भी सही संकेत किया, जिसके सामुद्रिक जीवन पर बेहद खतरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का अंतिम बिंदु भी चीन पर निशाना साधने वाला रहा। उन्होंने कहा कि बंदरगाह जैसे समुद्री कनेक्टिविटी से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास में देशों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जहां उन्हें विकसित किया जा रहा है वहां संबंधित देश ऐसे ढांचे को समायोजित कर सकते हैं या नहीं? यह बात चीन के संदर्भ में सटीक बैठती है, जो विभिन्न देशों में बंदरगाह और उनसे जुड़ी अवसंरचना विकसित कर रहा है। इसके कारण श्रीलंका जैसे कई देश उसके कर्ज जाल में फंस गए हैं। असल में ये परियोजनाएं आर्थिक रूप से उतनी फलदायी नहीं होतीं और इन देशों के लिए चीन से लिए कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन वे अपनी परिसंपत्तियां चीन के हाथों गंवा बैठते हैं। स्वाभाविक है कि इससे मुश्किलें पैदा होंगी।

राष्ट्रपति पुतिन ने एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर अध्यक्षता को लेकर मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सामुद्रिक क्षेत्र को लेकर सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहना चाहिए। हालांकि समुद्रों को लेकर देशों के बीच विवाद सुलझाने के मसले पर पुतिन ने कहा कि इसका दारोमदार संबंधित देशों पर ही होना चाहिए। यह तो मौजूदा अंतरराष्ट्रीय पंचाटों वाली व्यवस्था से गंभीर विचलन है, जो इन विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई है। स्पष्ट है कि पुतिन चीन को कुपित नहीं करना चाहते थे, जो इन पंचाटों के फैसले को अस्वीकार करता आया है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर से जुड़े विवादों में वे बीजिंग के खिलाफ ही गए हैं। इसीलिए पुतिन ने संबंधित पक्षों के बीच संवाद की बात कही। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन का नाम न लेते हुए भी दक्षिण चीन सागर में उसकी गतिविधियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे देशों के खिलाफ है, जो दूसरे देशों और उनकी समुद्री संपदा के बीच बाधा खड़ी करते हैं। अनुमान के अनुसार बैठक में उपस्थित चीनी प्रतिनिधि ने दक्षिण चीन सागर के मामले में अमेरिकी हस्तक्षेप को आड़े हाथों लिया। यह भी उल्लेखनीय है कि इस बैठक में चीन का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में उसके राजदूत ने नहीं किया। भारत इस संकेत को बखूबी समझता है।

समुद्री सुरक्षा में वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सभी देशों द्वारा जिम्मेदारी का परिचय देते हुए अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान सुनिश्चित करने संबंधी मोदी का आह्वान बेहद महत्वपूर्ण और अत्यंत समीचीन रहा। बहरहाल दूसरे कई अंतरराष्ट्रीय मामलों की तरह इस पहल के भी चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता की ही भेंट चढ़ने के आसार हैं।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

भ्रष्टाचार पर तकनीक की लगाम

रमेश कुमार दुबे

सूचना प्रौद्योगिकी भ्रष्टाचार रोकने के साथ गरीबी निवारण का भी कारगर हथियार बन रही है

समय, श्रम और धन की बचत कर रही तकनीक। फाइल

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में भ्रष्टाचार की व्यापकता स्वीकारते हुए कहा था कि गरीबों के लिए भेजे जाने वाले एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही जरूरतमंदों तक पहुंच पाते हैं। आज दिल्ली से भेजे गए एक रुपये में पूरे सौ पैसे लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि भ्रष्ट तंत्र सुधर गया है। इसका श्रेय मोदी सरकार द्वारा हर स्तर पर बैठाए गए सूचना प्रौद्योगिकी रूपी चौकीदार को है, जिससे लीकेज प्रूफ नकद हस्तांतरण संभव हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल इंडिया अभियान पारदर्शी, भेदभाव रहित और भ्रष्टाचार पर चोट करने वाला है। इससे समय, श्रम और धन की बचत हो रही है। इससे सरकारी तंत्र तक हर आदमी की पहुंच बनी है। मात्र छह वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने कामयाबी की तमाम गाथाएं लिखी हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया की बदौलत कोरोना महामारी के इस डेढ़ साल में ही भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग सात लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण अर्थात डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक खातों में भेजा। केवल भीम यूपीआई से ही हर महीने पांच लाख करोड़ रुपये का लेन-देन हो रहा है। अब तो सिंगापुर और भूटान में भी भीम यूपीआई के जरिये लेन-देन होने लगा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक लाख 35 हजार करोड़ रुपये दस करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजा गया।

डिजिटल इंडिया ने वन नेशन-वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। ई-नाम के जरिये देश के किसान अब तक 1,35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन कर चुके हैं। किसानों से होने वाली सरकारी खरीद का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाने लगा है। इसी तरह छात्रवृत्ति, गैस सब्सिडी, राशन कार्डों को आधार से जोड़ने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। यदि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण व्यवस्था न होती तो केंद्र सरकार से आम लोगों को दिए गए इन लाखों करोड़ रुपये में से अधिकांश धन बिचौलिये हड़प लेते। प्रधानमंत्री ने अलग-अलग सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए 2017 में यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फार न्यू एज गवर्नेंस (उमंग) लांच किया था। इस एप पर 2084 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 194 सरकारी विभागों की योजनाएं हैं। इस एप के डाउनलोड करने के बाद अलग-अलग सेवाओं का लाभ लेने के लिए कई तरह के एप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रह जाती। यह डिजिटल इंडिया की ही देन है कि ड्राइविंग लाइसेंस हो या जन्म प्रमाण पत्र, बिजली का बिल भरना हो या पानी का, आयकर रिटर्न दाखिल करना, अब ये सब काम आसानी से हो रहे हैं। गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों को ये सुविधाएं उनके घर के पास स्थित जन सेवा केंद्रों में उपलब्ध हैं। देश के हर गांव पंचायत में जन सेवा केंद्र खोले गए हैं, ताकि ग्रामीणों को जरूरी कामों के लिए तहसील या जिला मुख्यालय न जाना पड़े।

2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में 75 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, जिसके 2025 तक 90 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। भले ही देश की इतनी बड़ी आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती हो, लेकिन इसकी कई सीमाएं हैं, जिससे इसका समुचित लाभ देश को नहीं मिल पा रहा है। भारत में 90 प्रतिशत इंटरनेट मोबाइल पर चलता है। इसमें 88 प्रतिशत लोग 4जी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इससे इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। दूसरे, देश के 40 करोड़ लोगों तक अभी इंटरनेट की पहुंच नहीं है। शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता और स्पीड, दोनों कम हैं। ग्रामीण इलाकों में बैंडविथ संबंधी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल लाल किले की प्राचीर से एक हजार दिनों के भीतर छह लाख गांवों में भारत नेट कार्यक्रम के माध्यम से ओएफसी ब्राडबैंड लगाने का एलान किया था। इसके तहत सबसे पहले 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को आप्टिक फाइबर केबल के जरिये हाई स्पीड ब्राडबैंड किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। 31 मई, 2021 तक 1,56,223 ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड क्रांति को गति देने की यह महत्वाकांक्षी योजना है।

इंटरनेट के बहुआयामी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत छह करोड़ ग्रामीणों को कंप्यूटरों और डिजिटल उपकरणों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये छह करोड़ लोग देश के 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों से लिए जाएंगे। आगे चलकर सरकार एक लाख डिजिटल गांव बनाएगी, जहां विभिन्न जन केंद्रित सुविधाएं गांवों में ही मिल जाया करेंगी। इससे गांव-शहर के बीच की डिजिटल खाई पाटने में मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया क्रांति की भांति वाई-फाई क्रांति का आगाज हो चुका है। इसके लिए प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) शुरू की गई है। यह योजना ई-गवर्नेंस और फिर मोबाइल गवर्नेंस (एम गवर्नेंस) की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इसके तहत सभी को मुफ्त में वाई-फाई सुविधा मिलेगी। किसानों को सीधे बीज, खाद, कीटनाशक, उपकरणों आदि की जानकारी मिलेगी और वे अपनी उपज ई-मंडी के माध्यम से कहीं भी बेच सकेंगे। सरकार की योजना देश की 2700 कृषि उपज मंडियों और 4000 उप-बाजारों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) से जोड़ने की है।

फिलहाल ई-नाम प्लेटफार्म पर 1000 कृषि उपज मंडियां, 1.73 करोड़ किसान, व्यापारी और कृषि उत्पादक संगठन जुड़े हैं। जल्दी ही 1000 और कृषि उपज मंडियां ई-नाम से जुड़ जाएंगी। समग्रतः मोदी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी को भ्रष्टाचार रोकने और गरीबी निवारण का कारगर हथियार बना रही है।

(लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं)

response@jagran.com

चिंता और चिंतन

चिंता मनुष्य का एक गंभीर विकार है। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती है। यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन भर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से युक्त रहता है। एक कहावत है कि चिंता चिता के समान है। चिंता ग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव हो जाता है। चिंता से व्यक्ति इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसमें घिरा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मनोविकारों और रोगों से घिरने लगता है।

जीवन को सकारात्मक गति देने के लिए मनुष्य को चिंता न करके चिंतन करना चाहिए। चिंता से जहां मन अशांत रहता है वहीं चिंतन से मन में एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। चिंतन जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई न कोई सुगम मार्ग अवश्य मिल जाता है। वास्तव में चिंता ही चिंतन को जन्म देती है। जब व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त होता है तभी वह उस समस्या के बारे में चिंतन करता है और चिंतन से समस्या का समाधान निकालता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह चिंता, डर, लोभ, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, करुणा आदि मानवीय प्रवृत्तियों से युक्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों से बिना घबराए इनका सामना करे और आगे बढ़े।

भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य की चिंता व्यर्थ बताई है। उन्होंने वर्तमान में जीने को सर्वोचित बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। वह कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है फल पर नहीं। अतः हमें चिंता से उबरने के लिए उस चिंता के विषय में चिंतन करना चाहिए। चिंतन ही चिंता समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है, उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता है।

डा. मनोज कुमार मिश्र

बच्चों पर न डालें उम्मीदों का बोझ

चंदन कुमार चौधरी

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, जिसमें स्कूलों का माहौल खुशनुमा हो सके

संसद में हाल में पेश राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के एक आंकड़े के मुताबिक देश में वर्ष 2017-19 के बीच 14-18 आयु वर्ग के 24 हजार से अधिक बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से खुदकुशी करने वाले बच्चों की संख्या 4,046 है। निश्चित रूप से यह संख्या बहुत अधिक है, जो परेशान करने वाली है। इस पर समय रहते हुए लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो हालात भयावह हो सकते हैं। माना जाता है कि किशोर अक्सर आवेग में आकर आत्महत्या की कोशिश करते हैं। कुछ किशोर आत्महत्या को समस्याओं का हल मान लेते हैं जो कहीं से सही नहीं है। ऐसे में यह अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों के मनोभाव को ठीक से समझें और उसका उचित और तर्कपूर्ण समाधान निकालें, ताकि देश के नौनिहालों का जीवन सुरक्षित रह सके।

असल में जब बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराया जाता है तभी से अभिभावक उनकी उम्र, क्षमता को भूल कर अपनी उम्मीदों का सारा बोझ उनके कंधे पर लादने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। उस समय अभिभावक भूल जाते हैं कि बच्चों के नाजुक कंधे उनकी उम्मीदों का बोझ उठाने में सक्षम हैं भी या नहीं। फिर यहीं से शुरू होता है बच्चों के पास और फेल होने का खेल। हमें समझना होगा कि बच्चों का मन नाजुक होता है। उनके नाजुक मन पर अंकित होने वाली कोई भी बात जीवन भर उनके साथ रहती है। हमारा मकसद भले ही कुछ हो, लेकिन हम जाने-अनजाने इस मामले में गलत आकलन करके बच्चे पर पास या फेल का ठप्पा लगा बैठते हैं। इसके बजाय हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि बच्चों में तर्क आधारित सोच को कैसे बेहतर बनाया जाए। बच्चों को सिखाने का बेहतर तरीका यही है कि हम खेल-खेल में उन्हें समझाएं और बताएं। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों और घरों पर अभिभावकों को बच्चों की क्षमता पर टिप्पणी और किसी अन्य बच्चों के साथ उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। भले ही यह बात छोटी और सामान्य लगे, लेकिन बाल मन पर इसका बहुत ही गंभीर और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, जिसमें स्कूल का माहौल सकारात्मक और खुशनुमा हो सके। जब हम बच्चों पर उम्मीदों का बोझ डालते हैं तो फिर दिनों-दिन उनके नाजुक कंधों पर बोझ बढ़ता जाता है। और यही बोझ उनके लिए एक दिन काफी नुकसानदेह साबित होता है, जो उन्हें खुदकुशी की ओर ले जाता है। अगर हम बच्चों पर उम्मीदों का बोझ नहीं डाल, उन्हें चिंता मुक्त कर उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार कर सामने लाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वे समाज के एक जिम्मेदार सदस्य बन सकेंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

नई शिक्षा नीति का महत्व

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'सक्षम पीढ़ी तैयार करने वाली शिक्षा नीति' शीर्षक लेख में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही इस नीति की मुख्य बातों का उल्लेख किया है, जो कि सराहनीय है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालना वह भी ऐसे समय में जब पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा हो, एक चुनौती पूर्ण कार्य है। हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे समक्ष कई समस्याएं अभी भी विकराल रूप में खड़ी हैं। बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, कौशलविहीन श्रमिक, गुणवत्ताविहीन शिक्षा व्यवस्था आदि के कारण कई मामलों में हम आज भी वैश्विक पटल पर काफी पीछे हैं। शीर्ष वैश्विक शैक्षिक संस्थानों में हमारा न के बराबर प्रतिनिधित्व है। फलतः हम शिक्षा पद्धति को बदलकर ही अपना सफलतापूर्वक विकास कर सकते हैं। इसके लिए हमारी नई शिक्षा नीति-2020 एक बेहतरीन दस्तावेज है। इसमें हर स्तर की शिक्षा को ध्यान में रखा गया है। महत्वपूर्ण यह है कि छात्र अब अपनी रुचि के अनुसार गणित के साथ संगीत भी पढ़ सकते हैं, जो कि पहले की पद्धति में संभव ही नहीं था। पहले छात्र बोझ के रूप में कई विषयों को पढ़ते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति में छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। अब छात्र बीच में पढ़ाई छोड़कर कोई काम भी कर सकेंगे। बाद में हालात ठीक होने पर वे पुनः पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। अब पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों के कौशल विकास और प्रशिक्षण आदि पर भी विशेष जोर दिया गया है। इससे हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बेशक यह नई शिक्षा नीति कई उद्देश्यों को जेहन में रखकर तैयार की गई है। यदि यह पूर्णता से लागू हो जाती है तो हमारा नया भारत विश्व में पुनः ज्ञान का कीर्तिमान स्थापित कर सकेगा, जिसके लिए यह पूर्व में प्रसिद्ध था।

संदीप रौशन, प्रशिक्षु शिक्षक, समस्तीपुर, बिहार

सिसकता लोकतंत्र

इस मानसून सत्र में लोकसभा में लगभग 22 और राज्यसभा में 28 फीसद ही कामकाज हो पाया, शेष कार्य विपक्ष ने धो डाला। इसमें करदाताओं के करोड़ों रुपये स्वाहा हो गए। आखिरकार संसद को स्थगित करने के बजाय विपक्ष ने सरकार से कोरोना महामारी पर गंभीर व सार्थक बहस क्यों नहीं की? महंगाई, बेरोजगारी आदि पर कठिन सवाल पूछ कर सरकार को क्यों नहीं घेरा गया? निश्चित ही विपक्ष पर गंभीर प्रश्न तो उठेंगे। क्या तथ्यात्मक रूप से आधारहीन पेगासस स्पाइवेयर परिपक्व राजनीति का आधार हो सकता है? मानसून सत्र में संसद चलाने के बजाय विपक्षी सांसदों द्वारा केवल ध्यानाकर्षण के लिए साइकिल व ट्रैक्टर को चलाया गया वो भी बिना अनुमति और नंबर प्लेट के। कुछ सांसदों द्वारा सदन में प्रवेश के लिए शीशे के द्वारों को तोड़ना, संसदकर्मी का घायल होना, संसद के कैमरों में कैद महिला व पुरुष मार्शलों से हाथापाई व कर्मियों को चोटें आना, सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर चढ़ कर हंगामा करना, रूल बुक को सभापति की चेयर पर फेंकना, इसे माननीय सांसदों की उद्दंडता कहें या हुल्लड़बाजी। ये यकीनन लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार व कलंकित करती नजर आईं। सदन में सीटियां बजाना क्या संसद में एक आदर्श स्थिति हो सकती है? विपक्ष का आरोप है कि सरकार सदन में सुनती है और न ही बोलने देती है, तब विपक्ष के नेतागण ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) संशोधन बिल पास करवाने पर सरकार से कंधा से कंधा मिलाकर कैसे खड़े थे? दूसरा, जब विपक्ष संसद में इतना उग्र हो सकता है तो ये कैसे संभव है कि अपनी बात नहीं कह पा रहा हो। निश्चित ही यह प्रकरण विपक्ष की अनर्गल व बेदम बातों की पोल खोलता है। विपक्ष के माननीय सांसदों के अमर्यादित आचरण से आहत राज्यसभा सभापति द्वारा वक्तव्य देते समय रुदन ऐसे लगा, जैसे भारतीय लोकतंत्र सिसकियां ले रहा हो। एक पत्रकार द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछने पर उसको ही सरकार का पोस्टमैन बताना निःसंदेह अहंकारी व अपरिपक्व राजनीतिक बयान लगता है। संसद में हंगामा, राजनीतिक मतभेद नहीं है, बल्कि मनभेद से परिपूर्ण कुत्सित, तुच्छ व आक्रोशित राजनीति की पराकाष्ठा है।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

2.2 प्रतिशत की कमी हुई है दुनियाभर में काम के घंटों में केवल बढ़ती गर्मी की वजह से। भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। मसलन वर्ष 1995 में भारत में काम के घंटों में 4.3 प्रतिशत की कमी आई थी, जिसके 2030 तक 5.8 फीसद तक बढ़ने की आशंका है।

आजकल

मनुष्य के लालच की कीमत चुका रही धरती

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

विकास की भी एक कीमत होती है। यह सभी को चुकानी होती है। लेकिन इसकी बड़ी कीमत धरती और इसके पर्यावरण को अदा करनी पड़ रही है। पर्यावरण पर जो असर हो रहा है, वह हम मनुष्यों पर ही आ रहा है, परंतु अभी हमने उसके बारे में सही से संज्ञान लेना नहीं सीखा है। जैसे हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन कोई सामान्य हादसा नहीं है। यही वह खतरा है, जिसकी ओर एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की छतरी तले काम कर रही सरकारी संस्था इंटरगवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) की हालिया रिपोर्ट में साफ संकेत किया गया है

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बीते दिनों पहाड़ दरकने की घटना से हमें प्रकृति संरक्षण का सबक लेना चाहिए। इंटरनेट मीडिया

इस बारे में अरसे से कहा जा रहा है कि हमारी यह धरती और इसका पूरा पर्यावरण औद्योगिक क्रांति के डेढ़ सौ बरस में ही इतना ज्यादा बदल गया कि वैसा कुछ पृथ्वी पर जीवन के विकास के हजारों साल लंबे इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका अहसास करीब 50 वर्ष पहले ही विज्ञानियों को हो गया था। इसकी एक गवाही करीब चार दशक पूर्व जेनेवा में आयोजित पहले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (क्लाइमेट कान्फ्रेंस) में मिली थी, जिसमें जुटे विज्ञानियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे तमाम बदलावों पर चिंता जताई थी। दो साल पहले कुछ वैसी ही चिंता दुनियाभर के 11,258 विज्ञानियों ने यह कहते हुए प्रकट की है कि अगर जल्द ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बनाई गई तो इंसान के विलुप्त होने तक का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जलवायु आपातकाल (क्लाइमेट इमरजेंसी) का वक्त आ गया है।

विज्ञान के एक जर्नल 'बायोसाइंस' द्वारा भारत समेत दुनिया के 153 देशों के 11,258 विज्ञानियों के बीच कराए गए शोध अध्ययन में कहा गया था कि पिछले 40 वर्षों में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और आबादी बढ़ने के साथ पृथ्वी के संसाधनों के अतिशय दोहन, जंगलों के कटने की रफ्तार बढ़ने, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और मौसम के पैटर्न में बदलाव से हालात सच में क्लाइमेट इमरजेंसी वाले हो गए हैं। अब आइपीसीसी की रिपोर्ट कह रही है कि बढ़ते तापमान से दुनिया भर में मौसम से जुड़ी और भी भीषण आपदाएं आएंगी।

सच तो यह है कि दुनिया पहले ही बढ़ते जलस्तर, बर्फ की चादरों के पिघलने और मौसम के अतिशय व्यवहार (एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस) जैसे बड़े और अपरिवर्तनीय बदलाव झेल रही है। अब खतरा यह है कि पर्यावरण सुधारने और उसे बचाने की कोई बड़ी कोशिश नहीं होने की स्थिति में पृथ्वी की सतह का औसत तापमान वर्ष 2030 तक ही डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। पहले के अनुमानों में बताया गया था कि यह बदलाव वर्ष 2040 तक होगा, लेकिन जिस तरह से धरती को गर्माने की प्रवृत्तियां तेज रफ्तार से बढ़ रही हैं, उन्हें देखते हुए ये आशंकाएं एक दशक पहले ही घटित होने लगेंगी। इतना ही नहीं, मौसम और पर्यावरण संबंधी जो परिवर्तन अभी हम देख रहे हैं, वे रफ्तार पकड़ते हुए अगले कुछ सौ वर्षों या संभवतः कई हजार साल तक जारी रह सकते हैं। आइपीसीसी की नई रिपोर्ट कई मायनों में प्रासंगिक है। एक तो यह इस साल नवंबर में ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सीओपी (क्लाइमेट चेंज कान्फ्रेंस आफ द पार्टीज) के सिलसिले में बदलती जलवायु का अंदाजा लेने वाली वर्ष 2013 के बाद पहली बड़ी रिपोर्ट है। इसमें पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा करने वाले कारकों और बदलावों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया गया है। इसलिए इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

आखिर क्या-क्या बदला है : समस्या पृथ्वी के संसाधनों के दोहन को लेकर इंसान के बढ़ते लालच की है। असल में मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन कर रहा है, लेकिन उसकी भरपाई का जरा भी प्रयास नहीं हो रहा है। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण इकाई (यूनेप) ने एक रिपोर्ट जारी करके आकलन दिया था कि धरती के दोहन की रफ्तार प्राकृतिक रूप से होने वाली भरपाई के मुकाबले 40 प्रतिशत तक ज्यादा है। यानी मनुष्य एक साल में जितने प्राकृतिक संसाधनों हवा, पानी, तेल, खनिज आदि का इस्तेमाल करता है, उतने संसाधनों की क्षतिपूर्ति में पृथ्वी को न्यूनतम डेढ़ साल लग जाता है। धीरे धीरे भरपाई के मुकाबले दोहन का प्रतिशत बढ़ता भी जा रहा है। आइपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि बीते दशकों के दौरान इंसानों ने अपनी बढ़ती आवश्यकताओं और तेज विकास की चाहत में धरती व उसके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर अपनी लापरवाही से ऐसे घाव बना दिए हैं कि इस कारण पर्यावरण की बिगड़ी सूरत को आगामी हजारों वर्षों में भी पहले जैसी स्थिति में पलटाया नहीं जा सकता है। मसलन, एक बड़ा बदलाव तो तापमान के रूप में ही हुआ है।

बीते दो दशकों में ही कारों की संख्या, फैक्ट्री के धुएं और कस्बों-शहरों में एयर कंडीशनरों के इस्तेमाल में इतनी तेज बढ़ोतरी हुई है कि इनसे पैदा ग्रीनहाउस गैसों ने तापमान को रिकार्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। इसका असर इस वर्ष अमेरिका-कनाडा के उन इलाकों में कीर्तिमान ध्वस्त करती गर्मी की शक्ल में दिखा जो इलाके आम तौर पर बर्फ से आच्छादित रहते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव गर्मी के कारण बर्फ की चादरों के पिघलने के रूप में हो रहा है। आर्कटिक और अंटार्कटिका की छीजती बर्फ पर हमारा ध्यान अक्सर दिलाया जाता है, पर इस बीच भारत समेत दुनियाभर के न जाने कितने ग्लेशियर (हिमनद) पिघलकर पूरी तरह गायब हो गए और हमें पता भी नहीं चला। एक बड़ा बदलाव समुद्र के बढ़ते जलस्तर के रूप में हुआ है। खतरा यह है कि दुनिया के कुछ समुद्र तटीय शहर पूरी तरह डूबने की कगार पर हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जैसे शहरों के बाशिंदों ने अपने लिए रिहाइश और कामकाजी जगहों की तलाश शुरू कर दी है। शायद उन्होंने मान लिया है कि पृथ्वी को इंसानी प्रकोप से बचाया नहीं जा सकता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि स्वयं के अस्तित्व को बचाने के वैकल्पिक प्रबंध कर लिए जाएं।

क्या टल सकती है त्रासदी : इसमें कोई शक नहीं कि पर्यावरण संकट से जुड़ी बुरी खबरें बहुत सी हैं और उम्मीद के टुकड़े बहुत कम। लेकिन दुनिया में पृथ्वी के वजूद को लेकर फैल रही चेतना का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। इसलिए सबसे पहले जिस उम्मीद को साकार करने की चेष्टा हो रही है, वह यह है कि किसी भी तरीके से वर्ष 2050 तक कुल कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाया जाए।

मुश्किल में किसान और बेहाल मध्यवर्ग

धरती के विनाश को न्योता दे रही पर्यावरण से जुड़ी त्रासदियां वैसे तो हर किसी को बेचैन कर रही हैं। अमीर हो या गरीब, हर किसी को इनमें अपने लिए कोई न कोई खतरा अवश्य नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत उन पर टूट रही है जो सीधे तौर पर अपनी आजीविका के लिए मौसम के रहमोकरम पर निर्भर रहते हैं। जैसे किसान, मजदूर और मध्यवर्गीय नौकरीपेशा जनता। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में रोजगार के लिए सबसे ज्यादा लोग (करीब 90 प्रतिशत) खेती और उन असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां दिहाड़ी पर यानी प्रतिदिन के शारीरिक श्रम के बदले मजदूरी मिलती है। ऐसे में निरंतर बढ़ती गर्मी, लू, उमस, अतिशय बारिश या बाढ़ के हालात में ये सारे कामकाज प्रभावित होते हैं। ऐसे में ये लोग या तो कई दिनों तक कोई काम ही नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्हें कामकाज के कुछ ही घंटे मिलते हैं। ये स्थितियां कोरोना काल से इतर हैं। कोरोना के दौर में तो इस श्रमिक तबके का संकट अपने शीर्ष पर पहुंच चुका है। लेकिन कोरोना के प्रकोप से पहले ही संयुक्त राष्ट्र अपनी एक रिपोर्ट में बता चुका है कि जलवायु परिवर्तन का असर खेती और निर्माण क्षेत्र (बिल्डिंग या सड़कें आदि) पर पड़ता है। गर्मी, लू, उमस या भारी बारिश में तो यह सेक्टर पूरी तरह ठप पड़ जाता है। यह रिपोर्ट एक आंकड़ा देकर बता चुकी है कि सिर्फ बढ़ती गर्मी की वजह से ही दुनिया भर में काम के घंटों में 2.2 प्रतिशत की कमी आई है। भारत पर इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मसलन, वर्ष 1995 में भारत में उत्पादक काम के घंटों में 4.3 प्रतिशत की कमी आई थी। चिंता की बात यह है कि वर्ष 2030 तक यह आंकड़ा 5.8 प्रतिशत तक बढ़ने की आशंका है।

ऐसे में यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि कामकाज प्रभावित होने से कंपनियों का उत्पादन घटता है, जिससे वे नौकरियों के अवसरों में कटौती करती हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मध्यवर्ग इससे कैसे प्रभावित होता है, तो इसका भी एक सटीक जवाब है। पहले तो गर्मी से बचाव के लिए मध्यवर्ग एयरकंडीशनरों और महंगी बिजली के इस्तेमाल को प्रेरित होता है। इससे उसकी जेब पर असर पड़ता है। इसके बाद इस तबके को नौकरी देने वाली कंपनियां भी जब अपनी घटती आमदनी के चलते बैलेंस शीट का संतुलन बिठाती हैं, तो वे छंटनी का तात्कालिक उपाय आजमाती हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन की एक परोक्ष मार मध्यवर्ग भी झेलता है। लिहाजा मध्यवर्ग को इन सभी पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए।

यह कैसे होगा। अगर कारों का निर्माण रोक दें, फैक्ट्रियां बंद कर दें, एयरकंडीशनरों और रेफ्रीजरेटरों को ठप कर दें, तो यह नतीजा पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं। लिहाजा जोर इस पर है कि जहां संभव है, तकनीक को बदल दिया जाए। जैसे बस-कारें-ट्रक जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की बजाय बिजली से चलें।

हमारा देश तकनीकी तौर पर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन समेत कई विकसित देशों ने इस बारे में समयसीमा तक निश्चित कर दी है। इसी के साथ साथ सौर, पवन और ज्वार ऊर्जा के क्षेत्र में हर दिन कुछ नया हो रहा है। भारत जैसे गर्म देशों के लिए सोलर एनर्जी एक बेहतर विकल्प है और इस बारे में खबरें ये हैं कि यह तकनीक दिनोंदिन सस्ती व पहले के मुकाबले एफिशिएंट (कार्यकुशल) हो रही है। यूरोप में कई ऐसे शहर विकसित किए जा रहे हैं जो शून्य कार्बन उत्सर्जन करते हैं या आगे चलकर ऐसे हो जाएंगे। यानी वहां आपको कहीं आवाजाही के लिए साइकिलें मिलेंगी या फिर बिजली से चलने वाली बसें-ट्रेनें। फैक्ट्रियों के धुएं को कार्बन सोखने वाली तकनीकों से लैस किया जा रहा है। यानी अगर उनके कार्बन डाईआक्साइड वाले धुएं को रोकना संभव नहीं है, तो यह किया जा रहा है कि वे फैक्ट्रियां कार्बन सोखने के सारे उपाय करें।

दोहन को थामना और विकास की गति पर अंकुश लगाना अगर पूरी तरह संभव नहीं है, तो तकनीकें हमारी इतनी मददगार हो ही रही हैं कि वे इससे होने वाले नुकसान की थोड़ी-बहुत भरपाई कर सकती हैं या फिर उसे न्यूनतम कर सकती हैं। यही वे उम्मीदें हैं जिनमें हमें अवश्यंभावी लग रही त्रासदी टालने वाली कुछ गुंजाइशें नजर आती हैं।

खरी-खरी

सदन में मूकाभिनय

गिरीश पंकज

सदन में एक-दूसरे के खिलाफ अंट-शंट असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते करते जब पक्ष-विपक्ष के लोग थक गए तो तय किया कि अब हमें अपनी आचार संहिता तय कर लेनी चाहिए। जितने भी अपमानजनक या असंसदीय शब्द हैं, उनसे परहेज करना चाहिए। आपस में कभी सहमत न होने वाले बंदे इस मुद्दे पर सहमत हो गए और तय किया कि अब किसी को झूठा नहीं बोलेंगे और न निकम्मा कहेंगे। चार सौ बीस, बेशर्म, हरामखोर तो बिल्कुल नहीं। किसी भी बात को बकवास नहीं कहेंगे। किसी को भ्रष्ट नहीं कहेंगे। किसी को खलनायक भी नहीं कहना। उसकी जगह महानायक बोल दो। भले ही सदन में नौटंकी होती है, लेकिन नौटंकी शब्द का प्रयोग भी नहीं करना।

तो तय हो गया कि अब हमें असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना। दूसरे दिन सदन में अध्यक्ष ने कहा, कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर क आप अपने विचार रखें। मिस्टर क खड़े हुए और इशारे से बात करने लगे। वह कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ हाथ लहरा थे। यह देख कर अध्यक्ष ने कहा, अरे, आप कुछ बोलिए तो! यह क्या नौटंकी कर रहे हैं? मगर उसके बाद भी मिस्टर क मूकाभिनय करते रहे। तब अध्यक्ष ने जोर से कहा, यह क्या बकवास कर रहे हैं?

अध्यक्ष का इतना बोलना था कि मिस्टर क ने कहा, माननीय अभी-अभी आपने नौटंकी और बकवास शब्द का प्रयोग किया। इन्हें कल ही असंसदीय करार दिया था। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। रही बात मूकाभिनय की, तो मैंने सोचा, अब तो बोलना ही कठिन हो जाएगा। जब भी मैं किसी मुद्दे पर बात करूंगा तो स्वाभाविक है कि कभी चवन्नी छाप बोल दूंगा। मुंह से महामूर्ख भी निकलेगा। बेईमान, निकम्मा, कमीशनखोरी, लफड़े आदि बगैर तो मैं क्या कोई भी कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए बेहतर है कि संकेतों में बात करूं और आप मेरे मन की बातें समझ जाएं। या फिर अपना प्रश्न लिखित में प्रस्तुत कर दूं।

मिस्टर क की बात सुनकर सब सोचने लगे, बंदा सही कह रहा है। फिर सभी ने तय किया कि ठीक है, जिसको जो बोलना है, वह बोले। जो असंसदीय शब्द मुंह से निकल जाएंगे, उसे अध्यक्ष कार्रवाई में शामिल ही नहीं करेंगे।

ट्वीट-ट्वीट

अफगानिस्तान को कब्जाने के लिए खून की होली खेल रहे तालिबान के पीछे पाकिस्तान है। एक बार तालिबानी वहां स्थापित हो जाएंगे, तब अनुमान लगाइए कि आइएसआइ उन्हें कहां लगाएगी? जाहिर है पाकिस्तान-चीन के साथ अब तालिबान भारत के लिए नया खतरा बनने जा रहा। किसी भुलावे में न रहें, ऐसा होगा। क्या हम इसके लिए सचेत हैं? क्या हम इसके लिए अपनी सुरक्षा तैयारी कर रहे हैं?
मनीष छिब्बर@maneeshchhibber

मेरा दिल अफगान की महिलाओं और लड़कियों के बारे में सोचकर बैठा जा रहा है, जिनके साथ तालिबानी अपने 'सेक्स गुलाम' जैसा बर्ताव करेंगे। यह मानव त्रासदी हमारी नजरों के सामने होने जा रही है। दुख की बात है कि दुनिया की बड़ी ताकतें ऐसा होते चुपचाप देख रही हैं।
साध्वी खोसला @sadhavi

सरकार बार-बार कह रही है कि अफगानिस्तान में खतरा है, इलाका छोड़ दो। पर वहां टिके कुछ भारतीय सुन नहीं रहे। जब हालात बेकाबू हो जाएंगे तब इराक और लीबिया की तरह रोना-पीटना करेंगे कि सेना के जवान और एयर इंडिया के हवाई जहाज भेजो। हद है।
अरुण बोथरा @arunbothra

राज्यसभा में धक्कामुक्की का शिकार महिला मार्शल का दर्द कौन बताएगा? नेता तो खुद को ही पीड़ित बताने में व्यस्त हैं।
अद्वैता काला@AdvaitaKala

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या ट्विटर के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत सही है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या विश्व समुदाय तालिबान पर दबाव बनाने में नाकाम साबित हो रहा है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

साजिश रचता जा रहा गुपचुप पाकिस्तान,
अश्रु खून के पी रहा अब अफगानिस्तान।
अब अफगानिस्तान दग रहे चहुंदिश गोले,
है अचरज की बात न दुनिया कुछ भी बोले!
पहुंचेगा इक रोज सभी तक आतंकी विष,
तब जानेगा विश्व तालिबानी ये साजिश।
– ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

बाहर नजर आने लगी है भीतरी खेमेबंदी

आलोक मिश्रा
स्थानीय संपादक, बिहार

राजनीतिक दलों की सक्रियता ही उनके जीवंत होने का प्रमाण है। सामान्य दिनों में अपनी ताकत बढ़ाने और विरोधियों की ताकत कम करने के लिए यह सक्रियता होती है। कभी-कभी जब बाहर के मोर्चे पर लड़ाई की गुंजाइश कम रहती है, तो दलों के भीतर ही जोर आजमाइश शुरू हो जाती है। बिहार में आजकल कुछ यही हाल चल रहा है। प्रतिद्वंद्वियों से उलझने का किसी के पास कोई सीधा मौका नहीं है, लिहाजा आपस में ही शक्ति प्रदर्शन जारी है। यह शक्ति प्रदर्शन सत्तारूढ़ दल जदयू और मुख्य विपक्षी दल राजद दोनों में जारी है।

पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार और संगठन दोनों के प्रधान थे। 10 महीने पहले उन्होंने संगठन के प्रत्यक्ष नेतृत्व से खुद को अलग कर लिया और विश्वस्त समझे जाने वाले रामचंद्र प्रसाद सिंह (आरसीपी सिंह) को संगठन का उत्तराधिकारी बनाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। सब ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन केंद्र में मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद घटनाक्रम बदलने लगा। जदयू की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह दोनों की दावेदारी थी, लेकिन मंत्री पद केवल आरसीपी के हाथ लगा। भरपाई के लिए ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। नीतीश कुमार कहते हैं कि ललन सिंह को अध्यक्ष बनाने की पेशकश खुद आरसीपी ने ही की थी। जबकि आरसीपी के करीबियों का दावा है कि उनकी इच्छा दोनों पदों पर रहने की थी। यह अलग बात है कि आरसीपी ने कभी अपनी इस इच्छा का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन नहीं किया। केंद्र में मंत्री बनने के तुरंत बाद उनका सार्वजनिक बयान यही आया कि जब कहा जाएगा, वह अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। किसी के मन में क्या है, इसके बारे में ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 31 जुलाई को जब नई दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय पद का हस्तांतरण हो रहा था तो आरसीपी खुश ही नजर आ रहे थे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह के पटना आगमन पर उमड़ी भीड़। जागरण आर्काइव

लेकिन सब कुछ ठीक नहीं रहा। अध्यक्ष बनने के छठे दिन ललन सिंह पटना पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद ही जदयू की आंतरिक खेमेबाजी टुकड़ों में बाहर आने लगी। ललन सिंह के स्वागत में भारी भीड़ जुटी। अब मंत्री बनने के बाद आरसीपी पहली बार 16 अगस्त को पटना आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए ललन सिंह से लंबी लकीर खींचने की तैयारी है। आरसीपी के समर्थकों की योजना है कि 16 अगस्त को ऐसी भीड़ जुटे कि तटस्थ प्रेक्षक ललन सिंह के स्वागत के लिए जुटी भीड़ से उसकी तुलना कर सकें। कह सकें कि ललन की तुलना में आरसीपी का स्वागत बेहतर रहा। यह गुटबाजी पोस्टर-बैनर में साफ झलकने लगी है। छोटे-मझोले नेता पोस्टर और बैनर में ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर न देकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जदयू में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार गुटबाजी की किसी संभावना से इन्कार करते हैं। यह भी 16 अगस्त को ही ठीक-ठीक पता चलेगा कि आपस में लोग सचमुच उलझ रहे थे या महज एक पखवाड़े की यह नूरा कुश्ती थी। संभव है कि उस दिन मंच पर सभी नेता गले मिलें और गुटबाजी के नाम पर एक दूसरे पर वार करने वाले कार्यकर्ता नीचे बैठ कर ताली बजाते रह जाएं।

मुख्य विपक्षी दल राजद में अक्सर अपनी हरकतों से असहज स्थिति पैदा करने वाले लालू के बड़े लाल तेजप्रताप फिर सुर्खियों में हैं। उनका निशाना फिर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बने हैं। हाल ही में भरी सभा में जगदानंद को हिटलर बता तेजप्रताप ने माहौल गर्म कर दिया है। खबर है कि जगदानंद इससे बुरी तरह आहत हैं और दफ्तर आने में उनकी दिलचस्पी नहीं रह गई है। यह पहली बार नहीं हुआ है कि तेजप्रताप ने जगदानंद पर अप्रिय टिप्पणी की है। इससे पहले भी कई बार वे जगदानंद को आहत कर चुके हैं। बीच में उनके पार्टी छोड़ने की खबर आने लगी थी, लेकिन लालू प्रसाद के मनाने पर वे मान गए थे। लेकिन इस बार ताज्जुब की बात यह भी है कि खुद लालू प्रसाद या विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अब तक उन्हें मनाने की कोशिश शुरू नहीं की है।

वैसे, तेजप्रताप को राजद या दूसरे दलों में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। फिर भी उनकी हरकतें विरोधियों को भले ही मनोरंजक लगें, लेकिन राजद पर अब भारी पड़ने लगी हैं। देखना है कि इस बार हालात सामान्य होते हैं या जगदानंद सिंह की नाराजगी पार्टी के लिए कोई दिक्कत खड़ी करती है।

मंथन

अखंड भारत के सपने का महत्व

प्रो. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता
सदस्य, बिहार विधान परिषद

भारतीय प्रायद्वीप के सभी देशों को एकीकृत करते हुए अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने का सपना आज भी प्रासंगिक है जिस पर हमारा चिंतन-मनन जारी रहना चाहिए

अखंड भारत में आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका आते हैं। इसे सांस्कृतिक भारत भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा विभाजन 15 अगस्त, 1947 को हुआ। इसलिए 14 अगस्त अखंड भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब अखंड भारत की बात होती है, तो भारत की अखंडता के ध्वजवाहक रहे महर्षि अरविंद के कार्यों एवं विचारों को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।

महर्षि अरविंद भारत विभाजन का हमेशा विरोधी रहे। 14 अगस्त, 1947 को उन्होंने राष्ट्र के नाम दिए संदेश में कहा था कि 'यह स्वतंत्रता तब तक अधूरी मानी जाएगी, जब तक भारत भूमि की अखंडता को पूर्ण नहीं बनाया जाएगा। हर राष्ट्र की एक आध्यात्मिक नियति है और भारत की नियति सदैव अखंड होने की है।' स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सरदार पटेल गृहमंत्री बने। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नेहरू सरकार में मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। सरदार पटेल एवं डा. मुखर्जी भारतीय परिवेश व संस्कृति में पले-बढ़े थे। इसलिए भारत के पुनर्निर्माण के विषय में उनकी दृष्टि अलग थी। आजादी के समय देश में 562 देसी रियासतें थीं। सरदार पटेल के प्रयासों के कारण ही वे भारत में शामिल हो सकी थीं। इनमें हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल आदि कुछ रियासतें ऐसी भी थीं, जो भारत में शामिल होना नहीं चाहती थीं। उन्हें भी सरदार पटेल ने ही भारत में शामिल होने के लिए बाध्य किया। उधर नेहरू के हस्तक्षेप के कारण जम्मू-कश्मीर भारत के लिए समस्या बना रहा, जिसका समाधान नरेंद्र मोदी सरकार ने अब जाकर किया।

दरअसल भोपाल रियासत ने पहले संप्रभु एवं स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। वहां एक मुस्लिम नवाब हमीदुल्ला खान अधिसंख्यक हिंदू आबादी पर शासन करता था। उसने माउंटबेटन को लिखा कि वह एक स्वतंत्र रियासत चाहता है, किंतु माउंटबेटन ने उससे कहा कि कोई भी शासक अपने नजदीकी अधिराज्य से भाग नहीं सकता है। जुलाई 1947 तक जब अधिकांश राजाओं ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया तो अंततः भोपाल के नवाब ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी प्रकार गुजरात में स्थित एक रियासत जूनागढ़ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू एवं शासक मुस्लिम था। 15 सितंबर, 1947 को वहां का नवाब मुहम्मद महाबत खानजी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। उसने तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है। तत्कालीन भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे और भयावह रूप धारण कर लेंगे। साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या, जो कि 80 प्रतिशत है, इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण भारत सरकार ने जनमत संग्रह से विलय के मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव रखा। फरवरी, 1948 में जनमत संग्रह कराया गया, जो सर्वसम्मति से भारत में विलय के पक्ष में गया।

हैदराबाद सबसे बड़ी एवं समृद्ध रियासत थी, जो दक्कन पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। इसकी अधिसंख्यक आबादी हिंदू थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली शासन करता था। उसने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। उसने जिन्ना से मदद का आश्वासन प्राप्त किया था। परिस्थितियां तब भयावह हो गईं, जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदातें शुरू कर दीं। 13 सितंबर, 1948 को भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया। चार दिन तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। बाद में नेहरू की तुष्टीकरण वाली नीति के कारण निजाम के आत्मसमर्पण पर उसे पुरस्कृत करते हुए हैदराबाद राज्य का गवर्नर बनाया गया। नेहरू की तुष्टीकरण वाली नीति के कारण ही आगे चल कर इन रियासतों को जोड़ने के क्रम में देश के भीतर कुछ नए प्रविधान, कुछ नए कानून बनाए गए। जैसे अनुच्छेद 370, जो बाद में देश के लिए अभिशाप साबित हुए। अन्य कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी तुष्टीकरण की नीति पर चलते रहे और इसी कारण भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा मिला। कांग्रेस ने भारतीय समाज को धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर बांटा। नक्सलवाद का प्रणेता चारु मजूमदार हो या खालिस्तान का जनक भिंडरांवाले का जन्म भी कांग्रेस के शासन काल में ही हुआ। इसमें एक विषय और आता है कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत की अहम भूमिका रही, लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश को हमने स्वाधीन कराया, वह हमारा मित्र देश नहीं बन पाया। इसी कारण आज अपने देश के भीतर घुसपैठ के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इंदिरा गांधी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया, लेकिन उस आजादी के कारण भारत को क्या मिला, यह भी चिंतन का विषय है।

हिमालय के चारों ओर के निकटतम देश अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं। फाइल

2014 के बाद से मोदी सरकार ने भारत की एकता एवं अखंडता के लिए जो कार्य किया है, उसे आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। आज के परिवेश में यह बहुत ही जरूरी है कि युवा वर्ग को राष्ट्र की सर्वोपरिता का पाठ पढ़ाया जाए।

8 आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है बिहार के भागलपुर जिले में हुए सृजन घोटाले के मामले में। इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। सीबीआइ इस मामले में अब तक करीब दो दर्जन मुकदमे दर्ज कर चुकी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 अगस्त, 2021

बंगाल

कैदियों की रिहाई से जुड़े सवाल

ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से जेलों में भीड़ कम करने के लिए मानवीय आधार पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे अच्छे आचरण वाले कैदियों को सजा पूरी होने के पहले रिहा करने का निर्णय लिया है। पिछले दो अगस्त को राज्य सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे 63 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की थी। इसके बाद गुरुवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 73 और ऐसे कैदियों को मुक्त करने का फैसला किया गया है। दो अगस्त को ममता सरकार की ओर से रिहाई को लेकर जो लिखित बयान जारी किया गया था, उसमें लिखा गया था कि 51 हिंदू और 12 मुस्लिम कैदियों को रिहा किया जा रहा है। साथ में यह भी उल्लेख किया गया कि इनमें पांच अनुसूचित जाति, तीन अनुसूचित जनजाति, दो अन्य पिछड़े वर्ग और 53 सामान्य जातियों के कैदी हैं। इसे लेकर भाजपा की ओर से सवाल उठाया गया कि क्या ममता सरकार अपराधियों का भी जाति-धर्म देखती हैं? यह क्यों बताया गया कि इतने हिंदुओं और इतने मुस्लिमों को रिहा किया जा रहा है? अपराधी आखिर अपराधी होते हैं। उनका कोई जाति-धर्म नहीं होता। फिर इस तरह से वर्गीकरण क्यों? यह सवाल अहम है। अगर किसी सरकार की ओर से लिखित बयान में यह कहा जाए कि इतने हिंदू और इतने मुस्लिम अपराधी हैं तो इसे लेकर सियासत होना लाजिमी है।

दो अगस्त को सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे 63 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की थी। गुरुवार को फिर सीएम ने कहा कि 73 और ऐसे कैदियों को मुक्त करने का फैसला लिया गया है

कैदियों को रिहा करना विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर लिया गया फैसला है, क्योंकि बंगाल की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। ऐसे में अगर कोरोना महामारी को लेकर कैदियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया है तो यह अच्छी बात है। शुरुआत में जेल विभाग ने नियमों का अनुपालन करते हुए 350 कैदियों के नामों की सिफारिश की थी, लेकिन सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने 38 नामों का चयन किया। इस पर ममता सरकार ने असंतोष जताया था। उसके बाद रिहा होने वाले कैदियों की संख्या में वृद्धि की गई इसीलिए राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के तहत जिन आजीवन सजा प्राप्त कैदियों ने कम से कम 14 साल सजा की अवधि पूरी कर ली है तथा कैद के दौरान जिनका आचरण अच्छा रहा है, उन पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया है। इसी कारण 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष और 55 साल से अधिक उम्र की महिला कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में कैदियों की रिहाई में धर्म-जाति का रंग लगाने से सरकार को बचना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश

आपदा से बचाव

पहाड़ भूकंप और भूस्खलन की दृष्टि संवेदनशील होते हैं। इसलिए पूर्व आपदा प्रबंधन किए जाने जरूरी होते हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अन्य प्राकृतिक आपदाएं जख्म देती रही हैं। भारी बर्फबारी, अग्निकांड और भूस्खलन से यहां पर हर साल जानमाल का काफी नुकसान होता है। पहाड़ों के टूटने के संदर्भ में पूर्व आपदा प्रबंधन राज्य की प्राथमिकता में नहीं रहा है। हमीरपुर और ऊना जिलों को छोड़ दें तो सभी जिलों में पहाड़ टूटन व भूस्खलन से जख्म मिलते रहे हैं। कटिंग, बारिश और भूकंप से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सर्वेक्षण के नाम पर भी औपचारिकता निभाई जाती है। पहाड़ों पर परियोजनाएं धड़ाधड़ बनाई जा रही हैं, लेकिन पर्यावरण संतुलन की तरफ कितना ध्यान है, यह साल दर साल होने वाले हादसे साफ तौर पर बताते हैं। वैश्विक ताप बढ़ना अलग बात है, लेकिन राज्य में क्या इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, इस पर मंथन किया जाना जरूरी है? कुछ साल पहले तक जनजातीय जिलों में हरियाली नहीं होती थी, लेकिन अब वहां पर कई बगीचे लहलहा रहे हैं। कई जगह बड़े बड़े जंगल खड़े हो गए हैं। इन क्षेत्रों में बारिश

पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा से बचाव के लिए प्राकृतिक संरक्षण पर देना होगा जोर। फाइल

मानवीय दखल से कमजोर हो रहे पहाड़ों को बचाने के लिए धरातल पर ठोस प्रयास होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस दिशा में हमें प्रयास तेज करना होगा

नाम मात्र और बर्फबारी खूब होती थी। इसका प्रभाव भी पहाड़ों पर पड़ा है। विज्ञानी मानते हैं कि हिमाचल के पहाड़ अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। पहाड़ों पर गिरी बर्फ धीरे-धीरे पिघल कर नदियों में पानी के रूप में जाती थी, लेकिन अब इन क्षेत्रों में बारिश होने के कारण पानी पहाड़ों के बीच जा रहा है। इस कारण यहां से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। जिन क्षेत्रों में खनन हुआ है या पहाड़ों से छेड़छाड़ हुई है वहां पर ये खिसक रहे हैं। पहाड़ों पर परियोजनाएं स्थापित करने से पूर्व कई तरह की शर्तें होती हैं, लेकिन इनका कितना पालन होता है यह वहां पर पहाड़ों की कटिंग और नदियों के किनारे फेंके गए मलबे को देखकर पता चलता है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के बारे में लोगों को सचेत करने की दिशा में भी कोई प्रयास नहीं दिखते हैं। नीति नियंताओं के लिए आवश्यक है कि वे आपदा प्रबंधन के बजाय पूर्व आपदा प्रबंधन पर अधिक सोचें। इस दिशा में जल्द कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में स्थिति गंभीर हो सकती है।

झारखंड

पुलिस का सराहनीय कार्य

रांची के ओरमांझी में सिरकटी लाश की गुत्थी सुलझाने वाले पुलिस अफसरों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार ने टीम में शामिल अफसरों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेडल देने की घोषणा की है। वाकई यह मामला पुलिस तफ्तीश का बेहतर उदाहरण है। इस मामले में युवती की पहचान बड़ी चुनौती थी। पुलिस को सिर ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जांच के दौरान सुराग और संभावनाओं की कड़ियां एक-दूसरे से जोड़ते हुए पुलिस अपराधी तक पहुंच गई। इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस पर खासा दबाव भी था। रांची में विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा था। ऐसे में पुलिस ने धैर्यपूर्वक अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए बेहतर काम का उदाहरण पेश किया था। देशभर में ऐसे जटिल मामलों को सुलझाने वाले अफसरों का हौसला बढ़ाकर केंद्र सरकार ने भी सराहनीय काम किया है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अब ये अफसर और पुलिस विभाग समेत संबंधित राज्य के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं। हाल के दिनों में पुलिस ने

न्याय दिलाने में पुलिस की होती है अहम भूमिका। प्रतीकात्मक

फारेंसिक जांच समेत अनुसंधान के आधुनिक तरीकों का बेहतर इस्तेमाल किया है। इस अभ्यास को और भी कुशल तरीके से आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। सभी मामलों को सुलझाने में पुलिस को ऐसी ही तत्परता और कुशलता दिखानी होगी।

बेहतर अनुसंधान का उदाहरण पेश करने वाले पुलिस अफसरों को सम्मानित किया जाना सराहनीय है

धनबाद में जज की हत्या के मामले में अभी पुलिस से लेकर सीबीआइ तक के हाथ खाली हैं। हाई कोर्ट इसकी लगातार मानिटरिंग कर रहा है। अदालत ने जांच के प्रति असंतोष जाहिर किया है। जटिल मसलों को सुलझाने के लिए अनुसंधान टीम को लगातार खुद को अपग्रेड करना होगा। अपराध के मामलों में दोषियों का न पकड़ा जाना या पकड़े जाने के बाद भी छूट जाना पीड़ित पक्ष के प्रति अन्याय जैसा है। उन्हें न्याय दिलाने में पुलिस की भूमिका बड़ी है। पुलिस का कुशल व सक्षम होना समाज और देश को मजबूती देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जज हत्या की जांच के मामले पर ही टिप्पणी करते हुए पुलिस की जांच के तरीके और संपूर्ण कार्यशैली में सुधार की जरूरत बताई है। इसके निहितार्थ को समझना होगा।

उत्तराखंड

विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी चिंता का विषय है। इस कमी को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। हालांकि इन सबके बीच सरकार द्वारा संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियां सकारात्मक माहौल बना रही हैं। उत्तराखंड में चिकित्सकों की कमी काफी पहले से ही महसूस की जा रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर नहीं कर पाई है। स्वास्थ्य विभाग के ढांचे पर नजर डालें तो राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए 1144 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष प्रदेश में अभी 493 ही विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं। इनमें से भी अधिसंख्य चिकित्सक मैदानी जिलों में तैनात हैं। इनमें भी कई चिकित्सकों को प्रशासनिक पदों पर तैनात किया गया है तो किसी को अन्य काम दिया गया है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों से विशेषज्ञता का ही काम लिया जाए। हाल ही में शासन ने इनमें से 22 चिकित्सकों का तबादला अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान में किया है। इनमें कई विभागों के चिकित्सक शामिल हैं। एक साथ इन चिकित्सकों के तबादले से दून व हल्द्वानी के अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी हो गई है। सरकार का यह कदम सही है, पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सक जरूर तैनात करने चाहिए, मगर इसके साथ ही सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मैदानी जिलों के अस्पतालों में इनकी कमी न हो। कारण यह कि दूरदराज से इलाज कराने के लिए मरीज मैदानी जिलों के अस्पतालों में ही आते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह मैदानी जिलों में इन तबादलों के सापेक्ष रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती के लिए जल्द कदम उठाएं, ताकि यहां भी मरीजों को उचित इलाज मिल सके। मैदानी जिलों में पद खाली रहेंगे तो पर्वतीय जिलों में तैनात अन्य चिकित्सक मैदानी जिलों में आने के लिए जोर मारेंगे। पद भरे हुए होंगे तो हर जगह व्यवस्था सुचारू चलेगी। संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए यह जरूरी भी है कि सभी अस्पतालों में चिकित्सक हों। सरकार का फोकस अब सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी है। स्वास्थ्य उपकरण व दवाओं की खरीद हो रही है। सरकार को चाहिए कि इन सबके साथ यहां पर्याप्त चिकित्सकों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करे। इससे मरीज को इन्हीं केंद्रों में उचित इलाज मिल सकेगा और उन्हें इलाज के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी चिंता का विषय है। इस कमी को दूर करने के लिए सार्थक प्रयास करने की जरूरत है

अभिषेक-शृंगार के बाद चांदी के हिंडोले पर विराजे रामलला

जागरण संवाददाता, अयोध्या

रामलला को शुक्रवार को ब्रह्ममुहूर्त में चांदी के हिंडोले पर स्थापित किया गया। हिंडोले में रामलला के साथ भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के विग्रह को भी स्थापित किया गया। रामलला सावन पूर्णिमा यानी 22 अगस्त तक हिंडोले पर रहेंगे और सुबह-शाम जब वे भक्तों को दर्शन देंगे, उस दौरान अर्चक हिंडोले की डोर खींच कर उन्हें झुलाते रहेंगे।

21 किलो चांदी का यह हिंडोला दिल्ली के विशेषज्ञ कारीगर द्वारा तैयार कराया गया है। तीन फीट ऊंचा, इतना ही लंबा और दो फीट चौड़ा यह हिंडोला आकार-प्रकार में रामलला की उम्र के अनुरूप है और इसमें कलात्मकता का पूरा ध्यान रखा गया है। झूले के शिखर पर आनंद और उल्लास के पर्याय थिरकते मोर को स्थापित किया गया है। दोनों ओर दो और मोर हैं, जो उत्सुकता से मध्य के थिरकते मोर की ओर देख रहे होते हैं।

हिंडोले में रामलला के ठीक ऊपर चांदी का ही छत्र संयोजित है। शुक्रवार को ब्रह्ममुहूर्त में भाइयों सहित रामलला के स्थापित होते ही हिंडोले की शोभा कई गुना बढ़ गई। इससे पूर्व रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्रदास ने सहयोगी अर्चकों के साथ रामलला का अभिषेक और शृंगार किया। तदुपरांत शंखनाद और वैदिक मंगलाचरण के बीच रामलला को हिंडोले पर स्थापित किया गया। हिंडोले पर रामलला की स्थापना उनके उस गौरव की वापसी से जोड़ कर देखी जा रही है, जिसकी शुरुआत नौ नवंबर, 2019 को सुप्रीम फैसला आने के साथ हुई थी और जिस निर्णय के बाद रामजन्मभूमि पर भव्य-दिव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। एक ओर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, दूसरी ओर रामलला का दरबार वैष्णव उपासना से जुड़े अनेक पर्वों एवं त्योहारों से सुशोभित होता जा रहा है।

अयोध्या में शुक्रवार को रामलला को नवनिर्मित रजत हिंडोले पर विराजमान कराया गया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विग्रह को भी हिंडोले पर स्थापित किया गया है। सौ. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट

84,600 वर्ग फीट की होगी राम मंदिर नींव की ऊपरी सतह

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

35 हजार 400 वर्ग फीट कम होगी ऊपरी सतह

प्राचीनकाल में राजाओं के किलों व नदियों पर बनने वाले बड़े बांधों की शैली में तैयार हो रही राम मंदिर नींव की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल नीचे की सतह से 35 हजार 400 वर्ग फीट कम होगा। इसे परत दर परत एक निश्चित पैमाने के आधार पर कम किया जा रहा है। नींव फिलिंग का कार्य पूरा होने के बाद यह शंक्वाकार दिखेगी। जब नींव की अंतिम लेयर ढल कर पूरी होगी तो इसकी ऊपरी सतह 84 हजार 600 वर्ग फीट की ही बचेगी। इसी आधार पर ही तराशे गए पत्थर बिछाए जाएंगे और फिर उसके ऊपर मंदिर आकार लेगा। इन पत्थरों को 12 से 15 फीट ऊंचाई तक लगाया जाना है।

मंदिर की नींव की निचली सतह एक लाख 20 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में है। इस सतह की लंबाई 400 फीट तथा चौड़ाई 300 फीट थी, जो ऊपरी सतह तक आते-आते 360 फीट लंबी तथा 235 फीट चौड़ी ही बचेगी। इससे पहले निचली सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल में 36 फीट नीचे तक खोदाई कर मलबा निकाला गया था। फिर पूरे क्षेत्र में नींव फिलिंग का कार्य शुरू किया गया। अब तक 32 लेयर ढाली जा चुकी हैं। कुल 44-45 लेयर ढाली जानी हैं। एक लेयर 12 इंच मोटी है, इस पर वाइब्रो रोलर चला कर इसको दो इंच दबाया जाता है। इस तरह एक लेयर की मोटाई 10 इंच ही बचती है। नींव की ढलाई पत्थर की गिट्टी व पाउडर, कोयले की राख, सीमेंट का निर्धारित अनुपात मिला कर इसी मैटेरियल से की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि परंपरागत निर्माण की शैली में नींव की निचली सतह ऊपरी सतह से हमेशा ही अधिक होती है। इससे नींव हमेशा मजबूत होती है और बनने वाला भवन कालजयी होता है।

विधायक निधि को सांसद की दिखा कार्य किए स्वीकृत, सांख्यिकी अधिकारी निलंबित

नईदुनिया, अंबिकापुर

- चेक बाउंस होने के बाद शिकायत पर शुरू हुई जांच, तब हुआ राजफाश
- अंबिकापुर के अलावा सीतापुर व लुंड्रा विधायक की मद भी की गई परिवर्तित

छत्तीसगढ़ में विधायक निधि को सांसद निधि मद में परिवर्तित कर सांसद कोटे से विकास कार्य की स्वीकृति देने का मामला सामने आया है। ऐसा करने वाले सरगुजा के जिला योजना व सांख्यिकी अधिकारी एसके तिर्की को निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 से 2019 तक तत्कालीन भाजपा सांसद कमलभान सिंह की सांसद निधि से 25 करोड़ रुपये स्वीकृत करने थे, लेकिन जिला और सांख्यिकी अधिकारी तिर्की ने नियम विरुद्ध 30 करोड़ से अधिक रुपये स्वीकृत कर दिए। अंतर की राशि को समायोजित करने के लिए उन्होंने अंबिकापुर विधायक व मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की विधायक निधि के तीन करोड़ 97 लाख की राशि को स्थानांतरित कर दिया।

सीतापुर विधायक व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अलावा लुंड्रा विधायक डा. प्रीतम राम के मद की राशि भी सांसद मद में समायोजित कर दी गई। विधायक सिंहदेव द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए जब चेक जारी हुए तो वे बाउंस होने लगे। इसके बाद इसकी शिकायत की गई। सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि शिकायत मिलने पर समिति बनाकर मामले की जांच कराई गई।

इसमें विधायक निधि की राशि को सांसद निधि में समायोजित करने की पुष्टि होने पर जिला योजना व सांख्यिकी अधिकारी एसके तिर्की को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच शुरू की गई है। निलंबित अधिकारी को आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। वर्तमान जिला सांख्यिकी अधिकारी लव कुमार त्रिपाठी विभागवार जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। गड़बड़ी की राशि और भी बढ़ने की संभावना है।

ऐसे की गड़बड़ी

जांच में पता चला है कि जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी एसके तिर्की अपने घर में कार्यालयीन चालू खाता का चेक बुक रखते थे। घर से ही संबंधित एजेंसी, ठेकेदार को स्वयं के हस्तलिखित चेक जारी करते थे। इससे संबंधित कोई नोटशीट का संधारण भी नहीं होता था। इसी कारण गड़बड़ी करते रहे।

श्रद्धा का महासावन

कण-कण में शिव

श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा गया है, 'अलंकार प्रियो विष्णु, अभिषेक प्रिया शिव' अर्थात भगवान विष्णु को अलंकृत होने में आनंद मिलता है, वह सदा सजे-धजे रहते हैं, किंतु शंकर जी मात्र अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। आप प्रतिदिन शिव जी पर ही जल चढ़ाते हैं। यदि विचारपूर्ण दृष्टि से देखें तो शिव क्या केवल मंदिर में हैं? नहीं, वह तो सारे संसार में व्याप्त हैं, प्रकृति के कण-कण में शिव हैं। उनकी देह इतनी विशाल है कि सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह भूमि उनके चरण हैं, और आकाश के नक्षत्र, तारागण आदि उनके गले के हार हैं। यदि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनका शरीर है तो इसके ऊपर जल की वर्षा स्वयं उनके सिवाय और कौन कर सकता है? श्रावण माह में जब बादल बरसते हैं, मानो संपूर्ण पृथ्वी का अभिषेक होता है, चारों ओर का वातावरण धुला-धुला और स्वच्छ हो जाता है, पृथ्वी खिल उठती है, भगवान शंकर मानो अपना अभिषेक स्वयं ही कर रहे होते हैं। इसी कारण सावन के महीने को शंकर जी की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस काल में सारी प्रकृति नाच उठती है, खिल उठती है और एक अलौकिक रस में डूब जाती है। जब प्रकृति परमात्मा के रस में डूबती है, मनुष्यों को भी उसमें डूबना आवश्यक है। प्रकृति के साथ एक होकर हमें भी उसके गान में डूबते चले जाना है। इसी कारण श्रावण मास में हमें शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए।

श्री श्री रविशंकर
संस्थापक, आर्ट आफ लिविंग

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

छह माह में हुनरमंद बनेंगे उत्तर प्रदेश के तीन लाख युवा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- कोविड संक्रमण नियंत्रण के लिए 41 हजार युवाओं को हेल्थ सेक्टर में मिलेगा रोजगार
- 25 जिलों में लगेंगे रोजगार दिलाने के लिए मेगा प्लेसमेंट शिविर

व्यावसायिक शिक्षा के साथ कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश (यूपी) के तीन लाख युवाओं को छह माह में हुनरमंद बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार की पहल से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उनकी आय बढ़ेगी और प्रदेश में विकास की गति तेज होगी। हेल्थ सेक्टर, आक्सीजन प्लांट आपरेटर और उद्योगों में युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की शुरुआत हो गई है।

युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के अवसर देने के लिए जल्द ही 25 जिलों में मेगा प्लेसमेंट शिविर भी लगाए जाएंगे। कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए 41 हजार से अधिक युवाओं को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट-क्रिटिकल केयर, कोविड फ्रंटलाइन वर्कर, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलाजी असिस्टेंट का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। 15 हजार युवाओं को आक्सीजन प्लांट आपरेटर के कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाना है। इस समय 371 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मार्च, 2022 तक 50 हजार अभ्यर्थियों को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर प्रशिक्षण छात्रों को पंजीकृत किया जाएगा। अब तक सरकार 10 हजार युवाओं को विभिन्न उद्योगों में अप्रेंटिसशिप करा चुकी है। सरकार की योजना रोजगार की उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देना है। राजकीय आइटीआइ के प्रशिक्षार्थियों को पहली बार आन-जाब-ट्रेनिंग का लाभ मिलने से बड़ा बदलाव आया है। मार्च, 2022 तक प्रदेश के राजकीय आइटीआइ के 10 हजार प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना है। उद्योगों से समन्वय और उसमें सहभागिता करते हुए 14,356 प्रशिक्षार्थियों को ड्यूल सिस्टम आफ ट्रेनिंग के तहत उद्योगों में शाप-फ्लोर पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इससे प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के बाद इन्हीं औद्योगिक इकाईयों में रोजगार मिल जाएगा।

नागपंचमी पर छड़ी मुबारक का पूजन

अमरनाथ यात्रा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा में हिस्सा लिया, सुख-समृद्धि की कामना की
- इस बार पवित्र छड़ी मुबारक 22 अगस्त को श्री अमरेश्वर गुफा में प्रवेश करेगी

दशनामी अखाड़ा स्थित श्री अमरेश्वर धाम में शुक्रवार को नागपंचमी पर श्री अमरनाथ की पवित्र छड़ी मुबारक का पूजन हुआ। करीब दो घंटे तक वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच छड़ी पूजन संपन्न हुआ। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा में भाग लेते हुए जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा और सुख समृद्धि के वातावरण की बहाली की कामना की।

दशनामी अखाड़ा के महंत एवं पवित्र छड़ी मुबारक के संरक्षक दीपेंद्र गिरी ने पूजा के बाद बताया कि 1990 से पहले तक श्रावण शुक्ल पक्ष की नागपंचमी के दिन श्री अमरेश्वर धाम में पूजा के बाद ही पवित्र छड़ी मुबारक के पवित्र गुफा के लिए प्रस्थान की परंपरा रही है। तब पूरी यात्रा पैदल होती थी। उन्होंने बताया कि इस बार पवित्र छड़ी मुबारक 22 अगस्त को श्री अमरेश्वर गुफा में प्रवेश करने के बाद सनातन परंपराओं के अनुरूप शिव की पूजा का विधान पूरा करेगी। उल्लेखनीय है कि समुद्रतल से करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में ही भगवान शंकर ने मां पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। पवित्र गुफा में श्रावण मास के दौरान भगवान शंकर, मां पार्वती और भगवान गणेश हिमलिंग स्वरूप में विराजमान होते हैं। भगवान शंकर द्वारा अमरत्व की कथा सुनाए जाने के कारण इस श्री अमरनाथ की गुफा को श्री अमरेश्वर गुफा भी पुकारा जाता है। बीते साल की तरह इस वर्ष भी कोविड-19 से उपजे हालात के कारण श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा को आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद रखा गया है। सिर्फ छड़ी मुबारक ही धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के लिए पवित्र गुफा में जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को दशनामी अखाड़ा स्थित श्री अमरेश्वर धाम में श्री अमरनाथ की पवित्र छड़ी मुबारक का पूजन किया। सूचना विभाग

18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर चाहेंगे तो उनकी तस्वीर सर्च इमेज से हटा दी जाएगी। गूगल ऐसा नया फीचर ला रहा है। फोटो हटाने का अनुरोध बच्चों के माता-पिता भी कर सकेंगे।

कंधार और लश्करगाह पर तालिबान ने किया कब्जा

अफगानिस्तान में सत्ता संग्राम ▸ भुतहा नजर आ रहा हेरात, चहुंओर बर्बादी के निशान

कंधार हवाई अड्डे पर सरकारी बलों का कब्जा बना हुआ है

काबुल, रायटर : अफगानिस्तान में तालिबान के आगे बढ़ने की तेज गति बरकरार है। शुक्रवार को कट्टरपंथी लड़ाकों ने देश के दूसरे बड़े शहर कंधार और एक अन्य बड़े शहर लश्करगाह पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि कंधार हवाई अड्डे पर सरकारी बलों का कब्जा बना हुआ है। कंधार शहर कंधार प्रांत की राजधानी है जबकि ऐतिहासिक शहर लश्करगाह हेल्मंद प्रांत की राजधानी है। तालिबान का दावा है कि उसने देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 14 पर कब्जा कर लिया है। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों पर उसका कब्जा पहले से ही है।

शुक्रवार को सरकार को बड़ा झटका देते हुए तालिबान ने प्रमुख शहर कंधार पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में कंधार का खास महत्व है। माना जाता है कि कंधार जिसके पास होता है वह ही अफगानिस्तान पर शासन करता है, क्योंकि यह देश का मुख्य व्यापारिक शहर है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसकी प्रांतीय सीमाएं पाकिस्तान व ईरान से लगती हैं। तालिबान के लिए यह शहर इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं पर उसका जन्म हुआ था। अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए मुल्ला उमर ने कंधार में ही तालिबान का गठन किया था।

छह लाख की आबादी वाले हेरात का भी अपना महत्व है। इस शहर पर गुरुवार को तालिबान ने कब्जा कर लिया। ईरान की सीमा के नजदीक का यह शहर हाल के दिनों में भुतहा नजर आने लगा है। यहां की सड़कों पर सन्नाटा है और चारों ओर बर्बादी के निशान। लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं या फिर वे घरों में छिपे हुए हैं। तालिबान और सरकारी बलों की लड़ाई में यहां पर भारी मार-काट और बर्बादी हुई है। हेरात का शेर कहे जाने वाले तालिबान विरोधी मिलीशिया के प्रमुख मुहम्मद इस्माइल खान को हिरासत में ले लिया गया है लेकिन उनके साथ किसी तरह की बदसलूकी होने की खबर नहीं है। उनकी मिलीशिया के सशस्त्र लड़ाके तालिबान से मिल गए हैं। सरकार ने भी मान लिया है कि दक्षिण का यह व्यापारिक केंद्र अब उसके हाथ से निकल चुका है। हालांकि देश के बड़े शहरों में शुमार मजार-ए-शरीफ और जलालाबाद पर सरकार का कब्जा बना हुआ है। राजधानी काबुल में भी सरकार मजबूती के साथ काबिज है लेकिन आशंकित विदेशी सरकारों ने वहां से अपने राजनयिकों और नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है।

सरकार समर्थक मिलिशिया प्रमुख हिरासत में

तालिबानी आतंकियों और अफगान सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। राजधानी काबुल के दक्षिण-पश्चिमी में कंधार सिटी में लड़ाई के दौरान उठता घना काला धुआं। एपी

घोर की राजधानी पर बिना लड़े कब्जा

घोर प्रांत की राजधानी फिरूज कोह का कब्जा बिना लड़ाई के ही तालिबान को मिलने की जानकारी मिली है। वहां पर तैनात सरकारी बल तालिबान के खौफ से भाग गए या फिर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। कला-ए-नाव के भी तालिबान के कब्जे में जाने की खबर है। कब्जे वाले सारे शहरों-कस्बों में तालिबान कड़े इस्लामी कानून लागू करता जा रहा है। इस कानून में चोर के हाथ काट लिए जाते हैं और घर से बाहर निकली महिला के शरीर का कोई हिस्सा दिखने पर उसे कोड़े लगाए जाते हैं।

इस महीने के अंत तक चले जाएंगे अमेरिकी सैनिक

तालिबान की भीषण आक्रामकता के मद्देनजर अमेरिका ने अपने सैनिकों की वापसी के कार्यक्रम को थोड़ा तेज किया है। माना जा रहा है कि अगस्त के अंत तक कुछ सौ सैनिकों को छोड़कर बाकी के अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान की धरती से चले जाएंगे। सहयोगी देशों के सैनिक भी पूरी तरह से चले जाएंगे। काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए तुर्की के सैनिक रह सकते हैं। उस पर अभी नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) में विचार चल रहा है। अफगानिस्तान में 20 वर्षों की तैनाती के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 11 सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी का एलान किया है। हालांकि अफगानिस्तान की बिगड़ रही स्थिति के बीच अमेरिका में उनके फैसले का विरोध शुरू हो गया है।

चमन में पाक सैनिकों और अफगानों में झड़प

तालिबान और सरकारी बलों के साथ चल रहे संघर्ष के बीच भागकर पाकिस्तान पहुंचे अफगान शरणार्थियों में से कई सौ वापस अपने घर आना चाहते हैं। लेकिन तालिबान अब उन्हें वापस आने नहीं दे रहे। स्पिन बोल्डक इलाके पर कब्जे के बाद तालिबान ने चमन से लगने वाली पाकिस्तानी सीमा से आवागमन रोक दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान वीजा मुक्त आवागमन की सुविधा दे तो यह सीमा खोली जा सकती है। लेकिन अफगानिस्तान जाने पर आमादा शरणार्थियों की शुक्रवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से झड़प हो गई जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है।

अपनों को निकालने में जुटे कई देश

▸ अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और कनाडा भेजे रहे सैनिक

वाशिंगटन, एएनआइ : अफगानिस्तान से अपने लोगों को सुरक्षित निकालने में अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कई देश जुट गए हैं। वे अपने नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षित निकासी के लिए सैनिक भेज रहे हैं।

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव जान किर्बी ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'तीन हजार सैनिक काबुल एयरपोर्ट भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा मदद के लिए एक हजार सैनिक कतर में मौजूद रहेंगे।' उन्होंने बताया कि कुवैत में भी साढ़े तीन हजार अमेरिकी सैनिकों को तैयार रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर इन्हें काबुल भेजा जा सकता है। यह सब काबुल में अमेरिकी दूतावास के स्टाफ और उन अफगान नागरिकों को निकालने के लिए किया जा रहा है, जिन्होंने 20 वर्ष चले संघर्ष के दौरान अमेरिकी सरकार की मदद की। इधर, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस ने बताया कि अफगानिस्तान से ब्रिटिश नागरिकों को निकालने के लिए करीब 600 सैनिक भेजे जाएंगे। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, कनाडा भी काबुल से अपने स्टाफ को निकालने के लिए एक विशेष बल भेजने जा रहा है। जबकि आस्ट्रेलिया भी इसी तरह का कदम उठाने जा रहा है। वह आस्ट्रेलियाई सैनिकों की मदद करने वाले अफगान लोगों को सुरक्षित निकालने में अमेरिका की मदद करेगा। आस्ट्रेलिया ने गत मई में ही काबुल स्थित अपने दूतावास को बंद कर दिया था और जून में अपने सैनिकों को बुला लिया था।

जान किर्बी। फाइल/ इंटरनेट मीडिया

पूर्व रक्षा मंत्री और एनएसए ने की बाइडन की आलोचना

समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री बाब गेट्स ने राष्ट्रपति जो बाइडन की विदेश नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वह हर बड़े मामले में गलत तरफ खड़े हैं। उन्होंने वाल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक लेख मे कहा कि वह अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाकर बड़ी गलती कर रहे हैं। जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) एचआर मैकमास्टर ने भी अफगानिस्तान से निकलने को लेकर बाइडन प्रशासन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह समय पाकिस्तान पर सख्त कदम उठाने का है।

अफगानिस्तान में फंसे जेएनयू छात्रों ने मांगी मदद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पढ़ने वाले तीन अफगानी छात्रों ने हिंसाग्रस्त इलाकों से सुरक्षित निकालने की गुजारिश की है। जेएनयू छात्रसंघ ने कुलपति प्रो. एम जगदेश कुमार को पत्र लिखकर छात्रों की मदद के लिए कदम उठाने की मांग की है।

पत्र में कहा गया है कि वर्तमान सत्र में दाखिला लेने वाले व सीनियर छात्र हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं। दूसरे विश्वविद्यालय छात्रों को वीजा दिलाने में मदद कर रहे हैं। जेएनयू को भी उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास करने चाहिए। जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आयशी घोष ने कहा कि अब तक तीन छात्रों ने मदद मांगी है, लेकिन यह संख्या बढ़ सकती है। सबसे अधिक डर छात्राओं को है। उन्हें पढ़ाई छूटने का भी डर सता रहा है। ऐसे में जेएनयू को चाहिए कि उनको बुलाकर छात्रावास में रुकने की व्यवस्था करे, ताकि वे पढ़ाई पूरी कर सकें।

जेएनयू की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में बड़ी संख्या में विदेशी छात्र हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या अफगानिस्तान की है। 2019 में 438, जबकि 2020 में 556 विदेशी छात्रों ने दाखिला लिया था। डीयू प्रशासन ने बताया कि कुल 101 देशों के छात्र दाखिला लिए थे। इनमें सर्वाधिक छात्र अफगानिस्तान के थे। इसके बाद बांग्लादेश और नेपाल का स्थान आता है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए 1324 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। अकेले अफगानिस्तान से 320 छात्रों ने आवेदन किया। हालांकि डीयू के फारेन स्टूडेंट रजिस्ट्री के डीन प्रो. अमरजीव लोचन ने कहा कि अब तक किसी छात्र ने वीजा आदि के लिए मदद नहीं मांगी है।

फिर पनप सकता है अल कायदा

▸ ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने कहा, बिगड़ रहे वहां के हालात

▸ ब्लिंकन बोले, अमेरिका अफगान सरकार के साथ

लंदन, प्रेट्र: अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में वहां पर आतंकी संगठन अल कायदा का फिर से मजबूत होना तय है। यह बात ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वैलेस ने शुक्रवार को कही।

वैलेस ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद ब्रिटिश राजनयिकों और अन्य नागरिकों को वहां से निकालने के लिए 600 सैनिक भेजे जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताते हुए ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने कहा, अल कायदा वहां पर फिर पनप जाएगा क्योंकि वापसी के लिए उसे अनुकूल स्थितियां उपलब्ध हो रही हैं। वहां भी वैसा ही होगा जैसा कि दुनिया के अन्य विफल राष्ट्रों में हो रहा है। अस्थिरता के चलते हमारी सुरक्षा और हमारे हितों के लिए खतरा पैदा होगा। अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री बोरिस जानसन ने भी सहयोगियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की है। कहा है कि सरकार घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। ज्ञात हो, अमेरिका के प्रमुख सहयोगी के रूप में ब्रिटेन के सैनिक भी करीब 20 साल अफगानिस्तान में रहे हैं।

एएनआइ के अनुसार, तालिबान की आक्रामकता से बिगड़ रहे हालात पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से शुक्रवार को टेलीफोन पर बात की। अमेरिका ने काबुल में मौजूद अपने नागरिकों की संख्या में कमी करने का निर्णय लिया है। ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका अफगान समस्या को वार्ता से हल किए जाने का पक्षधर है। इसके लिए वह पूरा सहयोग करने को तैयार है। अमेरिका अभी भी अफगान सरकार के साथ खड़ा हुआ है।

अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान को उकसा रहा पाक

▸ सुरक्षाबलों से जंग में आतंकियों के साथ मिलकर लड़ रहे पाकिस्तानी सेना के लोग

▸ आतंकियों के लिए धन के इंतजाम के साथ ही राजनयिक मदद भी मुहैया करा रहा है

काबुल, एएनआइ : आतंकवाद पर दुनिया भर में बेनकाब हो चुके पाकिस्तान का दोहरा चेहरा अफगानिस्तान के मामले में भी सामने आया है। वह अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच युद्ध प्रभावित इस देश पर कब्जे के लिए तालिबान को उकसा रहा है।

अफगानिस्तान टाइम्स अखबार में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, पाकिस्तान खुले तौर पर तालिबान का समर्थन करने की बात स्वीकार कर चुका है। लेकिन इस आतंकी संगठन की सैन्य मदद करने से इन्कार कर रहा है। इससे पाकिस्तान का दोहरा चेहरा जाहिर होता है।

असल में पाकिस्तान इस आतंकी संगठन के लिए धन की व्यवस्था करने के साथ ही राजनयिक मदद भी मुहैया करा रहा है। वह तालिबान के लिए नई भर्ती और प्रशिक्षण में मदद करने के अलावा हथियार और ईंधन भी दे रहा है।

अखबार के अनुसार, अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ सीधी लड़ाई में तालिबान आतंकियों की आड़ में पाकिस्तानी सैनिक भी लड़ रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान के कई सैनिक भी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आइएसआइ भी तालिबान आतंकियों की मदद में पूरी से लिप्त है। बता दें कि अफगान सरकार भी यह दावा कर चुकी है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है।

गजनी का गवर्नर गिरफ्तार

अफगानिस्तान के वरदक प्रांत में गजनी के गवर्नर दाऊद लघमनी को गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकियों ने एक दिन पहले ही इस प्रांत की राजधानी पर कब्जा कर लिया था। यह आरोप लगाया गया है कि गजनी के गवर्नर और पुलिस प्रमुख तालिबान से डील कर फरार हो गए।

आतंकियों से शादी के लिए मजबूर की जा रहीं महिलाएं

अफगानिस्तान में बढ़ते कब्जे के साथ ही तालिबान की बर्बरता भी सामने आ रही है। वह अपने कब्जे वाले इलाकों में आतंकियों से शादी के लिए महिलाओं को मजबूर कर रहा है। अफगान नागरिकों ने बताया कि पकड़े गए कई अफगान सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया।

नापाक पाक : पूरी दुनिया तालिबान के बढ़ते वर्चस्व से चिंतित है, वही अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर तालिबान आतंकियों के कब्जे का पाकिस्तान में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। क्वेटा में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी नेताओं की इस करतूत से फिर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है। एपी

अमेरिका में कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को लगेगी अतिरिक्त डोज

वाशिंगटन, एपी : कोरोना महामारी की दो लहरों का सामना करने वाले अमेरिका में इस घातक वायरस का कहर फिर बढ़ गया है। ऐसे में अंग प्रत्यारोपण कराने वाले और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को वैक्सीन की एक अतिरिक्त डोज लगवाने की मंजूरी दी गई है। इससे कोरोना के डेल्टा वैरिएंट से बेहतर सुरक्षा मुहैया हो सकती है। देश में यह वैरिएंट तेजी से फैल रहा है।

अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने गुरुवार को अतिरिक्त डोज लगवाने को मंजूरी दी। फ्रांस और इजरायल जैसे कुछ अन्य देशों में भी इस तरह की सलाह दी गई है। समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, अमेरिका में कोरोना के दैनिक मामलों में उछाल के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी तेज गति से बढ़ रही है। अमेरिका में इस समय रोजाना एक लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिल रहे हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सीडीसी) की निदेशक रोशेल वालेंस्की ने कहा, 'हम देशभर में नए मामलों, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि देख रहे हैं। देश के तकरीबन 90 फीसद हिस्से में संक्रमण बढ़ रहा है।' वालेंस्की के अनुसार, बीते एक हफ्ते से रोजाना औसतन करीब एक लाख 13 हजार मामले मिल रहे हैं। इससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले 24 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। इस समय अस्पतालों में रोजाना औसतन 9,700 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। जबकि हर रोज औसतन 452 पीड़ितों की मौत हो रही है।

सावधानी जरूरी दक्षिण कोरिया के आग्यांग शहर के एक पार्क में बैंचों को टेप से कवर कर दिया गया है, ताकि कोई इन पर बैठकर संक्रमण की वजह न बन सके। एपी

आस्ट्रेलिया : सबसे बड़ी आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स प्रांत में रिकार्ड 390 संक्रमित पाए गए। यहां संक्रमण रोकने को सख्त कदम उठाए गए हैं।

पाकिस्तान : यहां चौथी लहर में तेजी से नए मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 4,619 नए मामले पाए गए और 79 पीड़ितों की मौत हो गई।

लैब से कोरोना फैलने की बात का विरोध कर रहे थे चीनी विज्ञानी

▸ डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में विज्ञानियों की एक टीम ने किया था अध्ययन

▸ वुहान इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी से वायरस लीक होने का लगता रहा है आरोप

वाशिंगटन, आइएएनएस : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के नेतृत्व वाली टीम में शामिल चीनी विज्ञानी प्रयोगशाला से कोरोना वायरस फैलने के सिद्धांत का विरोध कर रहे थे। दल का नेतृत्व करने वाले डब्ल्यूएचओ के विज्ञानी पीटर बेन एंबारेक ने एक डेनिश डाक्युमेंट्री में यह बात कही है। यह दल कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच कर रहा था।

'द वायरस मिस्ट्री' नामक इस डाक्युमेंट्री में एंबारेक ने कहा कि चीनी शोधकर्ता इस सिद्धांत के खिलाफ थे कि कोरोना महामारी आनुवंशिक रूप से परिष्कृत वायरस से फैली, जो वुहान इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी से लीक हुई थी। वाशिंगटन पोस्ट ने एंबारेक के हवाले से बताया कि शुरू में उन्हें प्रयोगशाला के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि यह असंभव था। इसलिए इस पर समय बेकार करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, हमने इसे शामिल करने पर जोर दिया, क्योंकि यह वायरस की उत्पत्ति से जुड़े मुद्दे का एक हिस्सा था।

यह पता करने के लिए कि क्या कोरोना की उत्पत्ति प्रयोगशाला में हुई है, डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों की टीम ने इस साल जनवरी में चीन में चार सप्ताह बिताए। मार्च में प्रस्तुत रिपोर्ट में जांच दल का कहना था कि प्रयोगशाला से वायरस लीक होने की दूर तक कोई संभावना नहीं है।

एंबारेक के मुताबिक, चीनी शोधकर्ता रिपोर्ट में प्रयोगशाला से वायरस लीक होने की बात शामिल करने को तैयार हो गए थे। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि हम इस परिकल्पना पर आगे के लिए किसी अध्ययन की सिफारिश न करें।

'किल लिस्ट' से आक्रोश, संसदीय समिति ने दिए जांच के आदेश

▸ तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के पूर्व प्रवक्ता ने उजागर की है सूची

▸ इसमें कई प्रख्यात शख्सियतों के नाम शामिल, मानवाधिकार मंत्री ने भी जताई विस्तृत जांच की जरूरत

इस्लामाबाद, प्रेट्र: प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के पूर्व प्रवक्ता और प्रमुख ब्रिटिश अखबार 'द गार्जियन' के हवाले से पाकिस्तान में पिछले हफ्ते एक 'किल लिस्ट' (हत्याओं की सूची) सामने आई है जिसमें कई प्रख्यात शख्सियतों के नाम शामिल हैं। इसके सामने आने से पाकिस्तान के राजनीतिक दलों में आक्रोश है। एक संसदीय समिति ने इस कथित लिस्ट की जांच कराने का आदेश दिया है।

समिति की चेयरपर्सन और विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की नेता शाजिया मैरी ने आंतरिक मामलों के सचिव को जल्द से जल्द पूर्व सीनेटर फरहतुल्ला बाबर और अफरासियाब खटक के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। डान न्यूज के मुताबिक, दोनों ही सीनेटरों के नाम 'किल लिस्ट' में शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र की पांच संस्थाओं ने भी 29 मई, 2019 को सरकार को लिखे एक संयुक्त पत्र में इस 'किल लिस्ट' का उल्लेख किया था। बाबर ने कहा कि यही कारण है कि इसे हल्के में लेना गंभीर हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने ऐसी किसी सूची के अस्तित्व को तत्काल नकार दिया, लेकिन सिर्फ इन्कार करने भर से संदेह खत्म नहीं हो जाता। खटक ने कहा कि हालात इतने खतरनाक हैं कि किसी का भी नाम इस सूची में हो सकता है। मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने भी कहा कि मामले की विस्तार से जांच की जरूरत है।

डान की खबर के मुताबिक, समिति को टीटीपी के पूर्व प्रवक्ता अहसानुल्लाह अहसान की एक फेसबुक पोस्ट फारवर्ड की गई है जिसमें उसने पिछले महीने दावा किया कि कुछ व्यक्तियों को खत्म करने के लिए उसे हत्यारों के एक दस्ते का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। अहसान की इस पोस्ट के मुताबिक, 'किल लिस्ट' में पूर्व सीनेटर बाबर व खटक के अलावा सैयद आलम मेहसूद और मुफ्ती किफायतुल्लाह के नाम भी शामिल हैं। बाबर ने कहा, 'अहसानुल्लाह अहसान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह टीटीपी का पूर्व प्रवक्ता है जिसने बाद में जमात उल अहरार नाम से अलग समूह बना लिया था, दोनों को ही आतंकी संगठन घोषित किया गया। उसने पाकिस्तान में कई जानलेवा हमलों की जिम्मेदारी ली है।'

शाजिया मैरी। फाइल/ इंटरनेट मीडिया

मानवाधिकार समिति को सूचित किया गया था कि अप्रैल, 2017 में अहसान ने कथित रूप से सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क करके खुद को आतंकवादी से एजेंसियों के विश्वासपात्र के रूप में बदल लिया था। उसे मीडिया को साक्षात्कार देने की आजादी थी और उसने कुछ चौंकाने वाली बातें उजागर की थीं। उच्च सुरक्षा वाली हिरासत से भागने के बाद अलजजीरा को दिए एक साक्षात्कार में उसने दावा किया कि उसकी रिहाई एक समझौते के एवज में हुई थी जिसके तहत उसे पूरा कानूनी संरक्षण, निजी वजीफा और शांतिप्रिय नागरिक की तरह रहने की अनुमति की गारंटी दी गई थी।

क्वेटा में पूर्व सीनेटर उस्मान काकर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अहसान ने कहा था कि उनका नाम 'किल लिस्ट' में शामिल था जो उसके पूर्व हैंडलर्स ने बनाई थी। इसके बाद उसने सूची में शामिल अन्य लोगों के नाम भी उजागर किए थे। अलजजीरा ने उसके आरोपों की सूची पाकिस्तान में सैन्य और नागरिक अधिकारियों को उपलब्ध कराई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

ब्रिटेन के प्लाइमाउथ सिटी में गोलीबारी की घटना में छह की मौत

लंदन, प्रेट्र : दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के प्लाइमाउथ में तीन महिलाएं और दो पुरुष समेत पांच की गोली मारकर हत्या करने के बाद हमलावर ने भी खुद को भी गोली मार ली। स्थानीय पुलिस ने इसे गंभीर घटना बताया है। डेवोन एवं कार्नवाल पुलिस ने शहर के केयहाम इलाके में घटनास्थल पर दो महिलाओं और दो पुरुषों के मारे जाने की पुष्टि की है। गोलीबारी में घायल तीसरी महिला की अस्पताल में मौत हुई। जैक डाविसन नामके संदिग्ध हमलावर ने गुरुवार रात गोलीबारी के दौरान खुद को भी गोली मार ली।

पुलिस ने कहा, 'दो महिलाओं और दो पुरुषों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक और पुरुष भी घटनास्थल पर मृत मिला,उसे हमलावर समझा जा रहा था। सभी की मौत गोली लगने से हुई। गोलीबारी में घायल एक और महिला की अस्पताल में मौत हो गई।

पाक एयर फोर्स के लिए बोझ बने चीनी जेएफ-17 लड़ाकू विमान

इस्लामाबाद, एएनआइ : चीन ने अपने जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमानों की खूबी को बढ़ा-चढ़ाकर बताकर अपने सदाबहार मित्र पाकिस्तान को दिए थे। अब चीन निर्मित यही विमान पाकिस्तानी एयर फोर्स के लिए बोझ बन गए हैं। इंजन में गड़बड़ी, उच्च रखरखाव और विमानों के प्रदर्शन में गिरावट कारण बताए जा रहे हैं।

दैनिक सन अखबार की खबर के अनुसार, वर्ष 1999 में चीन और पाकिस्तान ने जेएफ-17 के संयुक्त उत्पादन के लिए समझौता किया था। उस समय यह बताया गया था कि यह लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआइ, मिग-29 और मिराज-2000 जैसे लड़ाकू विमानों की तुलना में बेहतर है। बाद में पाकिस्तानी वायु सेना ने इन विमानों को दावों के आसपास भी नहीं पाया। इन विमानों में आरडी-93 एयरो इंजन लगे हैं, जो काला धुंआ छोड़ते हैं। इससे किसी युद्ध के दौरान ये लड़ाकू विमान आसानी से निशाने पर आ सकते हैं। इस तरह की खामियां मिलने पर पाकिस्तान ने चीन से कई बार शिकायत की। चीन ने इंजन भी बदले, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह बताई गई है कि ये आरडी-93 इंजन रूसी हैं। प्रतिबंधों के चलते रूस से इसके पार्ट और दूसरी मदद नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन जेएफ-17 के लिए एक नया इंजन विकसित कर रहा है। लेकिन इसमें लंबा वक्त लग सकता है।

जेएफ-17 लड़ाकू विमान (फाइल फोटो)

वाशिंगटन में गर्मी और लू से लोग हलकान

अमेरिका के कई हिस्सों में लोग भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। वाशिंगटन में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। इससे लोग व्याकुल हो गए हैं और गर्मी से बचने के लिए सार्वजनिक फव्वारों और कूलिंग सेंटरों का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने का रेड अलर्ट जारी किया है। एएफपी

विराट शायद मेरा अब तक का सबसे बड़ा विकेट है, इसलिए मैं खुश था। यह एक बहुत बड़ा क्षण था। हमारी योजना उनके खिलाफ हमेशा चौथी-पांचवी स्टंप पर गेंदबाजी करने की थी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि यह योजना काम कर गई। ओली राबिनसन

सिराज ने इंग्लैंड को दिए शुरुआती झटके

हसीब हमीद का विकेट लेने के बाद खुश भारतीय गेंदबाज मुहम्मद सिराज • रायटर

भारत के 364 रन के जवाब में इंग्लैंड ने तीन विकेट पर 119 रन बनाए

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : तेज गेंदबाज मुहम्मद सिराज ने इंग्लैंड को शुरुआती झटके दिए, जिसके चलते मेजबान टीम ने लंदन के ऐतिहासिक लार्ड्स के मैदान पर दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 119 रन बनाए थे। सिराज ने 34 रन देकर दो विकेट झटके। दिन का खेल खत्म होने के समय कप्तान जो रूट 74 गेंदों पर छह चौकों के साथ 48 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि जानी बेयरस्टो छह रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। इससे पहले जेम्स एंडरसन ने भारतीय बल्लेबाजों पर अंकुश लगाते हुए 62 रन देकर पांच विकेट झटके, जिससे भारत की पहली पारी 364 रन पर सिमट गई। दूसरे दिन रवींद्र जडेजा और रिषभ पंत के अलावा कोई भी उपयोगी पारी नहीं खेल सका। जडेजा ने 120 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 40 रन बनाए, जबकि पंत 58 गेंदों पर पांच चौकों की बदौलत 37 रन बनाकर आउट हुए।

दिन के दूसरे सत्र में इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। डोम सिब्ले और रोरी बर्न्स की सलामी जोड़ी ने इस सत्र में भारतीय गेंदबाजों को सफलता से दूर रखा। दोनों ने चायकाल तक स्कोर को बिना नुकसान के 23 रन तक पहुंचाया। चायकाल के बाद पहला ओवर करने आए सिराज की दूसरी ही गेंद को सिब्ले ने फ्लिक कर दिया और शार्ट मिडविकेट पर मुस्तैद खड़े राहुल ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। सिब्ले उसी अंदाज में आउट हुए जिस अंदाज में वह नाटिंघम टेस्ट की पहली पारी में आउट हुए थे। तब भी शार्ट मिडविकेट पर राहुल ने उनका कैच लपका था, लेकिन तब गेंदबाज मुहम्मद शमी थे। सिराज ने अगली गेंद पर ही हसीब हमीद को बोल्ड कर दिया। करीब चार साल आठ महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले हमीद पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान जो रूट ने सिराज को हैट्रिक लेने से वंचित कर दिया।

लार्ड्स की पिच काफी पेचीदा नजर आ रही है। यहां सेट बल्लेबाज लंबी पारी खेल रहे हैं, लेकिन एक बार विकेट गिरने के बाद नियमित अंतराल में विकेट गिर रहे हैं। बर्न्स और रूट ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाए रखा। दोनों ने इंग्लैंड के स्कोर को 108 रन तक पहुंचाया। इस स्कोर पर शमी ने बर्न्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड को जोरदार झटका दिया। रूट और बेयरस्टो ने दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड को कोई और नुकसान नहीं होने दिया।

इससे पहले भारत ने दूसरे दिन तीन विकेट पर 276 रन से आगे खेलना शुरू किया और पहले सत्र में ही 70 रन जोड़ने में चार विकेट गंवा दिए। शतकवीर केएल राहुल (129) अपने गुरुवार के स्कोर में सिर्फ दो रन जोड़कर ओली राबिनसन (2/73) की दिन की दूसरी गेंद पर कैच दे बैठे, जबकि एंडरसन ने अगले ओवर में पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे (1) को स्लिप में कैच कराया। यहां से पंत व जडेजा ने जिम्मा संभाला। पंत ने राबिनसन व एंडरसन दोनों पर चौके लगाकर दबाव कम किया, लेकिन मार्क वुड (2/91) पर मिडआफ और कवर के बीच से लगाया गया उनका चौका उनकी ताकत और बेफिक्र अंदाज का अच्छा नमूना था। हालांकि, यह बेपरवाही पंत को भारी पड़ी और वुड की गेंद पर ढीला शाट खेलकर उन्होंने विकेटकीपर बटलर को कैच दे दिया। शमी (0) को मोइन अली ने पवेलियन भेज दिया। भारत ने भोजनकाल तक सात विकेट पर 346 रन बनाए थे। भोजनकाल के बाद एंडरसन ने इशांत शर्मा (8) और जसप्रीत बुमराह (0) को लगातार ओवरों में चलता कर अपने पांच विकेट पूरे किए। जडेजा को वुड ने एंडरसन के हाथों कैच कराकर भारतीय पारी का अंत किया।

स्कोर बोर्ड

टास : इंग्लैंड (गेंदबाजी)

भारत (पहली पारी) 364 (126.1 ओवर) (276/3 से आगे)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
राहुल का. सिब्ले बो. राबिनसन	129	250	12	01
अजिंक्य रहाणे का. रूट बो. एंडरसन	01	23	00	00
रिषभ पंत का. बटलर बो. वुड	37	58	05	00
रवींद्र जडेजा का. एंडरसन बो. वुड	40	120	03	00
मुहम्मद शमी का. बर्न्स बो. अली	00	02	00	00
इशांत शर्मा एलबीडब्ल्यू बो. एंडरसन	08	29	01	00
बुमराह का. बटलर बो. एंडरसन	00	06	00	00
मुहम्मद सिराज नाबाद	00	00	00	00

अतिरिक्त : (बा-8, लेबा-5, नोबा-2) 15, **कुल :** 126.1 ओवर में 364 रन पर आलआउट, **विकेट पतन :** 4-278 (राहुल, 90.2), 5-282 (रहाणे, 91.1), 6-331 (पंत, 109.6), 7-336 (शमी, 110.5), 8-362 (इशांत, 123.6), 9-364 (बुमराह, 125.6), **गेंदबाजी :** एंडरसन 29-7-62-5, राबिनसन 33-10-73-2, कुर्रन 22-2-72-0, वुड 24.1-2-91-2, अली 18-1-53-1

इंग्लैंड (पहली पारी) 119/3 (45 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोरी बर्न्स एलबीडब्ल्यू बो. शमी	49	136	07	00
डोम सिब्ले का. राहुल बो. सिराज	11	44	01	00
हसीब हमीद बो. सिराज	00	01	00	00
जो रूट नाबाद	48	74	06	00
जानी बेयरस्टो नाबाद	06	17	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-2, नोबा-3) 5, **कुल :** 45 ओवर में तीन विकेट पर 119 रन, **विकेट पतन :** 1-23 (सिब्ले, 14.2), 2-23 (हमीद, 14.3), 3-108 (बर्न्स, 41.2), **गेंदबाजी :** इशांत 11-2-32-0, बुमराह 9-3-23-0, शमी 8-2-22-1, सिराज 13-4-34-2, जडेजा 4-1-6-0

टी-20 विश्व कप में ले जा सकेंगे 15 खिलाड़ी और आठ अधिकारी

आइसीसी ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों को दी अनुमति, 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ओमान और यूएई में होना है आयोजन

कराची, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने आगामी टी-20 विश्व कप में भाग लेने वाले देशों को यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) में टूर्नामेंट के लिए 15 खिलाड़ियों और आठ अधिकारियों को लाने की अनुमति दी है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को पुष्टि की कि आइसीसी ने भाग लेने वाले देशों के लिए अपने अंतिम-15 खिलाड़ियों और कोच एवं सहयोगी सदस्यों के आठ अधिकारियों की सूची भेजने के लिए 10 सितंबर की समय सीमा तय की है। इस अधिकारी ने बताया, 'आइसीसी ने कोविड-19 और बायो-बबल (कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए सुरक्षित माहौल) की स्थिति को देखते हुए टी-20 विश्व कप में भाग लेने वाले देशों को अतिरिक्त खिलाड़ियों को टीम के साथ लाने की अनुमति दी है, लेकिन इसका खर्च संबंधित बोर्डों को वहन करना होगा। आइसीसी सिर्फ 15 खिलाड़ियों और आठ अधिकारियों का खर्च वहन करेगी।'

साल 2016 के बाद पहली बार हो रहे टी-20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ओमान और यूएई में होगा। आठ देशों की क्वालीफाइंग टूर्नामेंट को 23 सितंबर से खेला जाएगा, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और आयरलैंड की टीमें भी शामिल हैं। इसमें से चार टीमें सुपर-12 चरण के लिए क्वालीफाई करेंगी। अधिकारी ने बताया, 'यह अब बोर्ड पर निर्भर करता है कि वह कोविड-19 स्थिति को देखते हुए अपनी मुख्य टीम के साथ कितने अतिरिक्त खिलाड़ी रखना चाहता है। मुख्य टीम से अगर कोई खिलाड़ी कोविड-19 जांच में पाजिटिव आता है या चोटिल होता है तो अतिरिक्त खिलाड़ियों में से कोई उसकी जगह ले सकता है।'

आइसीसी ने बोर्डों को सूचित किया है कि वे क्वारंटाइन अवधि शुरू होने से पांच दिन पहले तक अपनी टीम में अंतिम समय में बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'बोर्ड को हालांकि 10 सितंबर तक अपनी टीम की सूची भेजनी होगी।' इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होना था, लेकिन कोविड-19 की स्थिति के कारण आइसीसी ने इसे यूएई में स्थानांतरित कर दिया।

ला लीगा में निवेश के खिलाफ बार्सिलोना और रीयल मैड्रिड

42 में से 38 क्लबों ने पूंजी निवेश कंपनी सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के साथ करीब 236 अरब रुपये के निवेश सौदे को मंजूरी देने के लिए मतदान किया

मैड्रिड, आइएएनएस : ला लीगा क्लबों ने पूंजी निवेश कंपनी सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के साथ 2.7 बिलियन यूरो (करीब 236 अरब रुपये) के निवेश सौदे को मंजूरी देने के लिए मतदान किया है। इस समझौते के पक्ष में गुरुवार को 38 वोट पड़े, जबकि कुल 42 में से चार क्लबों ने इसके खिलाफ मतदान किया। खिलाफ मतदान करने वालों में रीयल मैड्रिड और बार्सिलोना प्रमुख क्लब के रूप में हैं। इनके अलावा एथलेटिक क्लब बिलबाओ और रीयल ओविएडो ने भी खिलाफ मतदान किया है।

समझौता के तहत क्लबों को एक लंबी अवधि के कर्ज के रूप में बड़ी धनराशि प्राप्त होगी, जिसे 40 साल की अवधि में वापस भुगतान किया जाना है। इस रकम का 15 प्रतिशत वेतन व नए खिलाड़ियों को खरीदने और बाकी हिस्सा बुनियादी ढांचे, युवा प्रणालियों और महिला टीमों पर खर्च किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके बदले में सीवीसी कंपनी ला लीगा के सभी नानआडियो-विजुअल व्यवसाय से आय का 11 प्रतिशत और अगले 50 वर्षों के लिए आडियो-विजुअल व्यवसाय से कुल आय का 10 प्रतिशत राजस्व प्राप्त करेगा। रीयल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिक क्लब और ओविएडो ने इस योजना से कोई भी रकम नहीं प्राप्त करने का विकल्प चुना है। इन क्लबों का मानना है कि यह सौदा उन्हें 50 वर्षों के लिए बंधक बना देगा।

विनेश फोगाट और डब्ल्यूएफआइ के बीच दंगल

- 16 तक विनेश को जवाब देना है, उसके बाद फैसला लेंगे : बृजभूषण
- मेरी मानसिक ताकत जीरो और हर कोई चाकू लेकर बैठा है : विनेश

जेएनएन, नई दिल्ली : टोक्यो ओलिंपिक से बिना पदक वापस लौटीं विनेश फोगाट को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) ने हाल ही में अनुशासनहीनता के चलते अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद विनेश ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बजाय भावुक पत्र लिखकर अपनी तमाम समस्याओं को सामने रखा है। हालांकि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि हम वाकयुद्ध में नहीं पड़ेंगे। यह हमारी फितरत नहीं है। हमने जो नोटिस भेजा है, उस पर उन्हें सोमवार तक जवाब देना है। जवाब के आधार पर हम फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है।

मालूम हो कि इससे पहले भी एक बार डब्ल्यूएफआइ ने विनेश को निलंबित करने का नोटिस भेजा था तब उन्होंने खेद जताया था और मामला रफा-दफा हो गया था। वहीं महासंघ के अधिकारी ने कहा कि विनेश कहां क्या लिखती हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। वह हमारे भेजे गए नोटिस का क्या जवाब देती हैं, हमें उसका इंतजार है और उसी के बाद हम कुछ बता सकेंगे।

मालूम हो कि विनेश ने भावुक पत्र में लिखा है कि मैंने कुश्ती को सबकुछ दिया और अब यह छोड़ने का सही समय है लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैंने छोड़ दिया और मैं नहीं लड़ी, तो यह मेरी ज्यादा बड़ी हार होगी। मेरी मेंटल स्ट्रेंथ (मानसिक ताकत) जीरो है। मुझे मेरी हार पर दुख भी नहीं मनाने दिया। हर कोई हाथ में चाकू लेकर तैयार बैठा है। हम सिमोन बाइल्स की बात की तारीफ करते हैं। जब वह कहती हैं कि मैं ओलिंपिक में उतरने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। जरा सोचिए ऐसा अगर भारत में होता। कुश्ती छोड़ने की बात तो रहने ही दीजिए सिर्फ इतना कहने की कोशिश कीजिए मैं तैयार नहीं हूं। किसी ने मुझसे पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर मैट पर क्या हुआ। सबने अपने आप फैसले लेने शुरू कर दिए। मैट पर क्या हुआ यह मैं ही बेहतर बता सकती हूं।' उन्होंने कुश्ती संघ पर निशाना साधते हुए लिखा, 'डब्ल्यूएफआइ ने मुझे मेरा फिजियो साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी। मुझे जो फिजियो दी गई वह निशानेबाजों टीम की थी। वह मेरे शरीर को समझती नहीं थी। मैं कुश्ती के लिए जाते समय वजन कम करने को लेकर संघर्ष कर रही थी। बस में मैंने उल्टी कर दी थी, जिसके बाद मैंने अपने पुराने फिजियो को फोन करके पूछा था कि क्या किया जाए। हालांकि मैं उस फिजियो की आलोचना भी नहीं करना चाहतीं क्योंकि यह सही नहीं होगा।'

विनेश फोगाट • फाइल फोटो, एपी

इस कारण निलंबित हुईं विनेश

नई दिल्ली : महासंघ ने कहा था कि विनेश ने हंगरी से टोक्यो पहुंचने के बाद काफी नखरे दिखाए थे। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ ठहरने से इन्कार किया साथ ही, टूर्नामेंट के दौरान उनके साथ ट्रेनिंग भी नहीं की। साथ ही विनेश ने भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के बजाय निजी प्रायोजक के नाम का सिंगलेट पहना था, जिससे डब्ल्यूएफआइ ने उन्हें निलंबित कर दिया था। विनेश को कई बार फोन किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

सोनम मालिक ने मांगी माफी

नई दिल्ली : एक अन्य महिला पहलवान सोनम मालिक ने डब्ल्यूएफआइ के नोटिस का जवाब देते हुए माफी मांग ली है। सोनम ने कहा कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगी। सोनम को नोटिस जारी किया था जिन्होंने खेलों के लिए रवाना होने से पहले अपना पासपोर्ट लेने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) स्टाफ की मदद मांगी थी।

> मुझे लगता है कि हमें विनेश की उपलब्धियों का सम्मान करने की जरूरत है। वह अच्छी पहलवान हैं, लेकिन वो उनका दिन नहीं था। जीतना और हारना खेल का एक भाग है। जब हम जीत हासिल करते हैं तो गलती छुप जाती है, जबकि हारने पर अच्छी चीजों को कोई याद नहीं रखता। सभी को यह याद रखना चाहिए कि कोई एथलीट हारना नहीं चाहता।
>
> **योगेश्वर दत्त,** ओलिंपिक पदक विजेता पूर्व भारतीय पहलवान

> छोटी बहन विनेश फोगाट, जीवन के हर मोड़ पर उतार-चढ़ाव हैं, बस बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहना है और किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। हम चैंपियन विनेश फोगाट को दोबारा और भी मजबूती के साथ कुश्ती के मैट पर देखना चाहते है। पेरिस ओलिंपिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
>
> **गीता फोगाट,** पूर्व भारतीय पहलवान और विनेश फोगाट की चचेरी बहन

एक नजर में

16 अगस्त से भारतीय महिला फुटबाल शिविर

नई दिल्ली : भारतीय महिला फुटबाल टीम के राष्ट्रीय शिविर का आयोजन 16 अगस्त से झारखंड के जमशेदपुर में किया जाएगा। अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) ने शुक्रवार को बताया कि इस शिविर का आयोजन एएफसी एशियाई कप 2022 की तैयारी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में 20 जनवरी से छह फरवरी 2022 तक होगा। मुख्य कोच थामस डेनेर्बी ने 30 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की है। (प्रेट्र)

विदित गुजराती ने स्विस लीग के लिए किया क्वालीफाई

चेन्नई : भारतीय ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती ने 25 अक्टूबर से आठ नवंबर तक रीगा, लातविया में आयोजित होने वाली फिडे ग्रैंड स्विस लीग के लिए क्वालीफाई कर लिया है। नासिक के इस खिलाड़ी ने हाल ही में संपन्न शतरंज विश्व कप 2021 में शीर्ष आठ में पहुंचने के बाद फिडे ग्रांप्रि 2022 के लिए भी क्वालीफाई किया है। उनके पास कैंडिडेट्स 2022 में अपना स्थान पक्का करने के लिए दो मौके हैं। कैंडिडेट्स 2022 में खिलाड़ी विश्व चैंपियन को चुनौती देने के लिए क्वालीफाई करेगा। (प्रेट्र)

हैंडबाल के विकास को लेकर आइएचएफ से मिले एचएफआइ अध्यक्ष

नई दिल्ली : भारतीय हैंडबाल महासंघ के कार्यकारी निदेशक आनंदेश्वर पांडेय ने अंतरराष्ट्रीय हैंडबाल महासंघ के अध्यक्ष हसन मुस्तफा से मुलाकात कर देश में इस खेल के विकास के लिए खाका तैयार करने को कहा है। ओलिंपिक के दौरान हुई मुलाकात में इस बात पर चर्चा हुई कि आइएचएफ भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन देने के लिए अपना समर्थन कैसे दे सकता है। (प्रेट्र)

उन्मुक्त ने लिया संन्यास

- अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के रह चुके हैं कप्तान
- चंद के अमेरिका में टी-20 लीग में खेलने की संभावना

उन्मुक्त चंद • फाइल फोटो, एएफपी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली भारत के पूर्व अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद ने शुक्रवार को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। वह अपनी यह सफलता सीनियर स्तर पर नहीं दोहरा सके। उन्मुक्त ने ट्विटर पर अपनी कुछ यादगार वीडियो के साथ एक लंबा नोट साझा करते हुए पुष्टि की कि वह भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन दुनियाभर में अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं।

28 वर्षीय उन्मुक्त जल्द ही अमेरिका रवाना हो सकते हैं और अब विदेशी लीगो में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनके अमेरिका में टी-20 लीग में खेलने की संभावना जताई जा रही है। अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के उनके साथी खिलाड़ी समित पटेल ने भी कुछ समय पहले ऐसा ही कदम उठाया था। अमेरिका में खेलने के लिए उन्हें संन्यास की घोषणा करनी पड़ती, क्योंकि बीसीसीआइ अपने पंजीकृत खिलाड़ियों को विदेशी टी-20 लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं देता। उन्मुक्त ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से चीजें हुई थीं उससे मैं अंदर से शांत नहीं था। मैं फिर भी उम्मीद की किरण देखता हूं और यादगार स्मृतियों के साथ बीसीसीआइ को अलविदा कहता हूं तथा दुनिया भर में बेहतर मौकों की तलाश करूंगा। क्रिकेट एक सार्वभौमिक खेल है और हो सकता है इसका मतलब बदल जाए, लेकिन लक्ष्य हमेशा एक ही रहता है और वह है सर्वोच्च स्तर पर खेलना। साथ ही मेरे सभी समर्थकों और चाहने वालों का धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा मुझे अपने दिल में पनाह दी। आप जैसे हैं उससे लोग प्यार करें, इससे बेहतर और कोई भावना नहीं। मैं खुद को काफी भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पास ऐसे लोग हैं। सबका शुक्रिया। अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं।'

उन्मुक्त ने अपने ट्वीट में अंडर-19 विश्व कप जीतने को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने लिखा, 'बीसीसीआइ को आभार जिसने मुझ जैसे क्रिकेटर को इतने सारे शिविरों, आयु ग्रुप और सीनियर बोर्ड टूर्नामेंट तथा इंडियन प्रीमियर लीग में खुद को अभिव्यक्त करने और अपना कौशल दिखाने का मंच प्रदान किया। भारत में मेरी क्रिकेट यात्रा में कुछ शानदार पल रहे, जिसमें देश के लिए अंडर-19 विश्व कप जीतना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्षण था। कप्तान के तौर पर कप उठाना विशेष अहसास था जिससे दुनिया भर में इतने सारे भारतीयों के चेहरों पर मुस्कान आई। मैं उस अहसास को कभी नहीं भूल सकता। साथ ही कई मौकों पर भारत-ए की अगुआई करना, विभिन्न द्विपक्षीय और त्रिकोणीय सीरीज जीतना मेरी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है।' उन्मुक्त घरेलू क्रिकेट में दिल्ली और उत्तराखंड जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। दायें हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज उन्मुक्त ने 67 प्रथम श्रेणी मैच खेले और 113 पारियों में 31.60 की औसत से 3379 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने आठ शतक और 16 अर्धशतक जड़े। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 151 रन है। उन्होंने 121 लिस्ट-ए मैचों की 120 पारियों में 41.30 की औसत से 4507 रन बनाए। इस प्रारूप में उनके नाम सात शतक और 32 अर्धशतक दर्ज है, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 127 रन है। टी-20 करियर में उन्होंने 77 मैच खेलते हुए 75 पारियों में 22.40 की औसत से 1565 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और पांच अर्धशतक जड़े।

बीसीसीआइ के चिकित्सा अधिकारी पर उठे सवाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : क्रुणाल पांड्या के कोविड-19 पाजिटिव मामले में बीसीसीआइ के श्रीलंका दौरे पर गए चिकित्सा अधिकारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन्होंने आरटी-पीसीआर परीक्षण में एक दिन का विलंब किया, जिससे आठ खिलाड़ी दो टी-20 मैचों में नहीं खेल पाए। अब पता चला है कि क्रुणाल ने गले में दर्द के लक्षण महसूस होने के बाद तुरंत 26 जुलाई को टीम के साथ गए डाक्टर अभिजीत साल्वी को बताया, लेकिन तुरंत न तो रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ और न ही उन्हें क्वारंटाइन में भेजा गया, बल्कि गले में दर्द के बावजूद टीम के डाक्टर ने खिलाड़ी को टीम बैठक में शिरकत करने की मंजूरी दी और 27 जुलाई की सुबह उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया।

एनबीए समर लीग में खेलने वाले दूसरे भारतीय बने प्रिंसपाल

नई दिल्ली, जेएनएन : बास्केटबाल की एनबीए समर लीग में पदार्पण करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी प्रिंसपाल सिंह का मानना है कि उनका सफर सपने से कम नहीं रहा है और वह एनबीए में खेलने के अगले लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी फिटनेस और कौशल पर काम कर रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले सिंह ने लुधियाना बास्केटबाल अकादमी के साथी सतनाम सिंह की तरह ही एनबीए समर लीग में पदार्पण किया जिसमें वह मंगलवार की रात लास वेगास में वाशिंगटन विजर्ड्स के खिलाफ साक्रामेंटो किंग्स के लिए खेले। सिंह ने कहा, समर लीग में खेलना शानदार है। मैं खिलाड़ी के तौर पर अपनी प्रगति से बहुत खुश हूं। मैं पहले जी लीग में खेला और फिर समर लीग में।

सितारों की बात टोक्यो ओलिंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय भारोत्तोलक ने कहा, देशवासियों से मुझे ढेर सारा प्यार मिला जिससे मेरा विश्वास बढ़ा है

मेरे पदक के बाद भारोत्तोलन में बढ़ रही है लोगों की दिलचस्पी : मीराबाई

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू का मानना है कि टोक्यो ओलिंपिक में उनके रजत पदक जीतने के बाद इस खेल को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि निकट भविष्य में और अधिक महिलाएं इस खेल में शीर्ष स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगी। मीराबाई ने कहा, 'जब से मैं वापस (टोक्यो से) आई हूं, मुझे भारत के लोगों से ढेर सारा प्यार मिला है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है। भारत के लिए पदक जीतना किसी सपने के सच होने जैसा है। टोक्यो से पहले ऐसा नहीं था लेकिन मैं पहली बार भारोत्तोलन में काफी अधिक रुचि देख रही हूं। इससे मुझे विश्वास है कि अगले ओलिंपिक में अधिक महिलाएं भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।'

नीरज बोले, मेरा भी सपना था कि मिल्खा सिंह की इच्छा पूरी कर सकूं: टोक्यो ओलिंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनका सपना था कि वह भारतीय एथलेटिक्स के पदक को जीतकर मिल्खा सिंह जी की इच्छा पूरी कर सके।

नीरज ने ट्विटर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि मेरा भी सपना था की मिल्खा सिंह जी की इच्छा पूरी कर सकूं। बस यही उम्मीद है की वो जहां भी हो यह देख कर खुश होंगे। रिजिजू ने नीरज के जीतने पर ट्वीट किया था कि मिल्खा सिंह जी की इच्छा पूरी हुई और नीरज चोपड़ा ने भारतीय एथलेटिक्स को पहला पदक स्वर्ण पदक के रूप में दिलाया। जिस पर नीरज ने अब उनका शुक्रिया अदा किया। मालूम हो कि नीरज ने टोक्यो ओलिंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर भारत को 100 से अधिक साल बाद एथलेटिक्स में पहला पदक दिलाया।

पूर्व खेल मंत्री और अब कानून मंत्री किरण रिजिजू के साथ रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू और पूर्व ओलिंपिक पदक विजेता टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस • ट्विटर

बार्टनिट्ज बोले, नीरज को तकनीक में लानी होगी स्थिरता : ओलिंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के कोच क्लाउस बार्टनिट्ज का मानना है कि इस भाला फेंक खिलाड़ी ने अपनी तकनीक की अधिकांश कमियों को ठीक कर लिया है और अब उनकी कोशिश आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छूने के लिए तकनीकी स्थिरता को बनाए रखने की होनी चाहिए। बार्टनिट्ज ने कहा, 'मुझे शुरुआत में उनमें दौड़ने की गति, शरीर की सही स्थिति में ब्लाकिंग (भाले को गति देने में अहम) और एक युवा ताकतवर एथलीट के रूप में थ्रो को जल्दी फेंकने जैसी कुछ कमियां नजर आई थी। मैंने उसे समझाया तब उसने सही तरीके से समझना शुरू कर दिया। इसमें कुछ भी नाटकीय नहीं था। भाला फेंकने का कोण (एंगल) सही होना चाहिए, अगर आप आगे फेंकना चाहते हैं तो आपको हवा की गति को जानने की जरूरत है। हमें सुधार जारी रखने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हमें हर समय तकनीक पर काम करना होगा, इसे जारी रखना होगा और इसे स्थिर बनाना होगा।' चोपड़ा ने एक सफल सर्जरी के बाद 2019 में बार्टनिट्ज के साथ काम करना शुरू किया था। जर्मनी के इस बायो-मैकेनिक्स विशेषज्ञ ने कहा कि इस भारतीय युवा की तकनीक में कोई खामी नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर ध्यान देने की जरूरत है।

हर किसी के अंदर कोई न कोई टैलेंट जरूर होता है, चाहे वह पढ़ाई में हो या फिर खेल में। खेलों में अवसर असीमित और ब्राइट फ्यूचर है। इसमें ढेर सारे करियर विकल्प भी हैं। युवा मैदान में एक पेशेवर खिलाड़ी या कोच बनकर या फिर मैदान से बाहर खिलाड़ियों के सहयोगी या खेल प्रबंधन क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। टोक्यो ओलिंपिक में भारतीय युवाओं के बेहतर प्रदर्शन के बाद उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से आकर्षक इनाम और नौकरियों तक के आफर किए जा रहे हैं। इससे खेलों में करियर बनाने की चाह रखने वाले किशोरों-युवाओं को और प्रोत्साहन मिलेगा। आइए जानें, खुद को इस दिशा में कैसे आगे बढ़ाएं...

पहचानें खुद का टैलेंट

फोटो : इमेजेज बाजार

टर्निंग प्वाइंट

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी
एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल आफ मैनेजमेंट, जेएनयू, नई दिल्ली

खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल के मैदान में ही हम हार-जीत का सबक लेकर स्वस्थ मानसिकता का विकास कर सकते हैं। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि-मुनियों ने योगासनों के महत्व को समझा तथा उसे जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। उपनिषद में लिखा है 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम' अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल तथा व्यायाम प्रमुख साधन हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि खुले मैदानों में खेलने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे मानवीय मूल्यों का विकास होता है। दरअसल, खेल हमें खेलने की प्रक्रिया में बहुत कुछ सिखाते हैं, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास में एक आवश्यक कारक के रूप में कार्य करता है। यह हमें समय प्रबंधन, नेतृत्व, कांफिडेंस बिल्डिंग, गलतियों से सीखने, जिम्मेदारी लेने, टीम वर्क, उत्साह व आत्मविश्वास जैसे मूल्यवान गुण सिखाता है। ये खेल के कुछ अमूर्त लाभ हैं, जो किताबों या आभासी गेमिंग में नहीं खोजे जा सकते हैं।

धारणा बदलने की जरूरत: हमारे समाज में खेल को शिक्षा से कमतर दिखाने की सदियों पुरानी धारणा है। अधिकतर माता-पिता मानते हैं कि खेल केवल समय गुजारने का साधन है। हमारी पीढ़ी में इस मानसिकता का परिणाम काफी स्पष्ट है, खासकर ऐसे समय में जब आभासी और मोबाइल गेमिंग उपकरणों ने किसी के जीवन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बच्चे हों या युवा, लगातार मोबाइल पर गेम या वीडियो गेम खेलना आज लोगों की आदत बनती जा रही है। समाज आज भी टापर व गोल्ड मेडलिस्ट को एक खिलाड़ी से ज्यादा महत्व देता है, पर यही खिलाड़ी मेडल जीतकर देश को अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिलाते हैं। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, पीटी उषा, मैरी काम, पीवी सिंधू, सायना नेहवाल, मीराबाई चानू कुछ ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र आज हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर करते हैं। ये कौन हैं? ये न तो आइएएस-पीसीएस हैं, न तो डाक्टर हैं और न ही इंजीनियर या वैज्ञानिक, ये तो सिर्फ खिलाड़ी हैं। हर कोई इनकी सराहना करता है और उनसे प्यार भी करता है, लेकिन हममें से कितने लोग इनके जैसा बनने का साहस जुटा पाते हैं?

भारत के संदर्भ में, खेल आमतौर पर क्रिकेट से जुड़ा होता है, जहां ज्यादातर अभिभावक भेड़-चाल चलकर बच्चों को सचिन बनाने में लगे होते हैं। वे नहीं सोचते कि महाराणा प्रताप के भाले से भी कोई नीरज चोपड़ा बनकर विश्व में छा सकता है। अधिकतर छात्र ऐसा सोचते हैं कि परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने से जीवन में आगे सफलता ही सफलता मिलेगी, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। आज जब कैंपस प्लेसमेंट में बड़ी-बड़ी कंपनियां युवाओं को अपनी कंपनी के लिए चुनने आती हैं, तो कालेज का टापर भी सेलेक्ट नहीं होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पर्सनैलिटी का ओवरआल विकास न होना जो कि सिर्फ और सिर्फ खेलों की मदद से ही हो सकता है।

खेलों से संपूर्ण विकास: खेलों का स्वभाव ही एकजुट होना है। खेल हमारे विकास का एक अभिन्न अंग हैं। खेल सभी के लिए समान है। यह बेटी-बेटे में भेदभाव नहीं करता है। आजाद भारत में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। फिर 2007 में हमारे देश में प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं। लेकिन क्या हम आज महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, समान और सशक्त समाज का दावा कर सकते हैं? कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है जिसके बिना स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उसी समाज का मिजाज कोख में कन्या की जानकारी होते ही आदिम बन जाता है। जीने के अधिकार से किसी को वंचित करना पाप है, क्या पता उसमें कोई सुषमा स्वराज, कोई लता मंगेशकर, कोई किरण बेदी, कोई सायना नेहवाल और कोई पीवी सिंधू होती, तो कोई मीराबाई चानू हो सकती थी। किसी कवि ने ठीक ही लिखा है- 'करते रहे गुनाह हम, केवल बेटे के शौक में, कितने मेडल मार दिए, जीते जी कोख में।' इसीलिए 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' से आगे बढ़कर 'बेटी खेलाओ' की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

500-600
अरब अमेरिकी डालर है खेल उद्योग का वैश्विक बाजार (केपीएमजी के अनुसार)।

खेलों में भी ब्राइट फ्यूचर: हमें यह समझना चाहिए कि सबके अंदर कोई न कोई टैलेंट जरूर होता है, चाहे वह पढ़ाई में हो या फिर खेल में। खेल बाजार विशाल है और इसमें अवसर असीमित हैं। खेलों में भी ब्राइट फ्यूचर है और ढेर सारे करियर विकल्प भी, युवा आन-फील्ड एक पेशेवर खिलाड़ी या कोच बनकर और आफ-फील्ड खेल प्रबंधन क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट्स कोच, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स ब्राडकास्टिंग, स्पोर्ट्स साइकोलाजी, स्पोर्ट्स पीआर, फिटनेस एक्सपर्ट इत्यादि। यदि किसी व्यक्ति की विश्लेषणात्मक मानसिकता है, तो वह स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में भी शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर, युवा कई रूपों में खेल में योगदान कर सकते हैं। आज सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिये नौकरी पाने के कई अवसर है।

कोविड काल का सदुपयोग: युवा कोविड के इस अशांत समय को एक सीखने योग्य क्षण के रूप में उपयोग करें, क्योंकि भारत का युवा भारतीय खेलों का भविष्य है। भारत के 2025 तक दुनिया का सबसे युवा देश बनने का अनुमान है, जिसमें 62 फीसद आबादी युवा होगी। युवाओं को सोचना होगा कि वे कैसे सकारात्मक बदलाव में योगदान दे सकते हैं? हम जैसे-जैसे बड़े होते गए, हमने अपने अंदर के उस खिलाड़ी को खो दिया है। वास्तव में खेलकूद जीवन में सफलता के लिए शिक्षा जितना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए खेल के प्रति मानसिकता बदलने की जरूरत है। पदक, आखिरकार, रातोंरात नहीं जीते जाते हैं। कई बार हम सिर्फ बहाने करके कोई कदम नहीं उठाते। मीराबाई चानू जैसे खिलाड़ियों के संघर्ष को देखें तो यह कह सकते हैं कि 'बहाने के आगे जीत है'।

(julybrajesh@gmail.com)

> प्रदर्शन पहचान दिलाता है। पहचान से सम्मान आता है और इसी सम्मान से शक्ति बढ़ती है।
> -एनआर नारायण मूर्ति

वीडियो रेज्यूमे से जमाएं अपना इंप्रेशन

टेक लर्निंग

कोरोना महामारी के बाद बदली परिस्थितियों में इन दिनों वीडियो रेज्यूमे का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जॉब तलाशने वाले युवाओं द्वारा अपलोड किए जा रहे इस तरह के वीडियो को नियोक्ता भी काफी पसंद कर रहे हैं। आइए जानें, क्या है वीडियो रेज्यूमे और किस तरह की प्रोफाइल वाली जॉब्स इससे आसानी से तलाशी जा सकती हैं...

वीडियो रेज्यूमे अमूमन एक से डेढ़ मिनट का एक छोटा-सा वीडियो होता है, जिसके जरिये नौकरी चाहने वाले युवा अपना आवेदन करते हैं। इस वीडियो में आवेदक को अपने कौशल, अनुभव, शिक्षा और संपर्क से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियां देनी होती हैं। वीडियो बनाने के बाद इसे इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया जाता है या फिर सीधे संभावित नियोक्ताओं को भी भेजा जा सकता है। कई बार यह भी होता है कि वीडियो पसंद आने और उससे प्रभावित होने पर लोग ही उसे संबंधित नियोक्ताओं को टैग कर देते हैं। वीडियो देखने के बाद नियोक्ता चयनित उम्मीदवारों से खुद सीधे संपर्क कर आगे की बातचीत करते हैं।

किसे बनाना चाहिए यह वीडियो: अगर वीडियो रेज्यूमे का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह संभावित नियोक्ताओं के समक्ष खुद की मार्केटिंग करने में काफी काम आ सकता है। यह वीडियो आप खुद बना सकते हैं या फिर किसी पेशेवर द्वारा बनवाया जा सकता है। वैसे, वीडियो रेज्यूमे उन युवाओं के लिए काफी उपयोगी हो सकता है, जो किसी विजुअल या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं और इसके जरिए अपनी किसी महत्वपूर्ण स्किल को प्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर परफार्मेंस बेस्ड कार्यों को दिखाने के लिए (जैसे कि एक्टिंग, टीचिंग, प्रेजेंटेशन) यह काम आ सकता है। वीडियो रिज्यूमे अपने व्यक्तित्व को दिखाने का भी एक शानदार तरीका हो सकता है, खासकर उन युवाओं के लिए जिनका काम क्लाइंट से डील करना है या जो सेल्स के पेशे से जुड़े हैं। बहरहाल, जो फील्ड विजुअल से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए यह बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है।

वीडियो रिज्यूमे बनाने के टिप्स: जो युवा नौकरी तलाशने के लिए वीडियो रिज्यूमे बनाने पर विचार कर रहे हैं, उन्हें कुछ बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऐसा वीडियो बनाते समय बिल्कुल पेशेवर तरीके से पेश आएं। एक साक्षात्कार के लिए जाते समय आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं और जो पेशेवर व्यवहार अपनाते हैं, उसका यहां भी खयाल रखें। वीडियो की पृष्ठभूमि अच्छी रखें। सुनिश्चित करें कि पृष्ठभूमि में कोई शोर-शराबा न हो। लाइट की व्यवस्था अच्छी हो। किसी स्क्रिप्ट की तरह अपनी बात रखने से बचें, क्योंकि विवरणात्मक होने से वीडियो नीरस हो सकता है। साथ ही, वीडियो यह सोचकर बनाएं कि किसी कंपनी को आपको क्यों काम पर रखना चाहिए यानी आपका मुख्य उद्देश्य यह व्यक्त करना होना चाहिए कि कंपनी को आप अपने योगदान से किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। आखिरी महत्वपूर्ण बात यह कि अपने वीडियो को संक्षिप्त रखें।

फीचर डेस्क

सक्सेस मंत्रा

नया करने के लिए साहस जरूरी

आरुषि वर्मा
सह-संस्थापक
फिटपास

2015 में दिल्ली में कुछ जिम के साथ मिलकर हुई थी एक शुरुआत। लेकिन विगत वर्षों में फिटनेस इकोसिस्टम में अपनी एक खास पहचान बनाई है 'फिटपास' कंपनी ने। आज यह देश के 17 से अधिक शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। लोग घर बैठे जिम या फिटनेस सेंटर से जुड़ सकते हैं। इनके प्लेटफार्म से चार हजार से अधिक जिम एवं फिटनेस स्टूडियो जुड़े हुए हैं। एप की मदद से न्यूट्रिशनिस्ट एवं अन्य विशेषज्ञों से परामर्श किया जा सकता है। कंपनी की सह-संस्थापक आरुषि वर्मा का मानना है कि अपने दिल की सुनने के लिए साहस का होना जरूरी है। सफलता तभी मिलती है जब हम धैर्य के साथ वह करते हैं, जो हम करना चाहते हैं।

आरुषि का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं रहा था। पिता सरकारी सेवा में रहे। मां प्रोफेसर। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कालेज से इकोनामिक्स में स्नातक किया। साथ ही लंदन यूनिवर्सिटी के 'द स्कूल आफ ओरिएंटल ऐंड अफ्रीकन स्टडीज' से डेवलपमेंट इकोनामिक्स में मास्टर्स किया। विदेश में नौकरी करने का कोई इरादा नहीं था, तो वापस लौटकर दिल्ली स्थित एसर (एएसईआर) सेंटर में बतौर रिसर्च एसोसिएट काम करने लगीं। इसके बाद उन्हें वर्ल्ड बैंक के साथ कंसल्टेंट के रूप में सेवा देने का अवसर मिला। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने उद्यमिता में जाने का निर्णय ले लिया। वह कहती हैं, जब हमने अपनी सरकारी कालोनी के आसपास लोगों को अच्छे जिम की कमी से जूझते देखा, तो समस्या को सुलझाने का मन बना। हमने बाजार का सर्वे किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि लोग फिटनेस को लेकर काफी सचेत हैं। यदि उन्हें उचित कीमत पर जिम आदि की सुविधाएं मिलेंगी, तो वे खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद ही 'फिटपास' का आइडिया आया और जनवरी 2015 में हमने इसे लांच कर दिया। यहां एक निर्धारित शुल्क पर मेंबर बनकर आप दिल्ली-एनसीआर, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद में कहीं के भी जिम या फिटनेस स्टूडियो की सुविधा हासिल कर सकते हैं।

बचत से हुई शुरुआत: आरुषि कहती हैं कि जब तक कुछ जोखिम नहीं उठाएंगे, तो नतीजे कैसे मिलेंगे? सपने कैसे पूरे होंगे? मेरे ऊपर कोई घरेलू जिम्मेदारी नहीं थी। इसलिए नौकरी करते हुए जो 8-10 लाख रुपये की बचत हुई थी, उसे स्टार्टअप में लगा दिया। वैसे भी शुरुआत में सिर्फ पांच लोगों की ही टीम थी। टेक्नोलाजी के लिए बाहर से कोई सहायता नहीं चाहिए थी। भाई अक्षय ने यह मोर्चा संभाल रखा है। मैं आपरेशन देखती हूं। हमारे खर्च सीमित हैं।

इनोवेशन से बढ़े आगे: कोई भी मार्केट हो, वह हमेशा बदलता रहता है। ऐसे में इनोवेशन करते रहने से आप अपने ग्राहकों को खोते नहीं। आपकी विश्वसनीयता भी कायम रहती है। शुरू के एक साल में हमें अपने पार्टनर्स को बिजनेस माडल से कनविन्स करने में काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जब उन्हें लगा कि प्लेटफार्म आमदनी का एक नया माध्यम बन सकता है, तो उन्होंने इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। पहले हम सिर्फ मेंबरशिप देते थे। लेकिन अब न्यूट्रिशनिस्ट्स को भी प्लेटफार्म से जोड़ा है। आने वाले समय में कुछ और सर्विसेज देने की योजना है।

बातचीत : अंशु सिंह

फोटो : इमेजेज बाजार

जो करो, पूरा करो, बीच में मत छोड़ो

आरुषि की प्रेरणा मां रही हैं। उनका कहना है कि जो करो, पूरा करो। बीच में मत छोड़ो। कोशिश करते रहो। सीखते रहो। आरुषि बताती हैं, कंपनी की टीम भी परिवार जैसी ही है। इसके कोर सदस्यों का विश्वास और साथ हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। यहां जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी टीम भागीदार होती है। इससे सभी एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। हर सदस्य को अपनी बात रखने की आजादी है, क्योंकि संस्थापकों की तरह उनके लिए भी कंपनी किसी शिशु के समान ही है। सभी एक-दूसरे के विकास में पूरा सहयोग देते हैं।

साफ्ट स्किल

'न्यू नार्मल' दौर में उभरती जॉब स्किल्स की तस्वीर

कोविड के बदलते दौर में काम करने के तरीके में भी काफी बदलाव आया है। आफिस में काम करने की संस्कृति जहां बदली है, वहीं कई नई स्किल्स के आधार पर कैंडिडेट्स का सेलेक्शन हो रहा है। कोरोना काल में वर्क फ्राम होम का कल्चर 'न्यू नार्मल' के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकतर आइटी कंपनियों ने रिमोट वर्क का सिस्टम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में कोई भी कंपनी जॉब देने से पहले कैंडिडेट्स की सिर्फ टेक्निकल स्किल ही नहीं देखती है, बल्कि वह साफ्ट स्किल्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। वर्क फ्राम होम में आप फिजिकल रूप में आफिस नहीं आते हैं, आफिस कल्चर से दूर रहते हैं। ऐसे में आपके काम का आकलन केवल आपकी साफ्ट स्किल्स के आधार पर ही होता है। आप फोन पर अपनी टीम के साथ कैसे कोआर्डिनेट करते हैं, कैसे समय पर अपना काम पूरा करते हैं, काम के प्रति आपकी निष्ठा कितनी है। ये सारी चीजें साफ्ट स्किल्स के तहत आती हैं।

कुछ साल पहले तक अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है और आप क्वालिफाइड हैं तो नौकरी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर पिछले दो साल के ट्रेंड को देखें तो सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से ही करियर में ऊंचाइयां नहीं मिलतीं, बल्कि एक सफल करियर पाने के लिए एक कैंडिडेट में साफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए। ये स्किल्स आपको किसी कालेज या इंस्टीट्यूट में सिखाई नहीं जाती हैं, बल्कि प्रैक्टिकली सीखनी पड़ती हैं।

क्या है साफ्ट स्किल: बात करने की कला, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, या प्रोफेशनल लाइफ के तनाव को पर्सनल लाइफ से कैसे अलग रखें, इंटरव्यू के दौरान ग्रूमिंग, बाडी लैंग्वेज, क्रिएटिविटी आदि ये सभी साफ्ट स्किल्स के अंदर आते हैं। साफ्ट स्किल्स आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देती हैं। आप किसी भी परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे समाधान निकालते हैं और कैसे विपरीत हालात में धैर्य बनाए रखते हैं, ये सब साफ्ट स्किल्स हैं। यही वे स्किल्स हैं जो आपको भीड़ से अलग करती हैं। आइआइटी मद्रास ने हाल ही में साफ्ट स्किल्स प्रोग्राम के लिए एक वेब पोर्टल लांच किया है, जहां कई तरह की ट्रेनिंग और डिप्लोमा कोर्स कराए जा रहे हैं।

कोविड के दौरान जिन लोगों ने नई नौकरियां ज्वाइन की हैं उनमें से एक हैं वैभव सैनी। वैभव अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में कई इंटरव्यू दिए लेकिन हर जगह उन्होंने एक बात नोटिस की। कंपनियां उनकी डिग्री से ज्यादा उनके बिहेवियरल पैटर्न को ज्यादा परख रही थीं। उनसे प्रैक्टिकल सवाल-जवाब कर रही थीं, जैसे-वह अपनी टीम को फोन पर कैसे मैनेज करेंगे, कैसे टाइम पर अपना काम पूरा करेंगे, कभी कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो क्या वह उसे टीम के दूसरे लोगों पर डाल देंगे या खुद आगे बढ़कर उसका समाधान निकालेंगे। वैसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कप्लेस पर ही इन स्किल्स की जरूरत होती है बल्कि एक खुशहाल जिंदगी और अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए भी इन स्किल्स की आजकल बहुत आवश्यकता है।

सुमन अग्रवाल

बदल गई हैं अपेक्षाएं

आजकल कंपनियां कैंडिडेट्स को जॉब देने से पहले उनकी टेक्निकल नालेज से ज्यादा साफ्ट स्किल्स का आकलन करती हैं। हमारी किताबी पढ़ाई और डिग्री, जॉब फील्ड की प्रैक्टिकल स्किल्स से बिल्कुल अलग है और इन दोनों में बहुत बड़ा गैप है। वहीं दूसरी ओर, इन दिनों एंप्लाइज से कंपनियों की अपेक्षाओं की तस्वीर भी बदलती दिखाई दे रही हैं। वे अपने कैंडिडेट्स के भीतर टेक्निकल नालेज कितनी है, इसे बाद में देखती हैं, बल्कि पहले उनकी साफ्ट स्किल्स का टेस्ट करती हैं।

भोलेश्वर प्रसाद दुबे, साफ्ट स्किल ट्रेनर

कंपनियां देखती हैं काम के प्रति निष्ठा और जुनून

कोरोना काल में जितने भी एंप्लाइज का चुनाव हुआ है वह उनकी साफ्ट स्किल्स के आधार पर ही हुआ है। आजकल कंपनियां कैंडिडेट्स में यह देख रही हैं कि वे काम के प्रति कितने निष्ठावान है, उसके अंदर काम को लेकर धैर्य है या नहीं, क्या वे घर से काम करने में सुस्त पड़ जाते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही कैंडिडेट्स का सेलेक्शन किया जा रहा है।

अंकुर मिश्रा, फाउंडर, फॉरेनटेक (आइटी कंपनी), गुरुग्राम

एजुकेशन और जॉब्स की खबरें विस्तार से पढ़ें www.jagran.com पर

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 14 अगस्त, 2021 शनिवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष षष्ठी का राशिफल।
आज का राहुकाल: प्रातः 09:00 बजे से 10:30 बजे तक।
आज का दिशाशूल: पूर्व।
पर्व एवं त्योहार: शीतला षष्ठी।

कल 15 अगस्त का पंचांग

कल का दिशाशूल: पश्चिम।
विशेष: भारतीय स्वतंत्रता दिवस।
कल की भद्रा: प्रातः 09:52 बजे से रात्रि के 08:49 बजे तक।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी 09 घंटे 52 मिनट तक, तत्पश्चात् अष्टमी स्वाती नक्षत्र तत्पश्चात् विशाखा नक्षत्र शुक्ल योग तत्पश्चात् ब्रह्म योग तुला में चंद्रमा तत्पश्चात् वृश्चिक में।

मेष: पारिवारिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रगति होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

वृष: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

मिथुन: रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

कर्क: बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी।

सिंह: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। जीवनसाथी का सहयोग और सान्निध्य मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।

कन्या: व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक कार्यों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संबंध मधुर होंगे।

तुला: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी।

वृश्चिक: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

धनु: रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। महिला अधिकारी से सहयोग लेने में सफल होंगे।

मकर: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

कुंभ: दांपत्य जीवन सुखमय होगा। संबंधित अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

मीन: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवनसाथी के कारण तनाव मिल सकता है। संयम से काम लेना हितकर होगा।

वर्ग पहेली-1667

बाएं से दाएं
5 [illegible] [2,3]।
6 [illegible] [2,2]।
7 [illegible] [3]।
9 [illegible] [3]।
11 [illegible] [4]।
13 [illegible] [3]।
14 [illegible] [3]।
16 [illegible] [4]।
17 तेज, तीव्रता [3]।
19 [illegible] [3]।
21 [illegible] [4]।
22 [illegible] [5]।

ऊपर से नीचे
1 [illegible] [4]।
2 [illegible] [3]।
3 चोट खाया हुआ [3]।
4 [illegible] [5]।
8 [illegible] [4]।
10 [illegible] [3]।
12 [illegible] [4]।
13 [illegible] [3]।
15 [illegible] [5]।
18 [illegible] [4]।
19 [illegible] [3]।
20 [illegible] [3]।

जागरण सुडोकू-1667

5			2					9
	7		5		3		6	
				7		2		
	2		1				4	
4	6				7		2	8
			4	2			1	
				4		8		6
	9		3		1		5	
6				9				1

कल का हल

9	7	6	2	1	3	8	4	5
8	3	1	7	5	4	2	9	6
2	5	4	8	6	9	3	1	7
4	8	7	9	2	5	1	6	3
6	2	3	1	4	7	5	8	9
1	9	5	6	3	8	7	2	4
7	4	8	5	9	2	6	3	1
3	1	2	4	7	6	9	5	8
5	6	9	3	8	1	4	7	2

मौसम

दो राज्यों की न्याय व्यवस्था संभालने वाले बांबे हाई कोर्ट की स्थापना

महाराष्ट्र और गोवा की न्याय व्यवस्था संभालने वाले बांबे हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में आज ही हुई थी। केंद्रशासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव के लिए भी यही हाई कोर्ट है। महाराष्ट्र के नागपुर व औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में इसकी खंडपीठ हैं।

मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला देश बना फ्रांस

1893 में आज ही फ्रांस में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके लिए वहां पेरिस पुलिस आर्डिनेंस पास किया गया था। इस कदम के साथ फ्रांस रजिस्ट्रेशन प्लेट की व्यवस्था शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना था।

समाज के विभिन्न पहलुओं को दिखाती हैं कुलदीप नैयर की किताबें

पत्रकार, नेता और राजनयिक सभी भूमिकाओं में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने वाले कुलदीप नैयर का जन्म 1923 में आज ही सियालकोट में (अब पाकिस्तान में) हुआ था। उन्होंने बिटविन द लाइंस, इंडिया : द क्रिटिकल ईयर्स, इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया हाउस और वाल एट वाघा समेत एक दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी थीं। इनमें बंटवारे के दर्द से लेकर समाज के अन्य कई पहलू दिखते हैं। वह आपातकाल के समय सरकार की आलोचना करने के कारण जेल भी गए थे। 23 अगस्त, 2018 को उनका निधन हो गया।

इधर-उधर की

दो लाख में बिका प्रिंसेज डायना की शादी का केक

डायना-चार्ल्स की शादी में बने थे 23 आधिकारिक केक • इंटरनेट मीडिया

लंदन, एजेंसी : प्रिंसेज डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी के केक का एक टुकड़ा 2,565 डालर (करीब दो लाख रुपये) में बिका है। इंग्लैंड में दुर्लभ वस्तुओं की नीलामी करने वाली कंपनी डोमिनिक विंटर ने इसे बेचा है। इसके लिए इंग्लैंड के ही रहने वाले गेरी लेटन ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। डायना और चार्ल्स की शादी 29 जुलाई, 1981 को हुई थी। शादी के लिए 23 आधिकारिक केक बनाए गए थे। केक का टुकड़ा उस समय की एक कर्मचारी मारिया स्मिथ को मिला था। उन्होंने केक को एक प्लास्टिक पैक में संरक्षित कर लिया था। 2008 में स्मिथ के परिवार ने इसे डोमिनिक विंटर को बेच दिया था।

ल्यूपस का कारक हो सकता है आरबीसी

शोध ▸ रेड ब्लड सेल के दोषपूर्ण विकास से बढ़ता है आटो इम्यून रोग

इस अध्ययन से ल्यूपस के इलाज का मिल सकता है नया विकल्प

वाशिंगटन, एएनआइ : ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है, जिसमें खुद का इम्यून सिस्टम अपने ही अंगों पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। इससे कई बार जीवन को खतरा हो सकता है। भारत में यह बीमारी प्रति दस लाख लोगों में औसतन 30 को होने का अनुमान है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस रोग से ज्यादा प्रभावित होती हैं। विज्ञानियों ने इस रोग के कारण पर एक नया शोध किया है। इसमें बताया गया है कि रेड ब्लड सेल (लाल रक्त कोशिका या आरबीसी) के दोषपूर्ण विकास से यह रोग पैदा हो सकता है। मतलब, यदि आरबीसी के विकास की प्रक्रिया को सही कर लिया जाए तो इस रोग का निदान हो सकता है। इसके आधार पर इलाज की नई पद्धति विकसित की जा सकती है।

वेल कार्नेल मेडिसीन के शोधकर्ताओं की इस खोज से ल्यूपस रोगियों का

आरबीसी के विकास की प्रक्रिया को सही करने से मिल सकता है नया निदान। फाइल फोटो

वर्गीकरण और इलाज आसान हो सकता है। सेल जर्नल में प्रकाशित इस शोध के अनुसार, पाया गया है ल्यूपस के कई रोगियों में परिपक्व आरबीसी अपने माइटोकांड्रिया, जो एक छोटा सा मालीक्यूलर रिएक्टर होता है और आक्सीजन को केमिकल एनर्जी में रूपांतरित करने में मदद करता है, में खामी होती है और यह कोशिका से बाहर होता है।

शोध के वरिष्ठ लेखक डाक्टर वर्जीनिया पास्कुअल तथा वेल्स कार्नेल मेडिसीन में पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर रोनेय मेंशेल ने बताया कि हमारे शोध के निष्कर्ष से जाहिर है कि रेड ब्लड सेल्स ल्यूपस के रोगियों के एक वर्ग में जलन या सूजन में अहम भूमिका निभाता है। इस लिहाज से ल्यूपस के मामले में यह एक नई पहेली है। लेकिन इससे इलाज की नई संभावनाओं का द्वार खुल सकता है। ल्यूपस की बीमारी में त्वचा, जोड़, हृदय तथा किडनी को नुकसान पहुंचता है।

इस रोग में सामान्य तौर पर इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने वाले प्रोटीन, जिसे टाइप-1 इंटरफेरान कहते हैं, का उत्पादन असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इसका इलाज काफी लंबा चलता है और उसका दुष्प्रभाव भी होता है। क्योंकि इसके इलाज में इम्यून एक्टिविटी तथा इंटरफेरान जनित इन्फ्लेमेशन को कम करने की जुगत की जाती है। लेकिन ल्यूपस की वजह अभी भी रहस्य बनी हुई है। एक अनुमान के अनुसार, अमेरिका में लगभग दो लाख लोग इस बीमारी के शिकार हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है।

पहले के अध्ययनों में पाया गया है कि ल्यूपस रोगियों के इम्यून सेल में दोषपूर्ण माइटोकांड्रिया होते हैं। लेकिन नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि ऐसा भी होता है कि रेड ब्लड सेल्स में माइटोकांड्रिया होता ही नहीं है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि बड़ी संख्या में ल्यूपस रोगियों के आरबीसी में माइटोकांड्रिया का स्तर भिन्न होता है। शोधकर्ताओं ने इस बात का अध्ययन किया है कि इंसानी रेड ब्लड सेल्स किस प्रकार से परिपक्व माइटोकांड्रिया से अलग हो जाता है। इसके पहले यह अध्ययन चूहों पर किया जा चुका है।

आगे के अध्ययनों में यह भी पता लगाया गया कि ये असामान्य रेड ब्लड सेल्स किस प्रकार से इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। सामान्यतौर पर रेड ब्लड सेल्स उम्र या क्षतिग्रस्त होने पर होने अन्य इम्यून सेल जिसे माइक्रोफैगस कहते हैं, के द्वारा हटा दिए जाते हैं। आरबीसी को बांध कर रखने वाले एंटीबाडीज भी उसे हटाने में मदद करती है।

आरबीसी के माइटोकांड्रिया को एक बार मैक्रोफैगस द्वारा निगल लिए जाने पर उसका डीएनए एक इन्फ्लेमेटरी मार्ग प्रशस्त करता है, जिसे सीजीएएस या एसटीआइएनजी पाथवे कहते हैं, जिससे इंटरफेरान पैदा होता है। इसके कारण परेशानी पैदा होती है।

भुज : द प्राइड आफ इंडिया

प्रमुख कलाकार : अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, शरद केलकर, नोरा फतेही
निर्देशक : अभिषेक दुधैया
अवधि : एक घंटे 53 मिनट
डिजिटल प्लेटफार्म : डिज्नी प्लस हॉटस्टार

जांबाज जज्बे को जज्बाती बनाने में चूके

साल 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध पर बार्डर, 1971 जैसी तमाम फिल्मों में भुज : द प्राइड आफ इंडिया का नाम भी शामिल हो गया है। इस फिल्म की कहानी भारतीय वायुसेना, थलसेना के अदम्य शौर्य और भुज की उन 300 महिलाओं के साहस को दर्शाती है, जिन्होंने रातोंरात पाकिस्तान द्वारा क्षतिग्रस्त की गई हवाई पट्टी को दुरुस्त कर दिया था।

कहानी शुरू होती है ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल के साथ, जिसमें उस घटना का जिक्र है, जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान जुल्म ढाया करता था। साल 1970 में जब वहां के बांग्ला मुसलमान और हिंदू इस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे, तब आपरेशन सर्चलाइट के तहत तीस लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अपनों के साथ हुए इस दुर्दांत बर्ताव से आहत हिंदुस्तान की फौज ने ईस्ट पाकिस्तान पर कब्जा किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इन विजुअल्स के बाद कहानी पाकिस्तानी हुक्मरानों के बीच पहुंचती है, जो हिंदुस्तान पर हमले की साजिश की योजना बना रहे हैं। आपरेशन चंगेज खान के तहत पाकिस्तान साल 1971 में भुज एयरबेस और जामनगर एयरबेस पर हमला करता है। भुज एयरबेस के कमांडिंग अफसर स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक (अजय देवगन) हैं। हमले में हवाई पट्टी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जामनगर एयरबेस में लड़ाकू विमान पायलट विक्रम सिंह बाज (एमी विर्क) साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को नष्ट कर देते हैं। पाकिस्तान का लक्ष्य भुज और कच्छ पर कब्जा करना होता है। पाकिस्तान की ओर से 100 टैंक्स और 1800 सैनिक, कच्छ के विघाकोट पोस्ट की ओर बढ़ते हैं, जहां केवल 120 भारतीय सैनिक हैं। कच्छ में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल नायर (शरद केलकर) पर है। हवाई पट्टी को दुरुस्त करने के लिए विजय कार्णिक सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरबेन (सोनाक्षी सिन्हा) की मदद लेते हैं। उनके साथ 300 महिलाएं मिलकर एक रात में हवाई पट्टी बना लेती हैं। फिल्म में पाकिस्तानी जासूस से लड़ने वाले दृश्य थोड़े फिल्मी लगते हैं। एक गाने में महिलाओं का अपने घर की ईंटों और पत्थरों को तोड़ने वाले दृश्य में जोश की कमी खलती है। अजय देवगन अपने सुर में नजर आए। वह अपने अंदाज से जोश जगाते हैं। लड़ाकू विमान उड़ाने वाले फिल्म के बेहतरीन शाट्स आए हैं। शरद केलकर अपने स्तर पर एक्टिंग का मोर्चा संभालते हैं। रा एजेंट के तौर पर संजय दत्त और नोरा फतेही का काम अच्छा है।

'कमीज के टूटे हुए बटन से लेकर टूटी हुई हिम्मत तक औरत कुछ भी जोड़ सकती है।' जैसे संवाद महिलाओं के साहसी व्यक्तित्व को बयां करते हैं। 'मैं जीता हूं मरने के लिए मेरा नाम है सिपाही...' कविता आंखों को नम कर जाती है।

-प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

मजबूत सुरक्षा मुहैया करा सकती है कोरोना की नई वैक्सीन

अनुसंधान

कोरोना वायरस (कोविड-19) से मुकाबले की दिशा में ज्यादा प्रभावी वैक्सीन और दवाओं की तलाश में निरंतर शोध किए जा रहे हैं। इसी प्रयास में जुटे विज्ञानियों ने प्रोटीन आधारित एक नई वैक्सीन विकसित की है। यह वैक्सीन शरीर में पहुंचने के बाद वायरस का आकार लेती है। इस तरीके से कोरोना के खिलाफ ज्यादा मजबूत सुरक्षा मुहैया हो सकती है। पशुओं पर परीक्षण में इस वैक्सीन से मजबूत एंटीबाडी रिस्पांस पाया गया।

एसीएस सेंट्रल साइंस पत्रिका में छपे अध्ययन के शोधकर्ताओं के अनुसार, चूहों को ऐसे नैनोपार्टिकल के साथ यह वैक्सीन लगाई गई, जो कोरोना का कारण बनने वाले सार्स-कोव-2 वायरस जैसा

बेहतर होगी इम्युनिटी। फाइल

आकार लेकर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन (आरबीडी) एंटीजन की प्रतिकृति तैयार करते हैं। प्रोटीन आधारित ज्यादातर टीके इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) को आरबीडी की पहचान करने में दक्ष करने का काम करते हैं। आरबीडी कोरोना के स्पाइक प्रोटीन का एक हिस्सा है। यह वायरस इसी प्रोटीन के इस्तेमाल से मानव कोशिकाओं में दाखिल होता है और संक्रमण फैलाता है। हालांकि सभी टीकों से एंटीबाडी और टी सेल रिस्पांस मिल नहीं पाता है। ये दोनों दीर्घकालीन इम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पूर्व में पालीमर्सोम नामक एक वैक्सीन डिलिवरी टूल विकसित किया था। यह टूल एंटीजन और एजवेंट्स को इम्यून सेल्स (प्रतिरक्षा कोशिकाओं) में पहुंचा सकता है। एजवेंट्स हेल्पर मोलीक्यूल होते हैं, जो इम्यून रिस्पांस को मजबूत करने का काम करते हैं। शोधकर्ताओं की टीम यह जानकर चकित रह गई कि अगर इस तरीके में कुछ बदलाव किया जाए तो एंटीबाडी रिस्पांस को और बेहतर किया जा सकता है। -प्रेट्र

प्रकृति को बचाने के लिए कृत्रिम द्वीप तैयार

दुनिया एक ओर जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़, आग और भूस्खलन जैसी आपदाओं से जूझ रही है, वहीं कुछ संस्थाएं प्रकृति के संरक्षण के लिए अनूठी पहल कर रही हैं। ऐसी ही एक गैरसरकारी संस्था नेचुरमोन्युमेंटन ने नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े पांच कृत्रिम द्वीप बनाए हैं। यह यूरोप में सबसे बड़ी प्रकृति बहाली परियोजनाओं में से एक है। इनका उद्देश्य जैव विविधताओं का संरक्षण और संवर्द्धन है। 374.5 वर्ग किमी में फैले कृत्रिम द्वीपों की इस अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना पर 68 मिलियन डालर (करीब पांच अरब रुपये) लागत आई है। इन द्वीपों का निर्माण गाद से किया गया है। एएफपी

भूख से हुई थी मैमथ की मौत

करीब 17000 साल पहले आर्कटिक अलास्का में पहाड़ी दर्रे में पाए जाने वाले विशालकाय मैमथ की मौत भोजन नही मिलने की वजह से हुई थी। अमेरिका के अलास्का म्यूजियम यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने मैमथ के दांतों के विश्लेषण के बाद यह जानकारी दी है। विज्ञानी मैथ्यू वूलर का यह शोध प्रतिष्ठित साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। वह मैमथ के धरती से विलुप्त होने के कारणों पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन विशाल जीवों के लिए भोजन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। मैमथ की यह पेंटिंग आर्टिस्ट जेम्स हेवेन्स ने बनाई है। रायटर

स्क्रीन शॉट

अगर बिग बास प्रतिभागी होते करण जौहर, तो तैयार होकर सोते!

रियलिटी शो बिग बास में प्रतिभागी 24 घंटे कैमरे के सामने रहते हैं। उन्हें दर्शकों का दिल जीतने के अलावा अपने लुक्स और बात करने के तरीके का भी ध्यान रखना पड़ता है। डिजिटल प्लेटफार्म वूट पर चल रहे बिग बास ओटीटी शो के होस्ट करण जौहर की अगर बात करें, तो उनका नजरिया इस पर कुछ अलग ही है। करण को अगर कभी मौका मिले बिग बास ओटीटी शो के घर में रहने का तो वह क्या करेंगे। इस बारे में उनका कहना है कि वह अगर प्रतिभागी होते, तो सोते समय भी ओवरड्रेस्ड यानी पूरी तरह से तैयार होकर ही सोते और हमेशा सुर्खियों में बने रहते। आगे करण ने कहा कि वह कभी इस शो में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वह अपने मोबाइल फोन के बिना एक घंटे भी नहीं रह सकते हैं, ऐसे में बिग बास ओटीटी शो में बतौर प्रतिभागी बनकर छह हफ्ते तक रहना उनके लिए कभी संभव ही नहीं है। दरअसल, इस शो के नियमों के तहत प्रतिभागी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। खैर, इस शो की बात करें, तो छह हफ्तों तक चलने वाले इस शो में बिग बास सीजन 13 के प्रतियोगी रह चुके सिडनाज की जोड़ी यानी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की एंट्री होने वाली है। सिद्धार्थ बिग बास सीजन 13 के विजेता रह चुके हैं। इस सप्ताहांत उनकी एंट्री बिग बास ओटीटी शो में होने वाली है। दोनों खास मेहमान के तौर पर शो में आएंगे।

बिग बास ओटीटी शो के होस्ट हैं करण।

मैं स्क्रिप्ट प्रोडक्शन हाउस को वापस कर देती हूं : शेफाली शाह

हर कलाकार का काम करने का अपना तरीका होता है। प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बात उनके लिए खास होती है। कई बार कुछ कलाकार अपने किरदार से जुड़ी कोई चीज अपने पास रख लेते हैं, तो कोई कलाकार अपने स्टाइल में काम करता है। बात करें अगर दिल धड़कने दो फिल्म की अभिनेत्री शेफाली शाह की तो वह अपने स्क्रिप्ट पर जब काम शुरू करती हैं, तो कुछ चीजें हैं, जिसे वह फालो करती हैं। शेफाली जब डार्लिंग्स फिल्म की शूटिंग शुरू कर रही थीं, तो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट की तस्वीर साझा की थी। उस पर स्वास्तिक बना हुआ था। इस बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में शेफाली ने बताया कि दरअसल, वह स्क्रिप्ट मैंने पूजा में से उठाई थी। शूटिंग से पहले जो पूजा की जाती है, उसमें वह स्क्रिप्ट रखी गई थी। वैसे मेरी आदत रही है कि मैं अपनी हर स्क्रिप्ट के पहले पेज पर ॐ गण गणपतये नमः? लिखती हूं। कई कलाकार स्क्रिप्ट अपने पास संभालकर रखते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं अक्सर अपने स्क्रिप्ट्स निर्देशक या प्रोडक्शन हाउस को वापस कर देती हूं। मुझे लगता है कि जब तक फिल्म रिलीज न हो जाए, तब तक किसी गलत हाथ में स्क्रिप्ट नहीं लगनी चाहिए। दिल्ली क्राइम वेब सीरीज पर मैंने बहुत काम किया था। उसकी स्क्रिप्ट शो की शूटिंग के बाद मैंने रिची (क्राइम शो के निर्देशक) को दी थी और उस पर एक नोट लिखा था कि आपने मुझे वर्तिका (शो में शेफाली के किरदार का नाम) दी है, उसे मैं आपको लौटा रही हूं।

आगामी शो दिल्ली क्राइम 2 में नजर आएंगी शेफाली

किरण खेर से फैंस बोले, ज्वेलरी और साड़ियां बहू को दे देना

अनुपम खेर और किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर अक्सर अपने फैंस के साथ लाइव जुड़ते हैं। कई बार वह अपने पिता अनुपम खेर को लाइव पर कनेक्ट कर लेते हैं। इस बार सिकंदर अपनी मां और अभिनेत्री किरण खेर के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव आए। दरअसल, सिकंदर एक गाना अपने फैंस को सुना रहे थे, तब किरण उनके कमरे में आकर बोलीं कि वह अच्छा गा रहे हैं। फिर सिकंदर लाइव में उनके साथ ही बैठ गए। इस दौरान सिकंदर ने बताया कि उनकी मां को हमेशा से बेटी की चाह रही है, इस पर किरण ने कहा कि हां पता नहीं मैं किसे अपनी साड़ियां और ज्वेलरी दूंगी। इस पर सिकंदर तुरंत बोले मैं पहन लूंगा मां, मैं टैलेंटेड इंसान हूं, आप मुझे सिखाइए कैसे साड़ी पहनते हैं। हालांकि फैंस ने अपनी राय देते हुए लिखा कि आप वह चीजें सिकंदर की होने वाली पत्नी और अपनी बहू को दे सकती हैं। इस पर किरण ने कहा कि आप लोगों के मुंह में घी शक्कर। इस दौरान सिकंदर ने बताया की जब भी मैं बारिश में शूटिंग करता हूं, तब मम्मी को बहुत डर लगता है। वह हाल ही में मुझसे पूछ रही थीं कि तुम रात में शूटिंग करने वाले हो, अगर बारिश आ गई तो। मैंने कहा फिर क्या शूटिंग रोकनी पड़ेगी। हाल ही में बारिश की वजह से मुझे शूटिंग रोकनी पड़ी थी, और मैं घर पर बहुत लेट आया था। वैसे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मां जो कहती हैं, वह सच हो जाता है। अगर ऐसा होता तो मैं स्टार बन गया होता। इस पर किरण ने कहा कि तुम स्टार बन जाओगे।

बेटे की शादी की बात पर किरण हुईं खुश।

अब सरप्राइज या गिफ्ट के इंतजार की उम्र नहीं रही : गौतम रोड़े

फिलहाल डिजिटल प्लेटफार्म पर फोकस कर रहे हैं गौतम।

बर्थडे हर शख्स के लिए कुछ खास होता है और इस मौके पर मिलने वाले तोहफों और सरप्राइज से तो अक्सर लोगों की कुछ खास यादें जुड़ी होती हैं। सरस्वतीचंद्र और सूर्यपुत्र कर्ण जैसे धारावाहिकों के अभिनेता गौतम रोड़े आज 44 साल के हो गए। अपने बर्थडे के बारे में उन्होंने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा, 'जन्मदिवस की पूर्व शाम 13 अगस्त को मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों और स्वजनों के साथ घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी और दोस्तों से खूब बातें कीं। उसके बाद 14 अगस्त से 16 अगस्त तक मैं अपनी पत्नी पंखुड़ी अवस्थी के साथ मुंबई के एक पांच सितारा होटल में रहूंगा, जो कि हमारी पसंदीदा जगह है। कोरोना संक्रमण के डर की वजह से फिलहाल ज्यादा सफर तो किया नहीं जा सकता है, इसलिए हमने मुंबई में ही रहने का फैसला किया है।' बर्थडे के यादगार गिफ्ट पर गौतम कहते हैं, 'अब मेरी वह उम्र नहीं रही कि किसी से गिफ्ट या सरप्राइज मिलने का इंतजार करूं। अब तो बस यही इच्छा होती है कि अपने करीबी लोगों से मिलूं और उनके साथ खूब गप्पे मारूं। अब मैं गिफ्ट देने वाले वर्ग में आ गया और घरवालों की मुझसे उम्मीदें होती हैं। मैं उनको गिफ्ट देता हूं।' इस बातचीत में गौतम ने यह भी बताया फिलहाल वह टीवी से दूर रहकर डिजिटल प्लेटफार्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालिया रिलीज फिल्म स्टेट आफ सीज : टेंपल अटैक में वह सैन्य अधिकारी के किरदार में नजर आए हैं।

(सभी फोटो इंस्टाग्राम से)

अवसाद का भी कारक है मोटापा

- यूनिवर्सिटी आफ एक्सेटर का शोध
- ह्यूमैन मालीक्यूलर जीनेटिक्स में प्रकाशित हुआ अध्ययन

एक्सेटर (यूके), एएनआइ : मोटापा को लेकर स्वास्थ्य संबंधी कई अध्ययन हुए हैं। इसके दुष्परिणामों के बारे में भी कई बातें बताई जा चुकी हैं। अब इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी होने की बात सामने आई है। बड़े पैमाने पर किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि मोटापा अवसाद भी पैदा करता है। यह निष्कर्ष ह्यूमैन मालीक्यूलर जीनेटिक्स में प्रकाशित हुआ है।

मोटापा दुनियाभर में एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। ब्रिटेन में हर चौथा व्यक्ति मोटापे का शिकार है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अध्ययन का फोकस इस बात पर रहा कि ज्यादा बाडी मास इंडेक्स (बीएमआइ) किस प्रकार से अवसाद पैदा करता है। शोध टीम ने इसके लिए जीनेटिक एनालिसिस का सहारा लिया। यह पता लगाने की कोशिश की कि इसका मानसिक या मेटाबोलिक क्रियाओं से किस प्रकार का संबंध है। मोटापे के कारण हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज तथा हृदय रोग का भी खतरा बढ़ता है।

एकेडमी आफ मेडिकल साइंसेज के सहयोग से यूनिवर्सिटी आफ एक्सेटर के शोधकर्ताओं द्वारा किए अध्ययन में शोध टीम ने यूके बायोबैंक के रिकार्ड में दर्ज 145,000 प्रतिभागियों के जीनेटिक डाटा का परीक्षण किया, जिनमें उनके मानसिक स्वास्थ्य का डाटा उपलब्ध था।

शोधकर्ताओं ने बाडी मास इंडेक्स से

मोटापा एक मानसिक समस्या भी। फाइल

जुड़े जीनेटिक वैरिएंट का भी विश्लेषण किया। इसके साथ ही क्लीनिकल डाटा के आधार पर ऐसी प्रश्नावली तैयार की, जिससे कि अवसाद, बेचैनी तथा सेहत संबंधी अन्य बातों के स्तर का पता लगाया जा सके।

अधिक बीएमआइ वाले लोगों में किस कारण से अवसाद पैदा होता या इसके कारक किस तरह से सक्रिय होते हैं, इसका पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने पूर्व के अध्ययनों से खोजे गए जीनेटिक वैरिएंट्स के दो सेटों की जांच-पड़ताल की।

जीन का एक सेट ऐसा था, जो व्यक्ति को मोटा तो बनाता है, लेकिन इसके साथ ही मेटाबोलिक रूप से स्वस्थ भी रखता है। मतलब, अधिक बीएमआइ से जुड़ी स्थितियां ज्यादा प्रभावी नहीं होती हैं। जबकि दूसरे सेट के जीन मोटापा बढ़ाने के साथ ही मेटाबोलिक तौर पर भी स्वास्थ्य को खराब करता है और अवसाद की स्थिति पैदा करता है।

शोध टीम ने पाया कि जीनेटिक वैरिएंट्स के दोनों सेट्स में बहुत कम अंतर है, जो इस बात के संकेत हैं कि शारीरिक और सामाजिक कारक भी अवसाद में अहम भूमिका निभाते हैं।

शोध के मुख्य लेखक जेस ओ'लफलिन के मुताबिक, मोटापा और अवसाद दोनों ही वैश्विक स्वास्थ्य की बड़ी चुनौतियों में से एक है और हमारे अध्ययन से इसका पुख्ता सुबूत मिलता है कि अधिक बीएमआइ अवसाद पैदा करता है। इस संबंध में यह समझना बेहतर होगा कि क्या फिजिकल या सोशल फैक्टरों के बीच ऐसा कोई संबंध है, जिसका कि मानसिक सेहत को सुधारने में रणनीतिक स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके।

उन्होंने बताया कि हमारे शोध से यह भी पता चलता है कि मोटापा से अवसाद का खतरा बढ़ता है और इस जोखिम में मेटाबोलिक स्थिति से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह भी है कि शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक परिस्थितियां दोनों ही मिलकर मोटापा तथा अवसाद के बीच के संबंधों में अहम भूमिका निभाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसके आधार पर अवसाद को कम करने के लिए मोटापा घटाने की सलाह देना या उसके लिए उपाय करने से फायदा हो सकता है। इसलिए अवसाद के इलाज में इस तथ्य पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।